A Multidisciplinary

National Seminar

on

Viksit Bharat 2047: Leveraging Technology for Economic Growth and Sustainable Development

29 & 30th, JANUARY 2026

souvenir

Organised By

MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR

&

CHHATTISGARH COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(CGCOST)

Mahant Laxminarayan Das College,
Raipur, Chhattisgah

SOUVENIR

A

Multidisciplinary

National Seminar

on

Viksit Bharat 2047: Leveraging Technology for Economic Growth and Sustainable Development

29 & 30th, JANUARY 2026

Organised By

MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR

Accreditation by NAAC with B grade.

&

CHHATTISGARH COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY (CGCOST)

SOUVENIR

ओ.पी. चौधरी
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त, वाणिज्यिक कर,
आवास एवं पर्यावरण,
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

कार्यालय निवास : बी–5/9, शंकर नगर,
रायपुर (छ.ग.), 0771–4221112
कार्यालय : एम–2/13, 14, मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, (छ.ग.)
दूरभाष : 0771–2221106
E-mail : opchoudharyofficial@gmail.com

अर्द्ध.शा.प.क्र. 1238 /वि./व.क.(पं)/आ.पर्या./यो.आ.सां./2026 रायपुर, दिनांक 01/01/2026

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकार अत्यंत हर्ष हो रहा है कि महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय रायपुर द्वारा Viksit Bharat : 2047 Leveraging Technology for Economic Growth and Sustainable Development जैसे समसामयिक, दूरदर्शी एवं राष्ट्रनिर्माण से जुड़े विषय पर सेमीनार का आयोजन किया जा रहा है। आज के वैश्विक परिदृश्य में तकनीक न केवल आर्थिक प्रगति का सशक्त माध्यम है, बल्कि सतत् विकास, समावेशी वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक सशक्तिकरण का भी आधार स्तंभ बन चुकी है। विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने हेतु डिजिटल नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप संस्कृति एवं अनुसंधान आधारित नीतियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सेमीनार निश्चित ही इन आयामों पर सार्थक विमर्श, नवोन्मेषी विचारों और व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करने में सफल सिद्ध होगा।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस अकादमिक आयोजन से प्राप्त निष्कर्ष एवं सुझाव नीति–निर्माण, शैक्षणिक अनुसंधान तथा सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे और युवा पीढ़ी को तकनीक के जिम्मेदार एवं रचनात्मक उपयोग के लिए प्रेरित करेंगे।

मैं कामना करता हूँ कि यह सेमीनार अपने उद्देश्यों की पूर्णता के साथ ज्ञान–सृजन, बौद्धिक संवाद और राष्ट्रहित में नवचिंतन का सशक्त मंच बने। भविष्य में भी ऐसे सार्थक एवं प्रेरणादायी अकादमिक आयोजनों की निरंतरता बनी रहे। सेमीनार के सफल आयोजन के लिए मैं आयोजक समिति, प्रतिभागी विद्वानों, वक्ताओं एवं सभी सहयोगियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

01/01/26
(ओ.पी.चौधरी)

SOUVENIR

विजय शर्मा
उप मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ शासन
गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

क्रमांक .....

रायपुर, दिनांक .....

Dear Organizers and Participants,

Warmest greetings and best wishes for the national seminar on Viksit Bharat and Technology. This seminar is a significant step towards exploring the vast potential of technology in shaping India's future. As the nation strives for growth and development, discussions on leveraging technology for a Viksit Bharat are crucial.

May this event foster meaningful conversations, spark innovative ideas, and pave the way for collaborations that drive progress. With esteemed speakers and passionate participants, I'm confident the seminar will be a catalyst for positive changes.

Wishing you engaging sessions, fruitful interactions, and a successful event!

Best regards

Vijay Sharma

कार्यालय : कक्ष क्रमांक एम 4–1, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) दूरभाष नं. 0771–2510904, 2221104
निवास : सी–3 सिविल लाईन, रायपुर (छ.ग.) दूरभाष नं. 0771–2445561, 91092–55611, ई–मेल : cghm.72@gmail.com

SOUVENIR

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़) - 492010 भारत

NAAC Grade A+

Pt. Ravishankar Shukla University
Raipur (Chhattisgarh) - 492010 - INDIA
Office : +91 771-2262857, +91 771-2263439
E-mail : vc_raipur@prsu.ac.in
Website : www.prsu.ac.in

रायपुर, दिनांक 09 जनवरी, 2026

शुभकामना

हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर द्वारा **"Viksit Bharat 2047: Leveraging Technology for Economic Growth and Sustainable Development"** विषय पर दो दिवसीय 'राष्ट्रीय संगोष्ठी' का आयोजन दिनांक 29 एवं 30 जनवरी, 2026 को किया जा रहा है साथ ही इस अवसर पर स्मारिका का प्रकाशन भी किया जा रहा है।

प्रौद्योगिकी आज केवल विकास का साधन नहीं बल्कि समावेशी, संतुलित और सतत राष्ट्र–निर्माण की आधारशिला बन चुकी है। डिजिटल नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा, स्मार्ट अधोसंरचना और स्टार्टअप संस्कृति जैसे क्षेत्र "विकसित भारत–2047" के संकल्प को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रौद्योगिकी–आधारित आर्थिक विकास एवं सतत विकास के नए आयामों को रेखांकित करेगी तथा नीति–निर्माताओं, शिक्षाविदों और युवाओं को सकारात्मक दिशा प्रदान करेगी। विकसित भारत–2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह संगोष्ठी मील का पत्थर सिद्ध हो, यह मंगलकामना है।

संगोष्ठी के सफल आयोजन एवं स्मारिका के प्रकाशन की सफलता की कामना करता हूँ।

09/01/26

(प्रो.सच्चिदानन्द शुक्ल)
कुलपति
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर

SOUVENIR

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त)
विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

प्रो. वी. के. सारस्वत
कुलपति

PANDIT SUNDARLAL SHARMA (OPEN)
UNIVERSITY CHHATTISGARH

Accredited by NAAC with Grade 'A+'
University with Graded Autonomy (Category-II) by U.G.C.

Prof. V. K. Saraswat
Vice-Chancellor

S.No. 174 /K.S./ 2025

Bilaspur, Date :26/ 12/2025

// Message//

Warm greetings on the occasion of the National Seminar on **"Viksit Bharat 2047: Leveraging Technology for Economic Growth and Sustainable Development"** organized by **Mahant Laxminarayan Das Mahavidyalaya, Raipur.** This seminar reflects a forward-looking vision aligned with India's aspiration to emerge as a developed, self-reliant, and inclusive nation by the centenary of its independence.

The theme highlights the pivotal role of technology in accelerating economic growth while ensuring environmental sustainability and social equity. Such academic platforms encourage meaningful dialogue, innovation, and research, and inspire students, scholars, and educators to contribute thoughtfully to nation-building. Mahant Laxminarayan Das Mahavidyalaya's initiative in organizing this national seminar demonstrates its commitment to academic excellence, intellectual inquiry, and societal progress.

May this seminar foster insightful discussions, collaborative learning, and innovative ideas that contribute to the realization of Viksit Bharat 2047. Best wishes for the grand success of the seminar.

26.12.2025

(Prof. V. K. Saraswat)
Vice – Chancellor

SOUVENIR

पंजीयन क्र.–12 दिनांक 25.11.1932

दूरभाष क्रमांक : 0771–4042701

शिक्षा प्रचारक समिति, रायपुर

के द्वारा संचालित संस्थान

श्री वामनराव लाखे उच्च माध्य. शाला क्रमांक 1 एवं महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक, रायपुर
श्री वामन राव लाखे उ.मा. शाला क्र. 2 एवं एस.पी.एस. इंग्लिश मिडियम स्कूल, हीरापुर (तेंदुआ रोड), रायपुर
गाँधी चौक, रायपुर 492001

अजय तिवारी	आर. के. गुप्ता	अनिल तिवारी
अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सचिव
मो. : 9425506733	मो. : 9425205248	मो. : 9425516360

पत्र क्रमांक ....76.....

दिनांक 14-01-2026

Message

It gives me immense pleasure that Mahant Laxminarayan Das college in association with Chhattisgarh Council Of Science And Technology (CGCOST) is organizing a Multidisciplinary National Seminar on "Viksit Bharat 2047: Leveraging Technology for Economic Growth and Sustainable Development" scheduled to be held on 29th–30th January, 2026.

The theme of the seminar is highly relevant in the present national and global context. Academic discussions on technology, sustainability, and economic development are essential for building an informed and progressive society that contributes for Viksit Bharat. This seminar will serve as a valuable platform for intellectual exchange and interdisciplinary learning.

I am honored to lead a community dedicated to fostering innovation, inclusivity, and strong character development. Our college provides a nurturing environment that sparks intellectual curiosity, creativity, and critical thinking.

I congratulate the organizing committee and the Internal Quality Assurance Cell for their sincere efforts in organizing this national-level academic event. I wish the seminar achieves its academic objectives and grand success.

With best wishes,

Ajay Tiwari

SOUVENIR

पंजीयन क्र.–12 दिनांक 25.11.1932

दूरभाष क्रमांक : 0771–4042701

शिक्षा प्रचारक समिति, रायपुर

के द्वारा संचालित संस्थान

श्री वामनराव लाखे उच्च माध्य. शाला क्रमांक 1 एवं महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक, रायपुर
श्री वामन राव लाखे उ.मा. शाला क्र. 2 एवं एस.पी.एस. इंग्लिश मिडियम स्कूल, हीरापुर (तेंदुआ रोड), रायपुर
गाँधी चौक, रायपुर 492001

अजय तिवारी	आर. के. गुप्ता	अनिल तिवारी
अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सचिव
मो. : 9425506733	मो. : 9425205248	मो. : 9425516360

पत्र क्रमांक ....76.....

दिनांक 14-01-2026

Message

It elates pleasure that Mahant Laxminarayan Das College is organizing a Multidisciplinary National Seminar on 29th–30th January, 2026. I sincerely appreciate and congratulate the organizing committee and staff whose dedicated efforts made this national seminar possible.

Our college has a strong tradition of organizing academic events such as national seminars, workshops, and conferences on a regular basis to promote research, innovation, and academic excellence. It is commendable that our innovative practices have led to such recognition for the college. As the secretary of Shiksha Pracharak Samiti, I feel proud of these achievements. This dedication to innovative practices is likely a key factor in the college's esteemed position among educational institutions.

This seminar is another important step in that direction and reflects our commitment to fostering a vibrant academic culture. I wish you all a very successful seminar

With best wishes

अनिल तिवारी

Anil Tiwari

Mahant Laxminarayan Das College,
Raipur, Chhattisgah

SOUVENIR

R. No. 367/ACA./AFFL./2003

MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR

Accredited by NAAC with Grade-B
Run by: Shiksha Pracharak Samiti, Raipur
(Affiliated to Pandit Ravishankar Shukla University, Raipur)
www.mldcollege.com

Near Municipals Corporation Building, Gandhi Chowk, Raipur (C.G.) Ph. No. :- 0771-4024234

No.: ..... Date :

प्राचार्य की कलम से

महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय में 29 एवं 30 जनवरी 2026 को "VIKSIT BHARAT 2047: LEVERAGING TECHNOLOGY FOR ECONOMIC GROWTH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT" विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के अवसर पर सभी विद्वत वक्ताओं, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों एवं प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

विकसित भारत-2047 की संकल्पना में प्रौद्योगिकी को आर्थिक प्रगति, सामाजिक समावेशन तथा पर्यावरणीय संतुलन का सशक्त माध्यम माना गया है। इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, जनजातीय संस्कृति तथा उभरती औद्योगिक संभावनाएँ प्रौद्योगिकी-आधारित सतत विकास के लिए अपार अवसर प्रदान करती हैं। डिजिटल नवाचार, ई-गवर्नेंस, स्मार्ट कृषि, कौशल विकास तथा हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से छत्तीसगढ़ विकसित भारत के निर्माण में एक सशक्त सहभागी बन सकता है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह संगोष्ठी प्रौद्योगिकी और सतत विकास के समन्वय पर सार्थक विमर्श को प्रोत्साहित करेगी तथा नीति, शोध और व्यवहार के स्तर पर नए दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगी। मैं आयोजन समिति के प्रयासों की सराहना करता हूँ, जिन्होंने इस अकादमिक आयोजन को सफलतापूर्वक साकार किया है।

मेरी कामना है कि यह संगोष्ठी ज्ञानवर्धन के साथ-साथ एक समृद्ध, आत्मनिर्भर एवं सतत भारत के निर्माण की दिशा में प्रेरक सिद्ध हो।

शुभकामनाओं सहित....

डॉ. देवाशीष मुखर्जी
प्राचार्य

SOUVENIR

R. No. 367/ACA./AFFL./2003

MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR

Accredited by NAAC with Grade-B
Run by: Shiksha Pracharak Samiti, Raipur
(Affiliated to Pandit Ravishankar Shukla University, Raipur)
www.mldcollege.com
Near Municipals Corporation Building, Gandhi Chowk, Raipur (C.G.) Ph. No. :- 0771-4024234

No.: ..... Date :

PROF. SHANTANU PAUL
CONVENOR

It is indeed a moment of pride that Mahant Laxminarayan Das college in association with Chhattisgarh Council Of Science And Technology (CGCOST) is organizing a Multidisciplinary National Seminar on "Viksit Bharat 2047: Leveraging Technology for Economic Growth and Sustainable Development" scheduled to be held on 29th–30th January, 2026.

This seminar brings together brilliant minds from across the nation to deliberate on topics of paramount national importance, offering a vital platform for sharing insights, fostering collaboration, and charting new directions in Viksit Bharat 2047. Our thoughtfully chosen themes and subthemes are designed to spark in-depth discussions and contribute significantly to our collective understanding and solutions.

Scientists, academicians, research scholars, and industry professionals will share the latest advances through lectures, oral, ppt presentations and will collaborate for the development of the nation. This will be a big leap towards making "Vikasit Bharat" by 2047.

I sincerely thank The Chief Guest, Keynote Speakers, Resource Persons, Participants, and the organizing committee for their valuable support and cooperation. I also appreciate the efforts of the faculty members, students, and staff whose dedication has made this academic event possible.

I wish the seminar every success and hope it proves to be an intellectually rewarding experience for all. I am confident that the discussions and interactions over these two days will be highly productive and intellectually enriching for everyone involved.

With best wishes

SOUVENIR

R. No. 367/ACA./AFFL./2003

MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR

Accredited by NAAC with Grade-B
Run by: Shiksha Pracharak Samiti, Raipur
(Affiliated to Pandit Ravishankar Shukla University, Raipur)
www.mldcollege.com

Near Municipals Corporation Building, Gandhi Chowk, Raipur (C.G.) Ph. No. :- 0771-4024234

No.: ..... Date :

MESSAGE FROM THE SOUVENIR EDITOR & ORGANIZING SECRETARY

DR. PREM KUMAR CHANDRAKAR
HEAD & ASSISTANT PROFESSOR
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

It gives me immense pleasure to share this moment of glory where we succeed to organize a two days National Seminar on the topic entitled "Viksit Bharat: Leveraging Technology for Economic Growth and Sustainable development". As India strides toward the vision of Viksit Bharat, technology emerges not merely as an instrument of progress but as a transformative force reshaping the nation's economic, social, and ecological landscapes. Digital tools, innovation, and smart systems are changing the way people work, learn, govern, and connect with one another. This seminar endeavors to bring together interdisciplinary perspectives that entail technology-driven initiatives attributing to Nation's growth. The seminar aims to encourage meaningful discussion on India's development journey. Viksit Bharat represents a shared goal—one where technology plays a pivotal role in attaining sustainable development of the country.

The souvenir has been carefully compiled to document the academic contributions, ideas, and perspectives shared during this seminar. I sincerely hope that this publication will serve as a valuable academic resource and inspire further research and collaboration.

I express my profound gratitude to the Patron, Convener, National Advisory Committee members, distinguished speakers, sponsors, and all contributors for their guidance and cooperation. I also appreciate the dedicated efforts of the organizing committee, whose commitment has made this academic endeavor possible.

I am confident that the deliberations of this seminar will significantly contribute to the national discourse on development and sustainability. I extend my best wishes for the grand success of the seminar and a fulfilling academic experience to all participants.

With profound regards

SOUVENIR

EDITORIAL BOARD

PATRON

DR. DEWASHISH MUKHERJEE, PRINCIPAL

CONVENOR

PROF. SHANTANU PAUL,
HEAD, DEPARTMENT OF COMMERCE

SECRETARY

DR. PREM KUMAR CHANDRAKAR,
HEAD, DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

JOINT SECRETARY

DR. SHRUTI TIWARI

SOUVENIR COMPILED BY

PRITAM KUMAR DASS
SUMAN SHARMA
SIMARAN CHANDRAKAR

Mahant Laxminarayan Das College,
Raipur, Chhattisgah

SOUVENIR

PAPER ID	TOPIC	AUTHOR	PAGE NO.
MLDC26001	TO STUDY “VIKSIT BHARAT @ 2047: LEVERAGING TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP IN CHHATTISGARH”	DR. NIDHI SHRI SHUKLA , DR. ASHOK KUMAR SHARMA, MONARK SINGH THAKUR	1
MLDC26002	VIKSIT BHARAT 2047 :LEVERAGING TECHNOLOGY FOR ECONOMIC GROWTH IN RELATION TO FINTECH AND FINANCIAL INCLUSION	DR. ARADHANA SHUKLA DR. ASHOK KUMAR SHARMA MS. NEETU MINJ	2
MLDC26003	INTEGRATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION	RAVINDRA SINGH	3
MLDC26004	THE ROLE OF AI AND BIG DATA FOR VIKSIT BHARAT 2047	DR. PREM KUMAR CHANDRAKAR	4
MLDC26005	LEVERAGING ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT IN INDIA: ALIGNING WITH VIKSIT BHARAT 2047	VIVEK PRAKASH SAHU	5
MLDC26006	NATIONAL EDUCATION POLICY 2020 AS THE FOUNDATION FOR A GLOBAL KNOWLEDGE SUPERPOWER BY 2047	DR. JAYA CHANDRA,	6
MLDC26007	AN ANALYTICAL STUDY OF AUTHORIAL PERSPECTIVE IN SLEEPING INDIA: BARRIERS TO VIKSIT BHARAT	DR SHRUTI TIWARI	7
MLDC26008	TECHNOLOGY-ENABLED AGRICULTURAL CREDIT SYSTEMS AND THEIR ROLE IN ACHIEVING VIKSIT BHARAT 2047	MS. AANCHAL MISHRA DR. RAJENDRA KUMAR SHUKLA	8
MLDC26009	A STUDY ON THE IMPACT OF INDUSTRY 4.0 ON INDIAN MANUFACTURING SYSTEM & INDIA’S VISION OF VIKSIT BHARAT 2047	DR. APURVA SHARMA	9
MLDC26010	PAST LIFE REGRESSION: A THERAPEUTIC APPROACH IN THE VISION OF VIKSIT BHARAT	DR MEGHA SINGH DR. JAYA CHANDRA	10
MLDC26011	IMPACT OF GREEN HRM PRACTICES ON ORGANIZATIONAL SUSTAINABILITY AND EMPLOYEE RETENTION	JEEWAN JYOTI SINGH	11

SOUVENIR

MLDC26012	ROLE OF GOVERNMENT POLICY AND INDUSTRIAL ECOSYSTEMS IN PROMOTING INDUSTRY 4.0 IN CHHATTISGARH'S MANUFACTURING CLUSTERS: A CRITICAL LITERATURE REVIEW	POONAM TANDEKAR DR. SHANTANU PAUL	12
MLDC26013	BRIDGING TRADITION AND TECHNOLOGY: A STUDY ON THE INTEGRATION OF CULTURAL HERITAGE AND DIGITAL INNOVATION IN INDIA	DR. SHILPA WADHWA	13
MLDC26014	SYNERGIZING TECHNOLOGY AND ENTERPRISE: A STUDY ON INNOVATION LED ENTREPRENEURIAL GROWTH IN CHHATTISGARH	MRS. DHANLAXMI DIWAN,	14
MLDC26015	MILLET-BASED DIETARY PRACTICES AND FOOD SECURITY IN RAIPUR DISTRICT: AN ANALYSIS OF CONSUMER AWARENESS	ASHU THAKUR DR. SHANTANU PAUL	15
MLDC26016	ACCELERATING TOWARDS A TECH SAVVY INDIA: ROLE OF KNOWLEDGE ECONOMY IN INDIA'S GROWTH	DR. SHANTANU PAUL MS. ANJALI MAJUMDAR	16
MLDC26017	INDUSTRY 4.0 IN MANUFACTURING: A PARADIGM SHIFT IN INDUSTRIAL PRODUCTION	DR. RISHI PANDEY	17
MLDC26018	A RESEARCH ON GENERAL PROGRESSIVE DIMENSIONS & APPROACHES IN GREEN MARKETING – BENEFITS, OPPORTUNITIES AND CHALLENGES	ADITI SHARMA DR. TAPESH CHANDRA GUPTA	18
MLDC26019	ROLE OF AGRICULTURE IN BUILDING A DEVELOPED INDIA 2047	MRS. SANA KHAN	19
MLDC26020	TRANSITION FROM A MONO-PRODUCT TO REVENUE STREAMS: INTEGRATED PESCATOURISM BUSINESS MODEL CANVAS ANALYSIS	DR. NEETU GUPTA DR. PRACHI SINGH MR. VAIBHAV SHRIVASTAVA	20
MLDC26021	APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN FINTECH A STUDY	OSIN KUNJAM SAMIKSHA PANDEY PROF. (DR.) G.K. DESHMUKH	21
MLDC26022	ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) ASSISTED SHOPPING: A STUDY	SAMIKSHA PANDEY OSIN KUNJAM PROF. (DR.) G.K. DESHMUKH	22

SOUVENIR

MLDC26023	GREEN COMPUTING AND ENERGY EFFICIENT DIGITAL INFRASTRUCTURE FOR SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN VIKSIT BHARAT 2047	SWATI JAIN MUKESH KASHYAP SANJAY KUMAR	23
MLDC26024	STUDY OF THE ROLE AND CHALLENGES OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES OF KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES IN THE DEVELOPMENT OF FOOD SECURITY SCHEMES IN THE STATE OF CHHATTISGARH.	BHUNESHWAR SAHU DR. DEWASHISH MUKHERJEE	24
MLDC26025	CARRYING CAPACITY OF LAND IN DANDAKARANYA REGION	HIMANSHI GOLE DR. TIKE SINGH	25
MLDC26026	A PARADIGM SHIFT: AI INTEGRATION WITHIN THE INDIAN GST FRAMEWORK	NAMRATA SINGH ASHANAND MAKHIJA H.S. BHATIA	26
MLDC26027	CONTRIBUTION OF MAHTARI VANDAN YOJANA TOWARDS VIKSIT BHARAT 2047 THROUGH WOMEN EMPOWERMENT IN CHHATTISGARH	SHUBHAM BHARDWAJ DR. SANJAY KUMAR SINGH	27
MLDC26028	ROLE OF TECHNOLOGY IN PROMOTING TOURISM, CULTURE AND HERITAGE UNDER VIKSIT BHARAT 2047 IN CHHATTISGARH	ASMITA SAHU DR. PRIYANKA BOSE	28
MLDC26029	CULTURAL HERITAGE REVIVAL THROUGH DIGITAL STORYTELLING: A STUDY ON HOW TECHNOLOGY RECONNECTS THE YOUTH WITH TRADITIONAL VALUES	DR. ANUPAMA JAIN	29
MLDC26030	BARRIERS TO ENTREPRENEURIAL INNOVATION IN INDIAN SELF-HELP GROUPS: A SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVE (FOCUS ON CHHATTISGARH)	ANANYA SHARMA DR. S.K. SHRIVASTAVA,	30
MLDC26031	PSYCHOLOGY OF MONEY: UNDERSTANDING THE EMOTIONAL AND COGNITIVE FACTORS INFLUENCING FINANCIAL DECISION-MAKING	DR. JAGANNATH SAHA SHRIYA PANDE	31
MLDC26032	A RESEARCH PAPER ON A STUDY ON EXAMINE THE EFFECT OF FINTECH SERVICES ON THE GROWTH OF ECONOMY	DR. SANTOSH KUMAR UKE DR. SURAJ PATEL	32

SOUVENIR

MLDC26033	SKILLS DEVELOPMENT AND MANAGEMENT EDUCATION	DR. SUCHITRA RATHI	33
MLDC26034	AGRICULTURE AND FOOD SECURITY IN DEVELOPED INDIA (VIKSIT BHARAT)	DR. ARCHANA S. MODAK	34
MLDC26035	INDIAN KNOWLEDGE SYSTEM (IKS) AND VIKSHIT BHARAT 2047	DR. MONIKA PATEL	35
MLDC26036	AGRICULTURE AND FOOD SECURITY	DR. RAJ KUMAR GAMBHIR	36
MLDC26037	MACHINE LEARNING IN CYBER SECURITY: STRENGTHENING DIGITAL INDIA FOR SUSTAINABLE GROWTH	MISS. SUMAN SHARMA	37
MLDC26038	DIGITAL TRANSFORMATION OF AGRICULTURE AND ITS IMPORTANCE IN ACHIEVING VIKSIT BHARAT 2047	DR. VAISHALI SARDE DR. PANKAJ SARDE	38
MLDC26039	ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CLINICAL HEALTHCARE SYSTEMS	DR. VIBHA DUBEY	39
MLDC26040	A STUDY ON PROSPECTIVE ROLE OF DAIRY PRODUCTS IN ACHIEVING VIKSIT BHARAT 2047: AN INTEGRATIVE FRAMEWORK FOR ECONOMIC GROWTH, NUTRITIONAL SECURITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT	MADHU KATARIA DR. S.K.SHRIVASTAVA	40
MLDC26041	ROLE OF FINTECH IN EDUCATION LOANS AND FINANCIAL INCLUSION: A CASE STUDY OF CHHATTISGARH	MRS. REEMA VERMA	41
MLDC26042	THE IMPACT OF E-COMMERCE ON THE RETAIL MARKET IN CHHATTISGARH.	DR. DHARMENDER SINGH DR. LALEE SHARMA	42
MLDC26043	ROLE OF IOT AND AI IN MANAGING HERITAGE TOURISM	KAVITA KUMARI BHARTI	43
MLDC26044	PLATFORM ECONOMY AND EMPLOYMENT GENERATION IN INDIA	DR. ROOPAM JAIN HAZRA	44
MLDC26045	USING MACHINE LEARNING TO SECURE DIGITAL PAYMENTS AND E-GOVERNANCE SYSTEMS	MISS. SIMARAN CHANDRAKAR	45
MLDC26046	WOMEN ENTREPRENEURSHIP AND INCLUSIVE TRADE PRACTICES	MISS SARITA DEVI	46

SOUVENIR

MLDC26047	SKILL DEVELOPMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MSME FOR VIKSIT BHARAT 2047	TRIPT KAUR DR DEWASHISH MUKHERJEE	47
MLDC26048	TECHNOLOGY DRIVEN- DIGITAL MUSEUMS: A NEW GATEWAY FOR CULTURAL HERITAGE IN THE JOURNEY TOWARDS VIKSIT BHARAT 2047	DHARMAKSHI SAHU	48
MLDC26049	ROLE OF DIGITAL BANKING AND FINANCIAL TECHNOLOGY IN THE GDP OF CHHATTISGARH	MR. RAKESH GONDWANI DR. SHWETA MAHAKALKAR	49
MLDC26050	ROLE OF DIGITAL EDUCATION IN ENHANCING SKILL DEVELOPMENT AND EMPLOYABILITY IN CHHATTISGARH	SUDHIR JAIN	50
MLDC26051	A COMPARATIVE STUDY OF MACHINE LEARNING APPROACHES FOR EARLY DETECTION OF DIABETES	SHRADDHA DOYE DR. OMPRAKASH CHANDRAKAR	51
MLDC26052	CORPORATE HOSPITALS IN SMART CITIES: CATALYSTS FOR SOCIO ECONOMIC DEVELOPMENT AND HEALTHCARE EXCELLENCE IN VIKSIT BHARAT 2047	MS. SHIVANGI DUBEY	52
MLDC26053	NEW DIMENSIONS OF JOURNALISM IN DEVELOPED INDIA	DR. AMAN JHA	53
MLDC26054	ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN AGRICULTURE AND FOOD SECURITY	MR. KHEMAN LAL SAHU	54
MLDC26055	ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PREVENTING CYBER CRIME IN DIGITAL INDIA	ROSHNI V. PASHINE	55
MLDC26056	INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP: SHAPING THE FUTURE THROUGH ONLINE BUSINESS	SANJIKA TIWARI DR. TAPESH CHANDRA GUPTA	56
MLDC26057	WOMEN ENTREPRENEURSHIP AND DIGITAL INNOVATION: BRIDGING THE GENDER GAP IN CHHATTISGARH	RAHUL TIWARI	57
MLDC26058	LEARNING OF HOW THEORETICAL MACHINE LEARNING CONCEPTS CAN BE USED TO ANALYZE, PREDICT, AND SUPPORT SOCIAL SUSTAINABILITY HEALTH CARE GOALS SPECIALLY CANCER EFFECTIVELY	PRIYANKA TIWARI DR ANUPA SINHA	58
MLDC26059	REVIEW ON SKILLS DEVELOPMENT & EDUCATION	ANSHIKA DUBEY	59

SOUVENIR

MLDC26060	GROWTH OF LIFE INSURANCE IN INDIA: AN ANALYSIS OF PREMIUM TRENDS, PENETRATION AND DENSITY	DR. YULENDRA KUMAR RAJPUT VIDHI CHHABRA	60
MLDC26061	DEEP LEARNING–BASED RICE DISEASE DETECTION IN CHHATTISGARH FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE DEVELOPMENT	NEHA TIKARIHA	61
MLDC26062	DIGITAL INCLUSION IN RURAL DEVELOPMENT TOWARDS VIKSIT BHARAT	DR. SWATI SHARMA	62
MLDC26063	EMPOWERING SELF-HELP GROUPS THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION: LEVERAGING TECHNOLOGY FOR INCLUSIVE ECONOMIC GROWTH IN INDIA UNDER THE VISION OF VIKSIT BHARAT 2047	TRIPTY DEWANGAN DR. ASHANAND MAKHIJA DR. H. S. BHATIA	63
MLDC26064	SKILLS DEVELOPMENT AND EDUCATION: INTEGRATING NEURAL NETWORKS FOR ENHANCED LEARNING OUTCOMES AND EMPLOYABILITY	DEEPSHIKHA SHARMA AMITA TELANG	64
MLDC26065	GREEN INNOVATION AND START-UP CULTURE: EVIDENCE FROM INDIAN ENTREPRENEURS	DR. ASHOK KUMAR JHA	65
MLDC26066	INTEGRATING COMPUTER EDUCATION FOR SKILLS DEVELOPMENT IN THE EDUCATION SYSTEM	DR. DEEPTI VERMA	66
MLDC26067	ECONOMIC IMPACT OF MACHINE LEARNING–BASED CANCER DIAGNOSIS IN INDIA'S HEALTHCARE SYSTEM	MRS. RUKMANI DIGRASKAR DR. ANUPA SINHA	67
MLDC26068	SKILL DEVELOPMENT IN EDUCATION	DR. PRAGATI DUBEY	68
MLDC26069	IMPACT OF CORPORATE GOVERNANCE IN COMPANY LAW REGIME: A KEY FOR VIKSIT BHARAT@2047	DR. ASHISH PRATAP SINGH	69
MLDC26070	SKILL DEVLOPMENT AND EDUCATION IN INDIA	DEVSHREE VERMA K.K. HARRIS	70
MLDC26071	ई-गवर्नेंस एवं डिजिटल सार्वजनिक सेवाएँ	डॉ. जी. डी. एस. बग्गा नूतन देशमुख	71
MLDC26072	छत्तीसगढ़ में दूध उत्पादन व्यवसाय: चुनौतियाँ और संभावनाएं	नमिता सिंह	72

SOUVENIR

MLDC26073	विकसित भारत की दिशा में प्रौद्योगिकी-संचालित उद्यानिकी व्यवसाय: कृषि, खाद्य सुरक्षा एवं सतत आर्थिक विकास का मूल्यांकन (छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ में)	सत्येन्द्र डॉ. शांतनु पॉल	73
MLDC26074	भारत 2047: सतत् आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में पर्यटन उद्योग की भूमिका	सोमा गोस्वामी	74
MLDC26075	परंपरा एवं प्रौद्योगिकी के मध्य सेतु के रूप में साहित्य	प्रज्ञा चौधरी डॉ. मालती तिवारी	75
MLDC26076	छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा चुनौतियां एवं संभावनाएं	डॉ. युलेंद्र कुमार राजपूत ओंकार प्रसाद साहू	76
MLDC26077	विकसित भारत के निर्माण में हिन्दी भाषा : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं समकालीन प्रासंगिकता	प्रीतम कुमार दास	77
MLDC26078	विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का भौगोलिक वितरण एवं सतत विकास	डॉ. श्वेता शर्मा	78
MLDC26079	डिजिटल इंडिया और होटल उद्योग: रायपुर (छत्तीसगढ़) का अध्ययन विकसित भारत–2047 के संदर्भ में	लोकेश कुमार साहू डॉ. श्वेता महाकालकर	79
MLDC26080	स्मार्ट सिटीज़ और शहरी विकास : ऐतिहासिक भारतीय संस्कृति एवं स्वदेशी ज्ञान प्रणाली का पुनरुत्थान	आशा गुप्ता डॉ. श्वेता महाकालकर	80
MLDC26081	प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्यटन विकास और चुनौतियां	जगदीश प्रसाद खटकर डॉ ए राजशेखर	81
MLDC26082	छत्तीसगढ़ में एमएसएमई में महिला उद्यमिता और तकनीकी नवाचार: एक अध्ययन	सुमन धृतलहरे डॉ. श्वेता महाकालकर	82
MLDC26083	स्मार्ट सिटी अवधारणा के अंतर्गत हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा सामाजिक उद्यमिता के नवाचारी प्रयासों का अध्ययन (प्रोजेक्ट शक्ति)	सुषमा पटले डॉ. प्रियंका बोस	83
MLDC26084	विकसित भारत 2047 के निर्माण में कौशल विकास एवं शिक्षा की भूमिका: एक शोधात्मक अध्ययन	डॉ. किरण अग्रवाल	84

SOUVENIR

MLDC26085	कौशल विकास में योग की भूमिका	डॉ. लक्ष्मीकांत साहू	85
MLDC26086	विकसित भारत में पत्रकारिता के आयाम	राम प्रसाद दुबे	86
MLDC26087	ई गवर्नेंस और डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं	डॉ राकेश कुमार चंद्राकर	87
MLDC26088	कृत्रिम बुद्धिमता और कौशल विकास विकसित भारत के महत्वपूर्ण आयाम	डॉ.किरण तिवारी	88
MLDC26089	निरंतरता का एक लक्ष्य: विकसित भारत @ 2047	डॉ. युलेंद्र कुमार राजपूत एकता ठाकुर	89
MLDC26090	विकसित भारत 2047: आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना फिनटेक और वित्तीय समावेशन	संगीता सेन डॉ.कमलजीत कौर	90
MLDC26091	कृषि एवं खाद्य सुरक्षा : चुनौतियाँ, अवसर एवं सतत समाधान	मोहन पटेल	91
MLDC26092	विकसित भारत 2047 हेतु औद्योगिक 4.0 एवं विनिर्माण में प्रौद्योगिकी की भूमिका का अध्ययन	मानवी शर्मा डॉ. संपदा भावे	92
MLDC26093	भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली का विकास व आर्थिक सशक्तिकरण में इसकी भूमिका	महिमा जोबनपुत्रा डॉ. ए. एन. माखीजा	93
MLDC26094	कृषि और खाद्य सुरक्षा	डॉ. दिव्या शुक्ला	94
MLDC26095	पर्यटन संस्कृति और विरासत	श्रीमती कुसुम राठौर,	95
MLDC26096	ई-गवर्नेंस और डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं	डॉ. संगीता घई	96
MLDC26097	आर्थिक विकास में मानव संसाधन प्रबंध की भूमिका	डॉ० गिरजा शंकर गुप्ता	97
MLDC26098	विकसित भारत @ 2047 : फल एवं फूल व्यवसाय के माध्यम से समावेशी आर्थिक विकास	ललित मोहन वर्मा	98
MLDC26099	विकसित भारत 2047 की दिशा में डिजिटल पत्रकारिता की भूमिका	श्रीमति गीता शर्मा	99
MLDC26100	ई-शासन और डिजिटल सार्वजनिक सेवाएँ	सुश्री माया निर्मलकर	100
MLDC26101	विकसित भारत में पत्रकारिता के नए आयाम	डॉ. लोकेश्वर प्रसाद सिन्हा,	101
MLDC26102	स्मार्ट सिटी और शहरी विकास	नीलू शुक्ला	102

SOUVENIR

MLDC26103	विकसित भारत अर्थव्यवस्था में ग्रामीण उद्यमी महिलाओं की सहभागिता: एक दृश्टिकोण	डॉ. मनोज कुमार शर्मा श्री ओम प्रकाश पटेल	103
MLDC26104	ई-शासन और डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं	डॉ. मनोज कुमार शर्मा श्री ओम प्रकाश पटेल	104
MLDC26105	छत्तीसगढ़ राज्य के आर्थिक विकास में प्लाईवुड उद्योग की भूमिका का अध्ययन: रायपुर जिले के संदर्भ में	देवाशीष मुखर्जी राकेश मनचंदा	105
MLDC26106	EMPOWERING BHARAT: FINANCIAL INCLUSION AND FINTECH FOR RURAL TRANSFORMATION AND URBAN GROWTH THROUGH ARTIFICIAL INTELLIGENCE	MANJU KUSHWAHA	106
MLDC26107	ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TRANSFORMING EDUCATION AND SKILL DEVELOPMENT	MS APARNA TIWARI	107
MLDC26108	INNOVATION & ENTERPRENEURSHIP	MS. JALPA SONI	108
MLDC26109	Enhancing Citizen Participation and Trust through Digital Innovation	Neeta Dhanga Kiran Bala Dubey	109

SOUVENIR

ABSTRACT

SOUVENIR

MLDC26001

To study "Viksit Bharat @ 2047: Leveraging Technology for Sustainable Development through Innovation and Entrepreneurship in Chhattisgarh"

DR. NIDHI SHRI SHUKLA
ASSISTANT PROFESSOR, VIPRA ARTS COMMERCE & PHYSICAL EDUCATION, RAIPUR (C.G.)

DR. ASHOK KUMAR SHARMA
PROFESSOR, GOVT.J.YOGANANDAM CHHATTISGARH COLLEGE, RAIPUR (C.G.)

MONARK SINGH THAKUR
RESEARCH SCHOLAR, GOVT. J. YOGANANDAM CHHATTISGARH COLLEGE, RAIPUR (C.G.)

Abstract-
This study is conducted to "Viksit Bharat 2047: Leveraging Technology for Sustainable Development through Innovation and Entrepreneurship in Chhattisgarh". This research focuses on how technology-based innovation and entrepreneurial activities can contribute to sustainable development in the state of Chhattisgarh. Viksit Bharat @ 2047: A Vision for India's growth and development, aiming to create a nation that is economically robust, socially inclusive, and environmentally sustainable. The vision highlights the importance of promoting technological innovation, fostering entrepreneurship, and improving skill development to build a knowledge-based economy. It also stresses the need of effective governance and transparency to ensure responsible and effective institutions along with the need for international collaboration to tackle global challenges together.

Keywords- Viksit Bharat, Chhattisgarh, Economic growth, Environmental Sustainability, Technological advancement, and good governance.

SOUVENIR

MLDC26002

VIKSIT BHARAT 2047 :LEVERAGING TECHNOLOGY FOR ECONOMIC GROWTH IN RELATION TO FINTECH AND FINANCIAL INCLUSION

DR. ARADHANA SHUKLA
ASSISTANT PROFESSOR, VIPRA KALA,VANIJYA AVAM SHARIRIK SHIKSHA MAHAVIDYALAYA,RAIPUR (C.G.)

DR. ASHOK KUMAR SHARMA
PROFESSOR, GOVT. J.YOGANANDAM CHHATTISGARH COLLEGE, RAIPUR (C.G.)

MS. NEETU MINJ
RESEARCH SCHOLAR, GOVT. J.YOGANANDAM CHHATTISGARH COLLEGE, RAIPUR (C.G.)

Abstract-
In 2047, Viksit Bharat aims to have transformed India into a fully developed, equitably distributed and highly prosperous nation where technology will have played a key role in the growth process. In the state of Chhattisgarh, located in India where it is known for its high numbers of rural and tribal communities, there is an on-going study of FinTech & effects on development in the economy. This study is examining how equitable economic growth can be increased through this. One of the significant developments in banking has been the creation of on-line banking systems which allow customers to access a range of banking services. Among the schemes is a mobile banking system, along with the Unified Payment Interface and Direct Benefits Transfer. Also included are Aadhaar related banking services. Financial and digital services designed for the finance sector which include electronic payment options and credit schemes have helped to benefit women and small scale enterprises who are economically disadvantaged. Currently the development of information and communication technology is hindered by a few main problems; these include a lack in digital literacy skills and inadequate internet access in rural regions. In order to make a meaningful contribution towards Viksit Bharat 2047 in the state of Chhattisgarh, it is necessary that there is significant improvement in digital infrastructure along with a state of financial literacy that is more knowledgeable.

Keywords- Chhattisgarh,Fintech,Viksit Bharat 2047,Technology.

SOUVENIR

MLDC26003

INTEGRATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION

RAVINDRA SINGH
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE
DURGA COLLEGE, RAIPUR (C.G)

Abstract-
In today's era, the need for artificial intelligence is playing an important role in education. In the coming times, artificial intelligence will be required to take education to a new direction and new dimension. It has to be adopted from today itself and preparations for the new era have to be made so that the coming generation can adopt a new technology and take education in a new direction, which will make education easy and simple.

Keywords: - integration of artificial intelligence, education, learning behaviors.

SOUVENIR

MLDC26004

THE ROLE OF AI AND BIG DATA FOR VIKSIT BHARAT 2047

DR. PREM KUMAR CHANDRAKAR
ASSISTANT PROFESSOR & HEAD, DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE
MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR, CHHATTISGARH

Abstract-
Viksit Bharat 2047 envisions India as a developed and self-reliant nation, emphasizing economic growth, social equity, and sustainable development. The realization of this ambitious national vision is intrinsically linked to the strategic adoption of transformative technologies, with Artificial Intelligence (AI) and Big Data Analytics positioned as critical enablers. The main objective of this paper is to analyze and present the versatile role of AI and Big Data Analytics in shaping a Viksit Bharat 2047. It aims to explore how these technologies drive efficiency, innovation, and inclusivity across key sectors to support the national goals of Viksit Bharat 2047. The analysis is conducted through a comprehensive review of current technological applications, existing policy frameworks, and future roadmaps. It employs a sectoral approach, examining case studies and trends in agriculture, healthcare, education, finance, urban management (smart cities), and digital governance to extrapolate their evolved state by 2047. The findings indicate that AI and Big Data are pivotal in enhancing productivity and decision-making. In the envisioned 2047 scenario, they enable precision agriculture, predictive healthcare, personalized education, efficient smart cities, and transparent governance. However, the results also highlight significant concurrent challenges, including data privacy risks, the digital divide, a shortage of skilled professionals, and ethical concerns in automated decision-making. It is concluded that while AI and Big Data Analytics possess the transformative potential to strongly accelerate India's journey toward Viksit Bharat 2047, their success is contingent upon addressing associated challenges. This necessitates robust policy regulations, widespread skill development, and a commitment to ethical and inclusive implementation to ensure technology acts as a catalyst for equitable and sustainable national development

Keywords- Accuracy, Big Data, Classification, Hadoop, Weaka, Viksit Bharat 2047,

SOUVENIR

MLDC26005

Leveraging Artificial Intelligence for Sustainable Economic Development in India: Aligning with Viksit Bharat 2047

VIVEK PRAKASH SAHU
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE
MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR

Abstract: Artificial Intelligence (AI) has emerged as one of the most transformative technologies of the twenty-first century, significantly influencing economic growth, productivity, governance, and social development worldwide. For India, a rapidly developing economy, AI presents an unprecedented opportunity to accelerate economic transformation and achieve the national vision of Viksit Bharat 2047, which aims to build a developed, inclusive, innovative, and sustainable nation by the centenary of independence. This paper examines the role of Artificial Intelligence in India's economic development using a descriptive and analytical approach. It explores sector-wise applications of AI in agriculture, manufacturing, healthcare, education, and governance, along with its implications for employment and sustainability. The study also highlights challenges such as skill gaps, ethical concerns, data privacy issues, and digital inequality. The paper concludes that strategic, ethical, and inclusive adoption of AI, supported by strong policy frameworks and human capital development, can significantly contribute to achieving the goals of Viksit Bharat 2047.

Keywords: Artificial Intelligence, Digital Transformation, Economic Development, Innovation, Sustainable Growth, Viksit Bharat 2047.

SOUVENIR

MLDC26006

National Education Policy 2020 as the Foundation for a Global Knowledge Superpower by 2047

DR. JAYA CHANDRA,
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF MANAGEMENT
THE ICFAI UNIVERSITY, RAIPUR (C.G)

Abstract

As India approaches the centenary of its independence in 2047, the nation stands at a critical juncture characterized by a unique demographic advantage and ambitious economic aspirations. The vision of Viksit Bharat @2047—a fully developed and globally competitive India—depends fundamentally on the quality, inclusiveness, and adaptability of its education system. In this context, the National Education Policy (NEP) 2020 emerges as a transformative framework aimed at restructuring Indian education to make it holistic, multidisciplinary, flexible, and innovation-driven. This research paper critically examines the role of NEP 2020 in shaping India's long-term knowledge future. It analyzes key structural reforms across school education, higher education, teacher preparation, research, and digital transformation, while assessing progress in implementation up to 2025. The study argues that NEP 2020 provides the institutional and intellectual foundation necessary for India to evolve into a global knowledge superpower by 2047, provided challenges related to financing, federal coordination, equity, and digital access are systematically addressed.

Keywords: National Education Policy 2020, Viksit Bharat @2047, Knowledge Economy, Multidisciplinary Education, Human Capital Development

SOUVENIR

MLDC26007

An Analytical Study of Authorial Perspective in *Sleeping India: Barriers to Viksit Bharat*

DR SHRUTI TIWARI
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF ENGLISH
MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR

Abstract-
Viksit Bharat or Developed India is an extensive vision of Government of India. It endeavors to make India a developed country in 100th year of independence by 2047. It is based on the vision of Holistic development in every field of the nation. Sleeping is an active andcomplex biological process through which the body and brain enter a state of distorted consciousness and reduced physical activity. It gives restoration for learning, healing, and regulating metabolism. It is an essential element of growth of the body.

Sleeping India: Barriers to Viksit Bharat is a the most famous work of Aman Shukla. It is published in 21st July 2025.Aman elucidates sleeping of India. It is not the usual sleep for rest and peace, but a deep sleep of ignorance. It plays the role of abarrier to Viksit Bharat. This paper examines Shukla's vision of Viksit Bharat by analyzing his key ideas and arguments, while treating technological advancement as a secondary concern.

Sleeping India: Barriers to Viksit Bharat is a provocative work and presents the deep Innate issues like casteism, unemployment, hypocrisy, toxic media and communalism as a real hurdle to making India a prosperous, self-reliant, and modern nation which will have strong economic growth, world-class education, quality healthcare, green energy, women's empowerment, and good governance contributing towards Viksit Bharat.

Keywords- Barriers, Casteism, Communalism Hypocrisy, Sleeping, Unemployment and Viksit Bharat

SOUVENIR

MLDC26008

Technology-Enabled Agricultural Credit Systems and Their Role in Achieving Viksit Bharat 2047

MS. AANCHAL MISHRA
RESEARCH SCHOLAR (COMMERCE), DURGA MAHAVIDYALAYA, RAIPUR

DR. RAJENDRA KUMAR SHUKLA
ASSISTANT PROFESSOR (COMMERCE), DURGA MAHAVIDYALAYA, RAIPUR

Abstract-
Agriculture is the backbone of Indian economy. It plays a vital role in improving financial status of the majority population as it is a major source of income for them. Since agriculture is still a major factor in India's socioeconomic transformation, Viksit Bharat 2047 emphasises inclusive economic growth and sustainable development. Obtaining timely and adequate agricultural financing remains a significant challenge for farmers, particularly small and marginal farmers. Credit plays a crucial role for the success of agricultural goals for the farmers. And with the development of technology, the use of technology in agricultural lending institutions has significantly altered the way financial services are delivered in rural India in recent years. This study examines how technology-enabled agricultural lending systems promote farmers' economic empowerment and sustainable agricultural growth in the context of Viksit Bharat 2047. The study used a descriptive methodology and secondary data from government documents, financial organisations, and earlier research. It looks at how financial inclusion, credit accessibility and dependence on unofficial moneylenders are impacted by digital platforms, fintech developments, data-driven credit evaluation and digital payment systems. The research also highlights significant challenges such gaps in financial literacy, infrastructure limitations and the digital divide. The study suggests that by 2047, technology-driven agricultural financing systems might enhance rural livelihoods, promote ecologically friendly farming practices and accelerate India's shift to a modern economy. The study's conclusion includes policy recommendations for enhancing the awareness about technology-driven credit facilities, effectiveness and inclusivity of agricultural finance systems.

Keywords: Technology-Enabled Credit, Agricultural Finance, Financial Inclusion, Viksit Bharat 2047

SOUVENIR

MLDC26009

A STUDY ON THE IMPACT OF INDUSTRY 4.0 ON INDIAN MANUFACTURING SYSTEM & INDIA'S VISION OF VIKSIT BHARAT 2047

DR. APURVA SHARMA
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF COMMERCE
MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE

Abstract :
This research paper covers the historical convergence of industrial revolution to Industry 4.0, the concept of the nine- pillars of Industry 4.0, its interaction with the Indian Manufacturing system. Furthermore it shows the top most leading companies and top 5 states of India working towards the movement of Industry 4.0. This paper also addresses the benefits such as sustainable development, optimization, the increase in productivity and challenges such as risk of cyber security, lack of infrastructure, lack of technological exposures of Industry 4.0 in manufacturing system of India. The research paper also mentions on how the adoption of Industry 4.0 is directly linked to the India's long-term goals and turning the manifestation of Viksit Bharat 2047 making India a developed nation and a strong economy to stand in global competitiveness. The study also enhances the future roadmap of Viksit Bharat 2047 and providing an outlook for Industry 5.0 which is a compliment to Industry 4.0 focusing on human centric design and sustainability.

Keywords: Industry 4.0 , Indian economy, Digitalization, Viksit Bharat 2047

SOUVENIR

MLDC26010

Past Life Regression: A Therapeutic Approach in the Vision of Viksit Bharat

DR MEGHA SINGH
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF ENGLISH
MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR

DR. JAYA CHANDRA
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF MANAGEMENT
ICFAI UNIVERSITY, RAIPUR

Abstract:
Modern men are living in chaos. They undergo conflict of emotions –stress, fear, anger, anxiety, and depression. Technology has become an utmost necessity in the contemporary society. It is an incredible tool in the digital era, a breath and soul for sustainable development of society. Attaining emotional well-being is a significant challenge in the present era. The present paper explores the significance of Past Life Regression, an advanced scientific technique, a convincing, practical and therapeutic approach to get rid of emotional traumas.

Past life Regression Practitioners claim that unresolved emotional patterns, fears, or traumas in the present life may stem from experiences carried over from past lives. The therapy aims to help individuals gain insight, emotional release, and personal transformation.

The paper delves deep in to Past Life Regression Therapy in the context of Viksit Bharat embodying spiritual wisdom of ancient India and techniques like meditation, Yoga to harness the power of subconscious mind, dealing in depth with human beings, their psyche. Transformation of consciousness is possible in tech driven society and Past life Regression has evolved as a new mechanism of survival in the digital era.

Keywords: Digital Era, Emotions, Past life Regression, Subconscious and Therapy.

SOUVENIR

MLDC26011

Impact of Green HRM Practices on Organizational Sustainability and Employee Retention

JEEWAN JYOTI SINGH
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF MANAGEMENT
MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR

Abstract

Green Human Resource Management (Green HRM) is an emerging concept that integrates environmental sustainability into human resource policies and practices. It emphasizes eco-friendly recruitment, training, performance appraisal, rewards, and employee engagement to foster long-term organizational sustainability while enhancing employee retention. This research examines how Green HRM practices influence both organizational outcomes (macro-level) and individual employee outcomes (micro-level). Secondary sources such as peer-reviewed articles, case studies, and industry reports were analyzed to understand these effects. Findings suggest that organizations implementing Green HRM benefit from reduced operational costs, improved environmental performance, and enhanced brand reputation, while employees experience higher job satisfaction, engagement, and loyalty, reducing turnover intention. The analysis highlights the mediating role of engagement and organizational commitment in linking green HRM practices to retention. Strategic adoption of Green HRM thus fosters a virtuous cycle of sustainability and workforce stability, benefiting both the organization and its employees (Azeez, 2017; Dutta, 2012; Margaretha & Saragih, 2013; Pillai & Sivathanu, 2014; Renwick et al., 2013; Yusoff et al., 2015).

Keywords: Green HRM, Organizational Sustainability, Employee Retention, Eco-friendly HR Practices, Work Engagement.

SOUVENIR

MLDC26012

Role of Government Policy and Industrial Ecosystems in Promoting Industry 4.0 in Chhattisgarh's Manufacturing Clusters: A Critical Literature Review

POONAM TANDEKAR [1]
RESEARCH SCHOLAR, MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR

DR. SHANTANU PAUL [2]
PROFESSOR & HOD (DEPT. OF COMMERCE), MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR, CHHATTISGARH

Abstract
Industry 4.0 is transforming manufacturing worldwide, and its adoption in India is central to the Viksit Bharat 2047 vision for economic growth and sustainable development. This this research paper examines how government policy and industrial ecosystems promote Industry 4.0 in Chhattisgarh's manufacturing clusters. Drawing on secondary data, the review synthesizes research on policy frameworks, ecosystem factors, and barriers to digital transformation. Evidence shows that government support, financial incentives, and targeted training are key enablers, while lack of digital strategy, resource constraints, and workforce readiness remain major barriers. Industrial ecosystems comprising firms, educational institutions, and policymakers play a vital role in fostering collaboration, innovation, and skills development. The review highlights the alignment of national initiatives like Make in India, Digital India, and Samarth Udyog 4.0 with Chhattisgarh's industrial policy, but also identifies gaps in local implementation, infrastructure, and SME engagement. The findings suggest that a coordinated, place-based approach involving all ecosystem actors is essential for successful Industry 4.0 adoption. The review concludes by identifying research gaps and proposing directions for future studies to support Chhattisgarh's journey toward a sustainable, technology-driven manufacturing sector.

Keywords: Industry 4.0, Government Policy, Industrial Ecosystem, Manufacturing Clusters, Chhattisgarh, Digital Transformation, Viksit Bharat 2047, Sustainable Development, SME, Skills Development.

SOUVENIR

MLDC26013

Bridging Tradition and Technology: A Study on the Integration of Cultural Heritage and Digital Innovation in India

DR. SHILPA WADHWA
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF ENGLISH
MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR

Abstract
The relationship between tradition and technology has evolved from contradiction to collaboration in the 21st century. As societies become more digitally interconnected, the survival and relevance of cultural traditions depend on how well they adapt to technological environments. This paper examines how digital innovation—through Artificial Intelligence (AI), Virtual Reality (VR), Blockchain, and digital marketplaces—is bridging the gap between India's rich cultural traditions and modern technological ecosystems. Using secondary data from 2018–2025, it analyzes national initiatives, academic studies, and case examples to understand how technology is preserving, transforming, and globalizing India's cultural identity. Findings reveal that technology, when guided by ethical frameworks and community participation, not only safeguards traditional knowledge but also revitalizes cultural industries and strengthens socio-economic inclusion. The study concludes that the true strength of modern India lies in harmonizing its ancient wisdom with the power of contemporary digital tools.

Keywords:
Tradition, Technology, Cultural Heritage, Digital Innovation, India, Preservation, Modernization, Cultural Sustainability.

SOUVENIR

MLDC26014

Synergizing Technology and Enterprise: A Study on Innovation-Led Entrepreneurial Growth in Chhattisgarh

MRS. DHANLAXMI DIWAN,
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF JOURNALISM
MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR

Abstract

This research paper examines how technology and entrepreneurship work together to drive economic growth in Chhattisgarh. The study looks at the state's startup ecosystem, government policies, and innovation support systems. Chhattisgarh has shown steady progress in building an environment where new businesses can grow. The state government launched several policies between 2016 and 2024 to support startups. These include financial help, incubation centers, and single-window clearance systems. As of 31st October 2025, Chhattisgarh has recognized 2143 startups and 917 Women-Led Startups/Women Entrepreneurs under the DPIIT framework. The state focuses on agriculture technology, manufacturing, and IT services.

This paper connects these local efforts with India's vision for 2047, known as "Viksit Bharat". The vision aims to make India a developed nation by 2047. Chhattisgarh's role in this plan includes creating jobs, increasing per capita income, and building innovation infrastructure. The Industrial Development Policy 2024-30 sets targets for investment, employment generation, and technology adoption. Events like Chhattisgarh TechStart 2025 and Tribal Business Conclave 2025 show the state's commitment to connecting startups with investors. This study uses secondary data from government reports, research papers, and policy documents. The findings show that while Chhattisgarh has made progress, challenges remain. These include limited access to capital, lack of skilled workforce, and weak industry-academia linkages. The paper suggests that continuous policy support, better funding mechanisms, and stronger networks can help Chhattisgarh contribute meaningfully to India's 2047 goals. The study concludes that innovation-led growth is possible when government, entrepreneurs, and technology work together.

Keywords: Technology adoption, Entrepreneurship, Startup ecosystem, Innovation policy, Chhattisgarh economy, Viksit Bharat 2047, Industrial development, DPIIT recognition, Government schemes, Economic growth

SOUVENIR

MLDC26015

Millet-Based Dietary Practices and Food Security in Raipur District: An Analysis of Consumer Awareness

ASHU THAKUR [1]
RESEARCH SCHOLAR, MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR

DR. SHANTANU PAUL [2]
PROFESSOR & HOD (DEPT. OF COMMERCE), MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR, CHHATTISGARH

Abstract

This study examines millet consumption and consumer awareness in Raipur district, Chhattisgarh, India, collecting primary data from 82 respondents through a structured questionnaire. Despite millets being nutritious and climate-resilient crops, their consumption remains low. Findings reveal that while 98.78% of respondents have heard about millets, only 31.70% possess high awareness of health benefits, and merely 28.05% consume them regularly (daily or weekly). Chi-square tests demonstrate highly significant associations between awareness and consumption ($\chi^2 = 42.85$, $p < 0.001$), market availability and consumption ($\chi^2 = 28.94$, $p < 0.001$), and affordability and consumption ($\chi^2 = 18.67$, $p < 0.001$). Primary barriers include lack of detailed awareness (29.27%) and limited market availability (25.61%).

The study aligns with Viksit Bharat 2047 goals and concludes that targeted consumer education combined with improved market access are essential to mainstream millet consumption. These evidence-based insights can guide policymakers and stakeholders in promoting millets as part of India's nutritional security and sustainable development strategy.

Keywords: Millets, Food Security, Consumer Awareness, Dietary Practices, Raipur District, Nutritional Security, Climate-Resilient Crops, Viksit Bharat 2047, Sustainable Development, International Year of Millets

SOUVENIR

MLDC26016

Accelerating Towards a Tech savvy India: Role Of Knowledge Economy In India's Growth

DR. SHANTANU PAUL [1]
PROFESSOR & HOD (DEPT. OF COMMERCE),
MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR,

MS. ANJALI MAJUMDAR [2]
RESEARCH SCHOLAR, MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR

Abstract:
"I and you should all encourage people for a Viksit Bharat , we should motivate especially young minds to realize their dreams" PM Modi

The Indian economy has been digitalising at a significant pace over the last decade. As per a report "India is the third largest digitised country in the world. It is expected to contribute nearly one -fifth of national income by 2029-30. India being the youngest country where youth population comprises 27% of the total population (below the age of 35 years) and nearly 37.1 crore Indians falling within the 15-29 age group. Therefore , seeing a higher potential in these igniting minds this paper examine how technology has brought modernisation (education) with digital pedagogy and the tireless efforts by the government towards building Digital Public infrastructure with its impact on employability standards based on education and gender basis in various sectors of economy specifically focussing on through Skill India Mission and education infrastructure. This also highlights the challenges arising in fulfilling the gap due to digital divide. Initiating from the historical background that dates back how India has revolutionised itself in modernising itself since 1990s and how it will plan to fulfil the dream of "Viksit Bharat "by availing the adequate training to youths of India under National digital education Architecture as per National education policy 2020. At the end , it concludes with suggestive measures to overcome large gaps through scaling up training framework making it accessible in the remotest areas across India.

Keywords : Digitalisation, National Digital Education Architecture , Workforce, National income ,Digital Public Infrastructure , Skill India Mission , National Education Policy, Digital Pedagogy ,Employability

SOUVENIR

MLDC26017

Industry 4.0 in Manufacturing: A Paradigm Shift in Industrial Production

DR. RISHI PANDEY
HEAD, DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE
MAHARAJA AGRASEN INTERNATIONAL COLLEGE, RAIPUR CHHATTISGARH

Abstract:
Industry 4.0 represents a fundamental shift in manufacturing, characterized by the integration of digital technologies into industrial production systems. This paradigm emphasizes the convergence of cyber-physical systems, the Internet of Things, artificial intelligence, big data analytics, and advanced automation to create smart, interconnected, and autonomous manufacturing environments. The objective of this paper is to examine how Industry 4.0 is transforming traditional manufacturing models into data-driven, flexible, and efficient production systems.

The study explores key enabling technologies of Industry 4.0 and analyzes their impact on productivity, operational efficiency, quality management, and supply chain integration. It further discusses the organizational and technological challenges associated with implementation, including system interoperability, cybersecurity risks, workforce skill gaps, and high investment costs. By synthesizing recent literature and industry practices, the paper highlights the strategic benefits of Industry 4.0 adoption, such as mass customization, predictive maintenance, real-time decision-making, and enhanced competitiveness.

The findings suggest that Industry 4.0 is not merely a technological upgrade but a comprehensive transformation of industrial production that requires alignment between technology, processes, and human resources. This paper contributes to a deeper understanding of Industry 4.0 in manufacturing and provides insights for researchers, practitioners, and policymakers seeking to navigate the transition toward smart and sustainable industrial production systems.

Keywords: Industry 4.0,Smart Manufacturing, Digital Transformation, Cyber-Physical Systems (CPS),Internet of Things (IoT),Artificial Intelligence (AI),Big Data Analytics, Advanced Automation

SOUVENIR

MLDC26018

A Research on General Progressive Dimensions & Approaches in Green Marketing – Benefits, Opportunities and Challenges

ADITI SHARMA [1]
RESEARCH SCHOLAR, GOVT. J YOGANANDAM CHHATTISGARH COLLEGE, RAIPUR

DR. TAPESH CHANDRA GUPTA [2]
PRINCIPAL, GOVT. J YOGANANDAM CHHATTISGARH COLLEGE, RAIPUR.

Abstract: The importance of green marketing can be understood from the fact that in today's environment, most customers worldwide want to purchase products from, establish relationships with, and maintain relationships with companies that prioritize environmental protection and demonstrate accountability in this regard. Customers have the perspective that a company's environmental consciousness should be a priority within their business operations, and that this should be even more impactful than customer trust, values, and care. Customers are also aware of and concerned about environmental issues such as pollution, global warming, rising earth temperatures, and rising sea levels. Therefore, green marketing involves developing business strategies that facilitate sustainable development. Companies that understand the purpose of green marketing and are committed to taking effective action for environmental protection should take serious steps in various activities such as manufacturing recycled products, reusing water, using as many eco-friendly materials as possible, and reducing toxicity. This will help promote the use of green products among customers and contribute significantly to sustainable development in the future. This research paper provides a detailed examination of the various benefits and opportunities of green marketing, aiming to understand the challenges faced by green marketers and to outline the key principles for making green marketing more effective and impactful. This initiative will also focus on various challenges in order to promote green businesses and encourage the production, understanding, and purchase of green and eco-friendly products in the future, thereby contributing to the betterment of society and opening up numerous opportunities.

Keywords: Green Marketing, Eco-Friendly Products, Sustainable Development.

SOUVENIR

MLDC26019

Role of Agriculture in Building a Developed India 2047

MRS. SANA KHAN
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE
MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR

Abstract:
Agriculture has served as the foundational pillar of India's economy, culture, and social fabric since ancient times, critically underpinning food security, employment, and rural development. In the vision of a Viksit Bharat (Developed India), the sector has evolved beyond mere subsistence farming, emerging as a central driver of economic growth, technological advancement, environmental sustainability, and social stability. This paper examines agriculture's role in realizing a developed India by analyzing its contributions to economic progress, employment, exports, rural prosperity, and ecological balance. It further identifies key challenges confronting the sector and proposes policy measures to reinforce agriculture as a cornerstone of inclusive and sustainable national development.

Keywords: Agriculture, Environmental Sustainability, Food Security, Rural Development, Sustainable Agriculture, , Vikshit Bharat

SOUVENIR

MLDC26020

Transition from a Mono-Product to Revenue Streams: Integrated Pescatourism Business Model Canvas Analysis

DR. NEETU GUPTA [1]
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF COMMERCE,
ST. VINCENT PALLOTTI COLLEGE, RAIPUR, (C.G.)

DR. PRACHI SINGH [2]
HOD, MANAGEMENT DEPARTMENT
MAHARAJA AGRASEN COLLEGE, RAIPUR, (C.G.)

MR. VAIBHAV SHRIVASTAVA [3]
HOD, DEPARTMENT OF COMMERCE
ST. VINCENT PALLOTTI COLLEGE, RAIPUR, (C.G.)

Abstract: The aquaculture industry has traditionally functioned with high production, low-margin and traditional business approach. This mono-product business model leaves Small and Medium Enterprises (SMEs) highly vulnerable due to increasing input cost, supply chain inefficiencies and highly fluctuating market price. In this paradigm concept of Pescatourism- the integration of aquaculture business with tourism and services, gains strategic importance for business model innovation and financial resilience. This study focuses in commercial viability of Pescatourism Business Model to generate multi-revenue system. The research helps in examining value proposition, cost structure and profit margin using Osterwalder Business Model Canvas (BMC) as analytical framework. The paper employs comparative case study methodology of traditional and integrated pescatourism firms. Comprehensive review from different case studies provides practical insights to diverse approaches and outcomes in implementation of this model. Qualitative data gathered through semi-structured interviews with industry stake holders helps in evaluation of impact, challenges and future direction of tourism business. Preliminary analysis showed higher initial Capital Expenditure (CAPEX), though by providing retail value of products to customer, 'payback period' (PBP) can be reduced. The study provides a strategic roadmap for aquapreneures to operate as commercial service hubs, thereby enhancing the socio-economic sustainability of rural communities.

Keywords: Aquaculture, Pescatourism, Business Model Canvas (BMC), Value addition, Revenue Generation, Fish Farmers.

SOUVENIR

MLDC26021

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN FINTECH – A STUDY

OSIN KUNJAM [1]
RESEARCH SCHOLAR, INSTITUTE OF MANAGEMENT

SAMIKSHA PANDEY [2]
RESEARCH SCHOLAR, INSTITUTE OF MANAGEMENT

PROF. (DR.) G.K. DESHMUKH [3]
DIRECTOR AND DEAN, INSTITUTE OF MANAGEMENT
PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR, CHHATTISGARH

Abstract:
Artificial Intelligence (AI) is used in all walks of life now-a-days due to its ability to provide faster and smarter assistance that further enhances efficiency and reduces human error. AI is also used in the field of finance particularly in the area of financial technology at world level. The use of AI is creating significant change in the finance industry while providing novel approaches and helping us understand financial matters for optimized decision making. This review-based study examines the applications, benefits, and challenges of AI adoption in Fintech. The present study is an attempt to review the articles published on the application of artificial intelligence in fintech during 2025 by using keywords like Artificial Intelligence, Financial innovation, Fintech industry, etc. The review shows that AI significantly enhances operational efficiency, accuracy, personalization, and risk management for financial institutions. It also enables data-driven decision-making and expands financial inclusion through innovative digital solutions. In nutshell, this study aggregates current research trends and provides insight into how AI continues to revolutionize financial services; hence it will be helpful to academicians and researchers. It will also offer valuable implications to policymakers, government officials and individual practitioners seeking to understand AI's strategic role in the fintech.

Keywords: Artificial Intelligence (AI), Finance, Fintech, Innovation, Operational Efficiency

SOUVENIR

MLDC26022

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) ASSISTED SHOPPING: A STUDY

SAMIKSHA PANDEY [1]
RESEARCH SCHOLAR, INSTITUTE OF MANAGEMENT

OSIN KUNJAM [2]
RESEARCH SCHOLAR, INSTITUTE OF MANAGEMENT

PROF. (DR.) G.K. DESHMUKH [3]
DIRECTOR AND DEAN, INSTITUTE OF MANAGEMENT
PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR, CHHATTISGARH

Abstract:
In today's busy life everyone wishes to save their precious time. So, getting assistance from Artificial intelligence (AI) or using AI tools have become common in every field. Customers are taking help of AI for shopping. They are using conversational AI-powered assistants, and recommendation engines to arrive at a decision to buy. AI provides immediate data, compare options, find appropriate goods, and provide recommendations to customers based on their interests. Consequently, AI-assisted shopping increases customer pleasure, decreases search efforts, and helps in decision making while providing customized product information on the basis of their inputs. The efficacy of AI-assisted purchase, despite its increasing popularity, is highly dependent on elements like perceived utility, usability, trust, data protection, and accessibility of artificial intelligence (AI) systems. This review paper is an attempt to understand how AI tools help customers in information search, product evaluation and how they provide personalized recommendation to them. This paper will provide insights to researchers and academicians about assistance provided by AI to customers for shopping different products. These insights can further be used to develop new theories or conduct further research. The paper will also provide insights to customers that how and why AI can be used in shopping. The paper will also provide insights to government officials involved in policy making to ensure ethical and proper usages of AI by citizens.

Keywords: AI Tools, AI assisted shopping, Perceived utility, Usability, Trust

SOUVENIR

MLDC26023

Green Computing and Energy Efficient Digital Infrastructure for Sustainable Economic Growth in Viksit Bharat 2047

SWATI JAIN [1]
ASSISTANT PROFESSOR,
GOVT. J. YOGANANDAM CHHATTISGARH COLLEGE, RAIPUR

MUKESH KASHYAP [2]
RESEARCH SCHOLAR, SCHOOL OF STUDIES IN COMPUTER SCIENCE &
INFORMATION TECHNOLOGY, PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR,

SANJAY KUMAR [3]
PROFESSOR, SCHOOL OF STUDIES IN COMPUTER SCIENCE &
INFORMATION TECHNOLOGY, PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR,

Abstract:
The vision of Viksit Bharat 2047 emphasizes sustainable economic growth driven by rapid digital transformation. However, the increasing reliance on data intensive services, cloud platforms, and smart systems has significantly amplified the energy consumption and carbon footprint of digital infrastructure. Addressing this challenge requires an architecture centric approach to green computing and energy efficient infrastructure design.

This paper investigates the role of energy efficient computer architectures in enabling sustainable digital infrastructure for a developed India. The study focuses on multicore and heterogeneous processor designs, memory hierarchy and cache optimization techniques, and power aware microarchitectural mechanisms such as dynamic voltage and frequency scaling (DVFS) and power gating. It further examines the integration of renewable energy sources with digital infrastructure, including green data centres and renewable powered edge computing systems.

Keywords: Green Computing; Energy Efficient Computer Architecture; Sustainable Digital Infrastructure; Renewable Energy Integration

SOUVENIR

MLDC26024

Study of the role and challenges of food processing industries of Khadi and village industries in the development of food security schemes in the state of Chhattisgarh.

BHUNESHWAR SAHU [1]
RESEARCH SCHOLAR, MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR

DR. DEWASHISH MUKHERJEE [2]
PRINCIPAL, MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR

Abstract:
The determination of poverty in India is based on calories, on the basis of which food value is equal to 2250 calories. According to the report of the expert group constituted by the Planning Commission, 2400 calories per person in rural areas and less than 2100 calories in urban areas are considered below the poverty line. Based on the report of the Rangarajan Committee, the poverty ratio in India (2011-12) is 39.90 percent in rural areas and 26.40 percent in urban areas and for all India. On base it was 29.50 percent. In India, 36.30 crore population is suffering from poverty. as per NITI Aayog 2011-12 state wise poverty situation, Chhattisgarh state's poverty line was above 40 per cent in rural areas and between 30-40 per cent in urban areas, in the Raghuram Rajan Committee (2013) report on this, among the 10 most backward states. Chhattisgarh state was ranked fourth in which 47.90 percent of the population was below the poverty line. The food security index of the state which was 66th rank in the year 2012 was 39th rank in the year 2016 but in 2018 the rank increased again to 76th rank. To address the above, strengthening the situation of food security has been an important challenge for the country, and for this, balancing the supply of food grains, availability of desired calories and reducing malnutrition has been the main goal. In the state of Chhattisgarh, Food and Nutrition Security Act 2012 has been implemented to ensure the right to food to the poor and needy of the state and to provide ration material as per their eligibility Which is the first state in the country. Schemes like Chirag Yojana, Millet Mission, Mukhyamantri Suposhan Abhiyan, Mid-Day Meal are run in the state, through which public distribution system provides food grains to the consumers at affordable prices, which is dependent on the food processing industry. Food Processing Industrial Policy 2012-19 has been implemented to promote the food processing industry in the state and efforts are being made to promote value addition to agricultural produce and employment generation through the Prime Minister's Employment Generation Program run by the Khadi and Village Industries Commission.

Keywords: Challenges, Chhattisgarh, Food Processing, Food Security, Industries

SOUVENIR

MLDC26025

Carrying Capacity of land in Dandakaranya Region

HIMANSHI GOLE
RESEARCH SCHOLAR, SCHOOL OF STUDIES IN GEOGRAPHY,
PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR.

DR. TIKE SINGH
SR. ASST. PROFESSOR, SCHOOL OF STUDIES IN GEOGRAPHY,
PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR.

Abstract:
The analysis is based on secondary data collected from Department of Agriculture and District Statistical Handbook 2022-2024. 32 tehsils of seven districts of Bastar division are taken as the unit of analysis. Population data is obtained from Census of India 2011 report. The concept of carrying capacity plays a vital role in understanding the sustainable limits of land resources in ecologically fragile and socio-culturally unique regions such as Dandakaranya. The region is marked by undulating plateau terrain, extensive forest cover, a predominantly tribal population, rain-fed farming systems, and inadequate infrastructure. This study evaluates the land carrying capacity of the Dandakaranya region through an analysis of the relationship between land capability, availability of natural resources, and traditional livelihood practices. Key indicators, including soil fertility, forest productivity, water resources, agricultural intensity, and population dynamics, are used to determine the ability of land resources to sustainably support the existing population. The results reveal that traditional subsistence-based livelihood systems earlier maintained a relative equilibrium between population and available resources. However, rapid population increase, deforestation, mining operations, and a growing shift towards market-driven land use have substantially diminished the region's carrying capacity. The study emphasizes the importance of adopting region-specific and ecologically sensitive land-use planning strategies that incorporate indigenous knowledge, forest protection, and sustainable agricultural practices to improve the long-term carrying capacity of the Dandakaranya region.

Key Words- Land Resources, Land Capability, Natural Resource Availability, Tribal Livelihood Systems, Forest Productivity.

SOUVENIR

MLDC26026

A Paradigm Shift: AI Integration within the Indian GST Framework

NAMRATA SINGH [1]
GOVT. DIGVIJAY PG AUTONOMOUS COLLEGE, RAJNANDGAON

ASHANAND MAKHIJA [2]
GOVT. SHIVNATH SCIENCE COLLEGE, RAJNANDGAON

H.S. BHATIA [3]
GOVT. DIGVIJAY PG AUTONOMOUS COLLEGE, RAJNANDGAON

Abstract:
The Indian textile industry, centered in regions like Rajnandgaon, Chhattisgarh, continues to face systemic hurdles in GST compliance. This study examines the potential of Artificial Intelligence (AI) to streamline these processes. It identifies a significant digital divide where small-scale enterprises are held back by high costs, limited digital literacy, and a lack of trust in automated systems. To address these gaps, the research proposes the adoption of affordable AI solutions, specialized training initiatives, and supportive government frameworks. By leveraging the expertise of Chartered Accountants and integrating AI, the industry can achieve greater transparency, operational efficiency, and global competitiveness.

Key words: Artificial Intelligence (AI), Goods and Services Tax (GST), Textile Industry, GST Compliance, AI Adoption, Affordable AI Solutions, Digital Transformation, Digital Literacy, Rajnandgaon, Digital Divide.

SOUVENIR

MLDC26027

Contribution of Mahtari Vandan Yojana towards Viksit Bharat 2047 through Women Empowerment in Chhattisgarh

SHUBHAM BHARDWAJ
RESEARCH SCHOLAR,
MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR

DR. SANJAY KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR (COMMERCE)
GOVT. PT. SHYAMACHARAN SHUKLA COLLEGE, DHARSIWA

Abstract:
Mahtari Vandan Yojana, launched by the Chhattisgarh government in March 2024, provides ₹1,000 monthly financial assistance via Direct Benefit Transfer to over 70 lakh eligible married women aged 21+, including widows and divorced women. This initiative addresses rural socio-economic challenges by enhancing economic self-reliance, health, nutrition, and family decision-making, directly supporting Viksit Bharat 2047's vision of inclusive growth with women as prosperity drivers. Empirical evidence from Palari Block survey (140 respondents, Balodabazar-Bhatapara district) documents 82.8% beneficiary satisfaction, priority spending on rations, education, and healthcare, and mean confidence improvement of 2.97/5. Over 95% bank account penetration facilitates seamless implementation, demonstrating strong financial inclusion infrastructure. This paper analyzes scheme impacts through secondary data and primary survey findings, linking outcomes to Sustainable Development Goal 5 (gender equality) and Viksit Bharat pillars of social welfare and economic empowerment. Key findings include improved household nutrition, reduced financial stress, and enhanced expenditure decision-making roles—critical for India's $30 trillion economy goal by 2047. Spatial implementation variations across rural districts highlight the scheme's scalability potential, building on prior geographic empowerment frameworks. While demonstrating high penetration, sustained impact requires skill development integration, SHG network linkages, and digital literacy programs. Policy recommendations emphasize real-time monitoring dashboards and annual statistical assessments using chi-square and regression analyses per established Palari protocols. Mahtari Vandan Yojana exemplifies state-level contributions to national development, offering a scalable model for gender-inclusive rural growth.

Keywords: Mahtari Vandan Yojana, Viksit Bharat 2047, women's empowerment, Chhattisgarh, financial inclusion

SOUVENIR

MLDC26028

Role of Technology in Promoting Tourism, Culture and Heritage under Viksit Bharat 2047 in Chhattisgarh

ASMITA SAHU
RESEARCH SCHOLAR, MATS UNIVERSITY, RAIPUR

DR. PRIYANKA BOSE
ASSISTANT PROFESSOR, MSBS DEPARTMENT
MATS UNIVERSITY, RAIPUR

Abstract:
This paper is descriptive in nature based on secondary data. The vision of Viksit Bharat 2047 emphasizes inclusive growth, cultural preservation, and sustainable development, where technology plays a transformative role in promoting tourism, culture, and heritage. Chhattisgarh, endowed with rich tribal traditions, ancient temples, archaeological sites, and natural landscapes, holds immense potential for technology-driven tourism development. The integration of digital technologies such as virtual reality (VR), augmented reality (AR), mobile applications, artificial intelligence (AI), and geographic information systems (GIS) has revolutionized the way cultural and heritage tourism is experienced and managed.

Digital platforms enable virtual tours of heritage sites like Sirpur and Bhoramdeo, allowing global audiences to explore Chhattisgarh's historical legacy remotely. Smart tourism applications provide real-time information, multilingual guides, online booking, and personalized travel experiences, enhancing tourist satisfaction. Social media and digital marketing play a vital role in showcasing local art forms, tribal festivals, folk dances, and handicrafts, thereby strengthening cultural identity and generating livelihood opportunities for local communities.

Moreover, technology aids in heritage conservation through digital documentation, 3D mapping, and data-driven preservation strategies. E-governance and smart infrastructure initiatives improve accessibility, safety, and sustainability in tourism destinations. Under the framework of Viksit Bharat 2047, the adoption of technology in Chhattisgarh's tourism sector fosters economic growth, cultural awareness, and global connectivity while ensuring the protection of indigenous heritage. Thus, technology emerges as a powerful catalyst in transforming Chhattisgarh into a sustainable and culturally vibrant tourism destination.

Keywords: Viksit Bharat 2047, Technology, Tourism Development, Culture and Heritage, Chhattisgarh

SOUVENIR

MLDC26029

Cultural Heritage Revival through Digital Storytelling: A Study on How Technology Reconnects the Youth with Traditional Values

DR. ANUPAMA JAIN
ASSIATANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF COMMERCE
MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR

Abstract:
The rapid expansion of digital technology and media platforms has transformed the ways in which cultural heritage is preserved, communicated, and experienced. The present study examines the role of digital storytelling in reconnecting the youth with traditional values and indigenous cultural heritage. Based on secondary data obtained from UNESCO, Ministry of Tourism (Government of India), Google Arts & Culture Reports, IAMAI Digital Consumption Surveys, and FICCI-KPMG media outlook, the paper evaluates how virtual museums, augmented and virtual reality experiences, cultural documentaries, animated folk narratives, and social media storytelling contribute to cultural revival. The findings reveal that youth cultural awareness and identity are significantly reinforced when cultural heritage is presented in visually engaging formats. Digital storytelling is observed to be an effective medium for cultural transmission, especially in bridging generational and geographical gaps.

Keywords: Digital Storytelling, Cultural Heritage, Youth Engagement, Virtual Tourism, Digital Preservation, Traditional Values

SOUVENIR

MLDC26030

Barriers to Entrepreneurial Innovation in Indian Self-Help Groups: A Socio-Economic Perspective (Focus on Chhattisgarh)

ANANYA SHARMA
RESEARCH SCHOLAR, MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE

DR. S.K. SHRIVASTAVA,
ASSISTANT PROFESSOR, MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE

Abstract:
Self-Help Groups (SHGs) have emerged as the cornerstone of rural financial inclusion in India, yet the transition from "survivalist" activities to "innovative entrepreneurship" remains a significant challenge. This research paper investigates the socio-economic barriers hindering entrepreneurial innovation among SHGs in Chhattisgarh, a state characterized by a high tribal population and unique rural livelihood frameworks like Bihan. Utilizing a socio-economic lens, the study analyzes how deep-seated structural issues —such as gendered "time poverty," limited digital literacy in tribal belts, and patriarchal control over household financial decisions—stifle the growth of innovative ventures.

The paper specifically explores the impact of recent policy shifts, including the Mahtari Vandan Yojana (2024–2026), to determine if direct cash transfers act as "nano-equity" for seed innovation or are merely absorbed by household consumption. Findings suggest that while the Bihan mission has successfully built a massive network of women's collectives, innovation is frequently blocked by a "credit-innovation gap," where loans are restricted to low-risk, traditional sectors like minor forest produce (MFP) collection rather than value-added manufacturing or digital services. The study concludes that for Chhattisgarh to achieve its "Lakhpati Didi" targets, policy must shift from providing micro-credit to fostering an innovation-centric ecosystem that integrates technical training, market-linked branding, and social support systems to alleviate the domestic burden on women entrepreneurs.

Keywords: SHG, Chhattisgarh, Bihan, Mahtari Vandan Yojana, Entrepreneurial Innovation, Socio-Economic Barriers, Tribal Entrepreneurship.

SOUVENIR

MLDC26031

Psychology of Money: Understanding the Emotional and Cognitive Factors Influencing Financial Decision-Making

DR. JAGANNATH SAHA[1]
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF COMMERCE,
VIVEKANAND MAHAVIDYALAYA, RAIPUR

SHRIYA PANDE[2]
RESEARCH SCHOLAR, DEPARTMENT OF COMMERCE,
VIVEKANAND MAHAVIDYALAYA, RAIPUR

Abstract:
This study examines the psychological factors influencing financial decision-making, with a focus on cognitive biases, heuristics, and emotional influences. Drawing on behavioural decision theory (Kahneman & Tversky, 1979), the research adopts a mixed-methods approach that combines survey data with an experimental design to analyse the relationships between personality traits, cognitive biases, and financial behaviour (Edmonds & Kennedy, 2017). The findings help explain why individuals often deviate from purely rational financial decision-making models.

Keywords: Behavioural, Cognitive Factors, Decision, Emotional, Financial, Psychology

SOUVENIR

MLDC26032

A Research Paper On A Study on Examine the Effect of Fintech Services on the Growth of Economy

DR. SANTOSH KUMAR UKE
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF COMMERCE
GOVT. DIGVIJAY AUTO. P.G. COLLEGE, RAJNANDGAON

DR. SURAJ PATEL
ASSISTANT PROFESSOR (GUEST), DEPARTMENT OF COMMERCE
GOVT. DIGVIJAY AUTO. P.G. COLLEGE, RAJNANDGAON

Abstract:

Introduction: The vision of Viksit Bharat aims to transform India into a developed, inclusive, and digitally empowered economy. Financial Technology (FinTech) has emerged as a major force in reshaping financial services through digital payments, online banking, mobile wallets, and digital lending. These innovations are playing a significant role in improving financial efficiency, expanding financial inclusion, and supporting economic growth.

Purpose: The main purpose of this study is to analyse the impact of FinTech services on economic growth and to examine their contribution toward achieving the goals of Viksit Bharat.

Research Methodology: This study is based on a descriptive and analytical research design using secondary data collected from RBI reports, government publications, journals, and online financial platforms. Trend and comparative analysis have been used to evaluate the growth and impact of FinTech services.

Research Findings: The study reveals that FinTech services such as UPI, digital banking, digital lending, and mobile payment systems have significantly improved access to financial services, especially for small businesses and rural populations. These services have reduced transaction costs, increased transparency, enhanced business efficiency, and promoted financial inclusion, thereby contributing positively to economic growth.

Conclusion: FinTech services are a powerful tool for achieving the objectives of Viksit Bharat. By promoting innovation, inclusion, and efficiency in the financial system, FinTech supports sustainable economic growth and strengthens India's position in the global digital economy.

Keywords: FinTech, Financial Inclusion, Digital Payments, Economic Growth, Viksit Bharat.

SOUVENIR

MLDC26033

Skills Development and Management Education

DR. SUCHITRA RATHI
HEAD & ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF MANAGEMENT
DURGA MAHAVIDYALAYA, RAIPUR (CG)

Abstract:
Skills development and management education is fundamental in preparing individuals for the complexities of the modern workforce and global economy. With rapid technological changes, globalization, and evolving labour markets, traditional education systems that emphasize theoretical knowledge alone are no longer sufficient. Skills development enhances employability, drives economic growth, and supports innovation by ensuring that Students can apply knowledge effectively in practical contexts. Management education plays a pivotal role in shaping future leaders who can adapt to disruptive environments, solve problems strategically, and foster organizational resilience.

Literature reveals that employability significantly improves when skills such as communication, critical thinking, teamwork, and digital literacy are integrated into the curricula. However, persistent skill gaps continue to challenge workforce readiness worldwide, with industries reporting shortages in both technical and soft skills among job applicants. In response, education systems are evolving to emphasize experiential learning, industry collaboration, and lifelong learning initiatives. Future prospects for skills development include integrating digital platforms, promoting policy reforms, and strengthening partnerships between academia and industry to address the need for emerging skills. This paper highlights the role of education in skill acquisition, examines challenges, and identifies avenues for enhancing skills development and management education to meet future economic demands. Role of NEP (2020) in skill development is also highlighted in brief.

Keywords: Challenges, Education, Management , Skills Development, skill gaps

SOUVENIR

MLDC26034

Agriculture and Food Security in Developed India (Viksit Bharat)

DR. ARCHANA S. MODAK
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF HUMANITIES
MAHANT LAXMINARYAN DAS COLLEGE, RAIPUR

Abstract:
Agriculture is a core part of India's economy and is crucial for achieving the goals of a developed India (Viksit Bharat). These goals include sustainable growth, adapting to climate change, ensuring that everyone receives sufficient nutritious food, and helping all people benefit. This study examines the changing role of agriculture, its current performance, the challenges it faces, food security policies, and possible solutions. Using official statistics and policy reviews, this study argues that changing how agriculture works is necessary to ensure that food is available, reachable, healthy, and stable for everyone in India. In addition to showing areas of progress, this paper also points out current problems and stresses the need for farming that can handle climate change, new technology, better markets, and strategies focused on nutrition.

Keywords: Foodgrain supply, Global Hunger Index, Food security

SOUVENIR

MLDC26035

Indian Knowledge System (IKS) and Vikshit Bharat 2047

DR. MONIKA PATEL
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE
DURGA MAHAVIDYALAYA RAIPUR (CG)

Abstract:
Indian Knowledge Systems (IKS) represent a comprehensive body of indigenous knowledge developed in India over thousands of years, encompassing philosophy, science, medicine, education, governance, and sustainable living. The national vision of Viksit Bharat 2047 aims to transform India into a developed, inclusive, and self-reliant nation by the centenary of its independence. This paper examines the relevance of Indian Knowledge Systems in achieving the objectives of Viksit Bharat 2047. It highlights the contribution of IKS to holistic education, ethical leadership, sustainable development, innovation, and cultural identity. The study argues that integrating traditional Indian wisdom with modern scientific and technological advancements can provide sustainable and context-specific solutions to contemporary challenges. The paper also discusses challenges in the integration process and suggests strategic measures for effectively incorporating IKS into policy, education, and research to support India's long-term developmental goals.

Keywords: Indian Knowledge Systems, Viksit Bharat 2047, NEP 2020, Sustainable Development, Education, Innovation

SOUVENIR

MLDC26036

Agriculture and Food Security

DR. RAJ KUMAR GAMBHIR
FORMER ASSISTANT PROFESSOR

Abstract:
As we all know, India is an agricultural country. Based on data from the 2023-24 fiscal year, agriculture and related sectors account for approximately 18% of India's GDP. This sector provides employment to approximately 58% of the population. Agriculture is considered the backbone of our country's economy, as it contributes to GDP and employment, as well as supporting important economic sectors like manufacturing and services. Agriculture is currently on a growth path, with record exports and modernization. India ranks among the world's top producers of rice, wheat, fruits, and vegetables, and is a world leader in milk production.

Despite all this, there are challenges that continue to hinder development. Most Indian farmers depend on small farms, and agriculture is not available year-round, leading to seasonal unemployment. On the other hand, even today a large area of agriculture is dependent on rainfall, to overcome which the need for efficient use of water is being felt. In an agricultural country, it is important that all citizens have access to adequate, safe and nutritious food at all times, so that they can live a healthy life. Food security does not only mean filling the stomach with food, but it also requires continuity in the qualities of quality, availability, accessibility, proper use and stability.

To achieve all these dimensions in India, steps like National Food Security Act, 2013 and Public Distribution System (PDS) have been taken.

Keywords: Agriculture, food, GDP

SOUVENIR

MLDC26037

MACHINE LEARNING IN CYBER SECURITY: STRENGTHENING DIGITAL INDIA FOR SUSTAINABLE GROWTH

MISS. SUMAN SHARMA
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE,
MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR

Abstract:
India is growing fast in the digital field under the Digital India program. Today, people use the internet for banking, payments, government services, education, and healthcare. These digital services help the country grow economically. However, the increase in online activities has also increased cybersecurity problems such as online fraud, phishing, hacking, and data theft. These problems can cause financial loss and reduce people's trust in digital systems. To solve these issues, Machine Learning (ML) is becoming an important tool in cybersecurity. Machine learning is a technology in which computer systems learn from data and improve their performance without being specially programmed. In cybersecurity, ML helps to find unusual activities, detect cyberattacks, and stop fraud at an early stage. It is commonly used to identify fake transactions, phishing emails, and suspicious network behavior. Machine learning also helps in continuous monitoring of digital systems. It reduces human mistakes and allows faster response to cyber threats. ML-based security systems protect important sectors such as banks, government websites, healthcare services, and digital payment platforms. This helps in building trust and supports long-term digital growth. At the same time, there are some challenges in using machine learning. Factors encompass a shortage of qualified professionals, the expense of technology, and issues surrounding data privacy. Consequently, effective planning, education, and robust cybersecurity legislation are essential. In summary, machine learning is vital for enhancing cybersecurity. Utilizing machine learning efficiently, India can enhance the security of its digital systems and advance towards Digital India and Viksit Bharat 2047 while ensuring sustainable growth.

Keywords: Machine Learning, Cyber Security, Digital India, Online Fraud, Phishing, Sustainable Growth, Viksit Bharat 2047

SOUVENIR

MLDC26038

Digital Transformation of Agriculture and Its Importance in Achieving Viksit Bharat 2047

DR. VAISHALI SARDE
ASSISTANT PROFESSOR
GOVT. J. YOGANADAM CHHATTISGARH COLLEGE

DR. PANKAJ SARDE
ASSOCIATE PROFESSOR
RUNGTA INTERNATIONAL SKILLS UNIVERSITY

Abstract:
The digital transformation of agriculture plays a vital role in realizing the vision of Viksit Bharat 2047. Indian agriculture continues to face issues such as low farm productivity, climate variability, limited access to timely information, and unstable farmer incomes. The integration of digital tools and advanced technologies—such as artificial intelligence, remote sensing, Internet of Things (IoT), data analytics, mobile-based advisory services, and online agricultural platforms—is reshaping the agricultural sector. These innovations support data-driven decision-making, precision farming, efficient use of inputs, and improved crop management. Digital agriculture also strengthens supply chains by enhancing market access, price transparency, and linkage to financial and insurance services. From a sustainability perspective, digital farming promotes efficient water use, reduces environmental stress, and improves resilience to climate change. Additionally, digital solutions encourage inclusive growth by empowering small and marginal farmers through access to knowledge, technology, and government support systems. This study highlights how digital transformation in agriculture contributes to productivity, sustainability, and rural economic development, thereby making it a crucial component in India's journey towards becoming a developed nation by 2047.

Keywords: Agriculture, Digital Farming, Digital Transformation, Viksit Bharat 2047

SOUVENIR

MLDC26039

Role of Artificial Intelligence in Clinical Healthcare Systems

DR. VIBHA DUBEY
HEAD AND ASSISTANT PROFESSOR
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE,
DURGA MAHAVIDYALAYA RAIPUR

Abstract:
The integration of Artificial Intelligence (AI) in healthcare is reshaping key areas such as clinical diagnosis, medical imaging, patient monitoring, and decision support systems. This paper provides an in-depth analysis of AI's role in modern healthcare systems, with a focus on foundational technologies like machine learning and deep learning. It examines how these technologies are applied in clinical settings, offering insights into their practical benefits and potential challenges. Additionally, the paper explores the architecture of AI systems, including data pipelines and infrastructure, which enable their effective implementation in healthcare. The advantages of AI in improving diagnostic precision, operational efficiency, and healthcare accessibility are discussed, alongside its limitations. The study also stresses the need for clear ethical, legal, and regulatory frameworks to guide AI's responsible deployment in healthcare. Finally, the paper suggests avenues for future research to further enhance AI's integration into healthcare, with the goal of improving patient care and overall system performance.

Keywords: Artificial Intelligence, Clinical Healthcare, Machine Learning, Deep Learning, Medical Imaging, Decision Support Systems, Data Analytics.

SOUVENIR

MLDC26040

A Study on Prospective Role of Dairy Products in Achieving Viksit Bharat 2047: An Integrative Framework for Economic Growth, Nutritional Security and Sustainable Development

MADHU KATARIA
RESEARCH SCHOLAR, MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE

DR. S.K.SHRIVASTAVA
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF COMMERCE
MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR

Abstract:
India is the largest milk producer in the world with a milk production of about 239 million tonnes (2023-24), and more than 8 crore (80 million) rural households being a part of it. It also accounts for 4.5–5% of the national Gross Domestic Product (GDP) and 24–25% of agricultural GDP, representing the largest dairy-based agribusiness sector. In the context of the Government of India's vision of Viksit Bharat 2047—a vision towards making India a developed, high-income, inclusive and sustainable economy by 2047—dairy figures as a means across several national development goals in the Government of India 2047 vision document. Our contribution is to develop a holistic, conceptual framework that synthesizes recent policy roadmaps, production data and sectoral considerations to analyze the potential of dairy to contribute to the following five pillars:(1) economic growth, value-addition; (2) nutritional security and health; (3) rural livelihood diversification and women's empowerment; (4) sustainability and climate resilience; and (5) innovation, skills and digital transformation. Based on NDDB's Vision 2047 strategy, White Revolution 2. Through broad-based consultations and a review of global 0 initiatives and peer-reviewed literature, the study anticipates that by 2047, the dairy sector will contribute 8-10% to the national GDP, have 10-15% of the share in global dairy trade, support 12 crore households, and convert 50% of milk into value-added products. Policy implications highlight cooperative-private complementarity, investment in infrastructure, quality standardization and farmer-centred financial instruments. This syntheses of analyses bridges gaps in available literature by aligning dairy sector reforms with multi-dimensional Viksit Bharat aspirations, providing a vision for stakeholders within the government, cooperatives and private sector.

Keywords: Viksit Bharat 2047, dairy sector development, milk production, rural livelihoods, nutritional security, value-addition, women empowerment, sustainability, cooperative sector, policy framework.

SOUVENIR

MLDC26041

Role of FinTech in Education Loans and Financial Inclusion: A Case Study of Chhattisgarh

MRS. REEMA VERMA
RESEARCH SCHOLAR, ANJANEYA UNIVERSITY

Abstract:
The increasing cost of higher education has made education loans a crucial instrument for ensuring equitable access to learning opportunities, particularly for students from economically and socially disadvantaged backgrounds. However, traditional banking institutions often impose rigid eligibility criteria, collateral requirements, and lengthy procedures that restrict access to formal credit. In this context, Financial Technology (FinTech) has emerged as a transformative force in the education loan ecosystem by leveraging digital platforms, alternative credit assessment models, and streamlined loan processing systems. This paper examines the role of FinTech in promoting financial inclusion through education loans with special reference to the state of Chhattisgarh.

The study is descriptive and analytical in nature and is based on secondary data collected from government reports, Reserve Bank of India publications, academic literature, and policy documents. A contextual case study approach is used to analyze education loan initiatives and their potential integration with FinTech solutions in Chhattisgarh. The findings indicate that FinTech-enabled education lending improves accessibility, reduces transaction costs, shortens approval timelines, and supports first-generation learners and students from rural and marginalized communities. State-supported interest-subsidy schemes, when combined with FinTech platforms, can further enhance outreach and transparency.

The paper concludes that FinTech plays a significant role in strengthening financial inclusion by democratizing access to education finance. For states like Chhattisgarh, strategic collaboration between government agencies and FinTech institutions, along with investments in digital infrastructure and financial literacy, can substantially improve higher education participation and long-term socio-economic development.

Keywords: FinTech, Education Loans, Financial Inclusion, Digital Lending, Higher Education, Chhattisgarh.

SOUVENIR

MLDC26042

The Impact of E-commerce on the Retail Market in Chhattisgarh.

DR. DHARMENDER SINGH
ASSISTANT PROFESSOR, GOVT.NEMICHAND JAIN COLLEGE, DALLIRAJHARA

DR. LALEE SHARMA
ASSISTANT PROFESSOR, GOVT.V.Y.T.PG AUTONOMOUS COLLEGE, DURG

Abstract:
This paper discusses the need to study the impact of e-commerce on the retail market in Chhattisgarh. In today's globalized world, internet connectivity is readily available, and technology is advancing rapidly. In this digital age, sellers can easily reach customers in any country through online platforms. This is why the rapid growth of e-commerce is impacting the retail market in Chhattisgarh. Many retailers in Chhattisgarh are facing fluctuations in their business turnover. This study is based on secondary data collected from various sources regarding the retail market in Chhattisgarh. The analysis reveals that traditional stores are facing the problem of declining profits as their margins are significantly affected by the shift of retail customers to online platforms. This study also presents various ideas and techniques for differentiating businesses and winning over customers to compete with e-commerce businesses. Traditional retailers should analyze the market forces that drive their businesses. Various types of additional services, product segmentation offers, discounts, etc., can improve traditional retail sales.

Keywords: Chhattisgarh, E-commerce, Growth, Internet, Retail Market

SOUVENIR

MLDC26043

Role of IoT and AI in Managing Heritage Tourism

KAVITA KUMARI BHARTI
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE
DURGA MAHAVIDYALAYA, RAIPUR

Abstract:
Heritage tourism plays a crucial role in preserving cultural identity, strengthening local economies, and fostering intercultural understanding by enabling visitors to engage with historical sites, traditions, and cultural assets. Despite its significance, heritage tourism management faces numerous challenges, including overcrowding, environmental degradation, inefficient utilization of resources, inadequate monitoring mechanisms, and limited visitor engagement. These issues threaten the long-term sustainability and conservation of heritage destinations worldwide. In recent years, the rapid advancement of digital technologies has positioned the Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI) as transformative solutions capable of addressing these challenges effectively. IoT technologies facilitate real-time data collection through interconnected sensors and smart devices that monitor environmental conditions, visitor movement, and infrastructure usage within heritage sites. When combined with AI-driven analytics, this data can be intelligently processed to enable predictive insights, automated decision-making, and adaptive management strategies. This article explores the role of IoT and AI in the management of heritage tourism by enhancing visitor experiences through personalization, ensuring sustainable site operations, improving conservation and preventive maintenance practices, and supporting data-driven planning and policy formulation. Furthermore, the study discusses current applications, benefits, and limitations associated with the adoption of these technologies, including issues related to cost, data privacy, and technological accessibility. Finally, the article outlines future research directions and emerging opportunities for integrating IoT and AI into smart heritage tourism frameworks, emphasizing the need for a balanced, ethical, and sustainable approach to technology-driven heritage management.

Keywords: Artificial Intelligence, Heritage, Internet of Things, Management, Tourism

SOUVENIR

MLDC26044

Platform Economy and Employment Generation in India

DR. ROOPAM JAIN HAZRA
ASSISTANT PROFESSOR
KALINGA UNIVERSITY, NAYA RAIPUR, C.G

Abstract:
The rapid expansion of the platform economy has emerged as a transformative force in India's labour market, reshaping traditional employment structures and creating new forms of work. Digital platforms such as ride-hailing services, food delivery apps, e-commerce marketplaces, freelance portals, and online service aggregators have significantly contributed to employment generation, particularly among youth, women, and informal sector workers. In the context of India's vision of Viksit Bharat 2047, the platform economy holds substantial potential to promote inclusive growth, flexibility, and entrepreneurial opportunities.

This study examines the role of the platform economy in employment generation in India, with a focus on its economic, social, and technological dimensions. It analyses how platform-based work has expanded income-generating opportunities by lowering entry barriers, enabling flexible work arrangements, and facilitating access to markets through digital infrastructure. The paper also explores the contribution of platforms to self-employment, gig work, and micro-entrepreneurship, especially in urban and semi-urban areas. By leveraging digital technologies such as artificial intelligence, data analytics, and mobile connectivity, platforms enhance productivity, match demand with supply efficiently, and optimize service delivery.

The paper adopts a descriptive and analytical approach, drawing on secondary data from government reports, policy documents, and existing empirical studies. It emphasizes policy initiatives such as the Code on Social Security, digital public infrastructure, and skill development programs aimed at enhancing the sustainability of platform-based employment. The study concludes that with appropriate policy support, regulatory clarity, and inclusive digital governance, the platform economy can play a pivotal role in generating productive, dignified, and sustainable employment, thereby contributing meaningfully to India's long-term economic development goals.

Keywords: Platform Economy; Gig Work; Employment Generation; Digital Platforms; Labour Market Transformation; Viksit Bharat 2047

SOUVENIR

MLDC26045

USING MACHINE LEARNING TO SECURE DIGITAL PAYMENTS AND E-GOVERNANCE SYSTEMS

MISS. SIMARAN CHANDRAKAR
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE,
MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR

Abstract:
India is leveraging digital technology to enhance public services and stimulate economic growth through initiatives like Digital Payments and E-Governance. Platforms offering online banking, UPI transactions, digital subsidies, and government portals have significantly streamlined processes for citizens, making them more efficient and accessible. But this quick uptake of digital technology has also escalated vulnerabilities to cyber threats such as online fraud, counterfeit transactions, identity theft, and system breaches. These risks, if unaddressed, can undermine public confidence in digital systems. To safeguard digital payments and e-governance infrastructure, Machine Learning (ML) has emerged as a crucial protective tool. ML enables computer systems to learn from historical data, autonomously identify patterns, and detect anomalies. In the context of digital payments, ML algorithms can monitor transactions in real time to flag suspicious activity, counterfeit accounts, and potential fraud. Within e-governance frameworks, ML aids in tracking user behavior, securing citizen data, and preventing unauthorized access. Operating continuously, ML systems process vast datasets with both speed and precision, minimizing human error and enabling faster responses to cyber incidents. The integration of ML-driven security allows banks and government agencies to enhance the safety, transparency, and dependability of their digital offerings. Nevertheless, deploying Machine Learning is not without obstacles. Challenges include significant technological costs, a shortage of skilled professionals, and concerns regarding data privacy. Addressing these issues will require targeted training programs, robust cybersecurity legislation, and the ethical application of technology. In summary, Machine Learning serves as a vital component in securing India's digital payment and governance ecosystems. By adopting ML effectively, India can foster more secure digital services, reinforce public trust, and advance toward the goals of a Digital India and a Viksit Bharat by 2047, anchored in sustainable and resilient development.

Keywords: Machine Learning, Digital Payments, E-Governance, Cyber Security, Online Fraud, Digital India, Viksit Bharat 2047

SOUVENIR

MLDC26046

Women Entrepreneurship and inclusive trade practices

MISS SARITA DEVI
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF COMMERCE
GOVT SHYAMA PRASAD MUKHERJEE COLLEGE SITAPUR , SARGUJA (C.G)

Abstract:
Women Entrepreneurship is an important contributor to economic growth , innovation and social development . Yet women –owned businesses continue to face structural barriers in accessing markets , finance and global trade opportunities.

Inclusive trade practices such as gender-responsive policies, digital trade platforms , capacity-building initiatives and equitable procurement systems play a crucial role in reducing this gaps . Inclusive trade practices can strengthen the competitiveness of women-led enterprises , enhance their participation in domestic and international value chains and promote gender –equitable economic outcomes .

Integrating gender considerations into trade policy not only empowers women entrepreneurs but also promotes sustainable inclusive and resilient economic growth.

Keywords: Entrepreneurship , businesses , barriers , global trade , inclusive , equitable procurement , International value chains , sustainable .

SOUVENIR

MLDC26047

Skill Development and Sustainable development of MSME for Viksit Bharat 2047

TRIPT KAUR
RESEARCH SCHOLAR,
MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE RAIPUR

DR DEWASHISH MUKHERJEE
PRINCIPAL,
MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR

Abstract:
This research study is undertaken to analyze the way forward to realize the objective of developed India. India is the most populous nation and is endowed with a strong working force. With such a huge strong population there comes big responsibility on us to strive in a planned way to be one of the developed nation in the world. In today's dynamic world and fast evolving technology coming up, the skill development becomes imperative for overall economy of the country. In this research study descriptive method is used to seek and determine the relation between skill development and sustainable MSME development. This study is based on secondary data, which is used to analyze the important "skill" factor responsible for sustainable development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). This paper also analyzes the investments of government on skill development programs and schemes in different states and union territories of India. The results shows that skills are prerequisite for success of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). It is required to ensure that an enterprise is able to survive and stand out in the competitive market. These skills can be acquired by a person. In this regards, government has started various programs and more needs to be done in order to achieve Viksit Bharat by 2047.

Keywords: Enterprises**,** Population**,** Skill Development, Sustainable development, Viksit Bharat 2047

SOUVENIR

MLDC26048

Technology Driven- Digital Museums: A New Gateway For Cultural Heritage In The Journey Towards VIKSIT BHARAT 2047

DHARMAKSHI SAHU
ASSISTANT PROFESSOR (HISTORY),
MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR

Abstract:
Technology has been an integral part of our lives since the last two decades. And we incorporate it in every aspect of our daily lives. With the new technological innovations and idea people continue to enhance their experiences in different spheres of life. One such example is 'Digital Museum'. A digital museum is an institution showcasing the cultural heritage in an interactive and impressive way, with the uses of recent technological innovations. Now the traditional museums are transforming into the digital museums. It is accompanying the changing demand of the time and society. This paper examines the scope of digital museums in India in the present era of technologies and innovations. It tries to understand the two different aspects, that is culture and technology contributing together towards better experiences of the visitors. Although, in the field of digitisation of museum, there have been many developments took place at global level, but still we need to consider it at national level as well. It contributes significantly to make ourselves compatible to the developing world.

Keywords: Cultural, Digital Museums, Heritage, Technology, Transforming

SOUVENIR

MLDC26049

Role of Digital Banking and Financial Technology in the GDP of Chhattisgarh

MR. RAKESH GONDWANI
RESEARCH SCHOLAR, MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE
PT. RAVI SHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR, C.G.

DR. SHWETA MAHAKALKAR
ASSISTANT PROFESSOR, DERPARTMENT OF COMMERCE
MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE

Abstract:
Digital Banking and financial technology has contributed a lot in solving the problems of financial inclusion through its facilities of making and receiving the payments online and this paper is the study of the role of digital banking and financial technology (FinTech) in the economic growth of Chhattisgarh, with a comparative reference to India's Gross Domestic Product (GDP). The study is based entirely on secondary data collected from government publications, RBI reports, Economic Surveys, and reliable statistical sources. Digital banking services such as UPI, mobile banking, internet banking, and FinTech-based digital lending have significantly transformed India's financial system by enhancing financial inclusion, transparency, and efficiency.

India's GDP has shown consistent growth over the past decade, supported by rapid digitalization of financial services. Chhattisgarh, though contributing a smaller share to national GDP, has demonstrated steady growth in its Gross State Domestic Product (GSDP). The increasing adoption of digital payments, Direct Benefit Transfer (DBT), and digital banking initiatives has positively influenced the state's economic activities, particularly in urban, rural and semi-urban areas.The analysis highlights that digital banking and FinTech support MSME development, reduce transaction costs, and promote inclusive economic growth. The paper concludes that strengthening digital infrastructure, improving digital literacy, and encouraging FinTech innovation can further enhance Chhattisgarh's contribution to India's GDP.

Keywords: Digital Banking, FinTech, GDP, GSDP, Chhattisgarh, Digital Economy

SOUVENIR

MLDC26050

Role of Digital Education in Enhancing Skill Development and Employability in Chhattisgarh

SUDHIR JAIN
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF COMMERCE
MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE,RAIPUR

Abstract:
This paper examines how digital education is helping to improve skills and job chances in Chhattisgarh. The state has launched several online learning programs and skill-building courses. These efforts are guided by the National Education Policy 2020. Now, mobile apps and online platforms are reaching students from tribal and rural areas. Programs like Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana are training young people for jobs. However, there are still many challenges. Internet access is not good in villages. Many teachers and students are not prepared for online learning. There is a big difference in digital access between city and rural areas. Still, early results are encouraging. Students are gaining new skills through mobile learning. Short courses are helping them get ready for work. This paper reviews current programs, their effects, and what still needs to be done. It uses data from research papers, government reports, and program evaluations. The results show that digital education can help to increase employment if the state improves internet access and provides more online training and programs to the students.

Key words: Digital education, Skill development, Employability, Digital divide, Mobile learning, NEP 2020

SOUVENIR

MLDC26051

A Comparative Study of Machine Learning Approaches for Early Detection of Diabetes

SHRADDHA DOYE
RESEARCH SCHOLAR, SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY
MATS UNIVERSITY, RAIPUR

DR. OMPRAKASH CHANDRAKAR
PROFESSOR AND HEAD, SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY,
MATS UNIVERSITY, RAIPUR

Abstract:
Diabetes mellitus has emerged as one of the most critical chronic diseases affecting global public health, with a rapidly increasing prevalence in developing countries such as India. Early diagnosis and timely intervention are essential to reduce long-term complications and healthcare costs. This research presents a comprehensive machine learning–based framework for early diabetes prediction using demographic, clinical, and lifestyle-related attributes. Multiple supervised learning algorithms, including Logistic Regression, Support Vector Machine, Random Forest, Decision Tree, and k-Nearest Neighbours, are implemented and evaluated. Data preprocessing techniques such as missing value handling, feature normalization, and feature selection are applied to enhance predictive accuracy. Model performance is assessed using accuracy, precision, recall, sensitivity, specificity, F1-score, and ROC–AUC metrics. Experimental results indicate that ensemble-based models outperform traditional classifiers, demonstrating higher robustness and reliability. The proposed framework highlights the effectiveness of machine learning techniques as decision- support tools for early diabetes prediction and can assist healthcare professionals and policymakers in implementing targeted preventive strategies and improving healthcare delivery.

Keywords: Diabetes Prediction, Machine Learning, Healthcare Analytics, Classification Models, Early Diagnosis

SOUVENIR

MLDC26052

Corporate Hospitals in Smart Cities: Catalysts for Socio-Economic Development and Healthcare Excellence in VIKSIT BHARAT 2047

MS. SHIVANGI DUBEY
RESEARCH SCHOLAR, MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR

Abstract:
India's Viksit Bharat 2047 vision envisions universal healthcare access through corporate hospitals integrated within smart city ecosystems. This research paper examines how corporate healthcare institutions leverage technology, public-private partnerships, and innovative service delivery models to drive socio-economic development while addressing health equity. Corporate hospitals in smart cities adopt artificial intelligence (AI) for diagnostics, telemedicine platforms reaching tier-2/3 cities, and precision medicine reducing treatment costs by 30-40%[1][2]. The Smart Cities Mission has catalyzed healthcare infrastructure development with ₹1.52 lakh crore investment creating synergies with medical institutions, generating 400,000 healthcare jobs and improving service accessibility for 100 million urban residents[2]. Integration of IoT-enabled patient monitoring, electronic health records (EHR), and blockchain-based insurance systems achieves 50% faster diagnosis and 25% cost reduction while ensuring data security[1]. Corporate hospitals in cities like Bangalore, Pune, and Hyderabad demonstrate scalable models: Narayana Health operates 1,200-bed facilities with 60% cost efficiency; Apollo Hospitals telemedicine reaches 5 million patients annually across rural areas[3]. These institutions create inclusive growth through skill development (training 50,000 healthcare workers annually), affordable care programs (subsidizing 30% of surgeries), and research collaborations advancing India's pharmaceutical leadership[2]. Challenges including regulatory harmonization, cybersecurity risks, and affordability gaps are addressed through policy recommendations emphasizing technology standardization, insurance integration, and capacity building. By 2047, corporate hospital networks within smart cities could contribute ₹5 lakh crore to healthcare GDP while achieving universal health coverage targets. The paper presents implementation strategies aligning corporate healthcare expansion with Viksit Bharat pillars—people-centric care, economic prosperity, environmental sustainability, and inclusive development.

Keywords: Corporate hospitals, smart cities, Viksit Bharat 2047, telemedicine, digital health, socio-economic development, universal health coverage, healthcare technology, inclusive growth

SOUVENIR

MLDC26053

New dimensions of journalism in developed India

DR. AMAN JHA
ASSISTANT PROFESSOR
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE,
DURGA MAHAVIDYALAYA RAIPUR

Abstract:
Journalism in developed India is experiencing rapid transformation due to advancements in digital technology, social media platforms, artificial intelligence, and data-driven reporting. Traditional forms of journalism such as print and broadcast media are evolving to integrate digital tools, mobile journalism, and citizen participation. These new dimensions have enhanced the speed, accessibility, and diversity of news dissemination, while also presenting challenges related to misinformation, ethical standards, and media credibility. In a developed India, journalism plays a vital role in strengthening democracy, promoting transparency, supporting development, and encouraging informed public discourse. This abstract highlights the emerging trends, opportunities, and responsibilities of journalism in shaping a progressive and informed Indian society.

Keywords: Journalism, Developed India, Digital Media, Social Media, Citizen Journalism, Media Ethics

SOUVENIR

MLDC26054

Artificial Intelligence in Agriculture and Food Security

MR. KHEMAN LAL SAHU
ASSISTANT PROFESSOR
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE,
DURGA MAHAVIDYALAYA RAIPUR

Abstract:
The implementation of Artificial Intelligence (AI) technologies is progressively transforming agricultural methods and enhancing global food security. By employing smart algorithms, such as machine learning and sophisticated data-driven models, AI enhances farming practices to be more efficient and sustainable. This research explores the technological and analytical dimensions of AI use in agriculture, concentrating on aspects like crop health monitoring, yield prediction, soil quality assessment, pest and disease control, and automated watering. It also examines the system structures and data processing procedures necessary for deploying AI-driven agricultural solutions. The document emphasizes the possible benefits of AI, such as enhanced agricultural output, improved resource management, ecological sustainability, and informed decision-making, while also discussing current obstacles like data integrity, technology access, and ethical issues. The research highlights the importance of strong governance, supportive policies, and regulatory supervision to guarantee responsible AI implementation. Furthermore, potential research avenues are recognized to strengthen the role of AI in developing sustainable and resilient food systems

Keywords: Artificial Intelligence; Smart Agriculture; Food Security; Machine Learning; Precision Farming; Sustainable Agriculture; Data Analytics.

SOUVENIR

MLDC26055

ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PREVENTING CYBER CRIME IN DIGITAL INDIA

ROSHNI V. PASHINE
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE,
MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR

Abstract:
India is becoming more digital under the Digital India programme. People use the internet for banking, online payments, education, healthcare, shopping, and government services. While digital technology makes life easier, it also increases the risk of cyber crimes such as online fraud, phishing, hacking, identity theft, and data misuse. These cyber crimes can cause financial loss and reduce public trust in digital systems. To control these problems, Artificial Intelligence (AI) is playing an important role in cyber crime prevention. Artificial Intelligence is a technology that allows computer systems to think, learn, and make decisions based on data. In cyber security, AI helps in identifying suspicious activities by studying user behaviour and system patterns. It can detect cyber attacks at an early stage and help in stopping them before serious damage occurs. AI is widely used to prevent online fraud and phishing. It can analyze emails, messages, and transactions to identify fake or harmful activities. AI-based systems work continuously and can process large amounts of data quickly, which is difficult for humans to do. This helps in faster response to cyber threats and reduces human errors. Artificial Intelligence also supports the protection of important digital infrastructure such as banking systems, government portals, healthcare platforms, and digital payment networks. This strengthens trust in digital services and supports safe digital growth. However, there are some challenges in using AI, such as high cost, shortage of skilled professionals, and data privacy concerns. Therefore, proper planning, training, strong cyber laws, and ethical use of AI are necessary. In conclusion, Artificial Intelligence plays a key role in preventing cyber crime in Digital India. By using AI responsibly, India can build a safe digital environment and move towards Viksit Bharat 2047 with sustainable development.

Keywords: Artificial Intelligence, Cyber Crime, Digital India, Cyber Security, Online Fraud, Phishing, Viksit Bharat 2047

SOUVENIR

MLDC26056

INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP: SHAPING THE FUTURE THROUGH ONLINE BUSINESS

SANJIKA TIWARI
RESEARCH SCHOLAR, GOVT. J YOGANANDAM CHHATTISGARH COLLEGE, RAIPUR

DR. TAPESH CHANDRA GUPTA
PRINCIPAL, GOVT. J YOGANANDAM CHHATTISGARH COLLEGE, RAIPUR

Abstract:
Innovation and entrepreneurship are widely recognized as the engines of economic growth and societal transformation in the digital era. The rapid expansion of the internet, mobile technologies, artificial intelligence, and digital platforms has revolutionized traditional business models and created unprecedented opportunities for online entrepreneurship. Online businesses are no longer limited to e-commerce; they now encompass digital services, education platforms, fintech, health-tech, content creation, and platform-based ecosystems. This research paper examines how innovation and entrepreneurship together are shaping the future of online business. It reviews key literature to understand the evolving nature of digital entrepreneurship, identifies major opportunities and challenges faced by online ventures, and analyses successful case studies from India to illustrate practical application. The study also proposes innovative online business ideas relevant to emerging markets. The findings suggest that innovation in technology, business models, and customer engagement is essential for entrepreneurs to remain competitive in an increasingly saturated digital marketplace. At the same time, challenges such as cybersecurity threats, regulatory complexity, digital trust, and intense competition require strategic management. The Indian online business landscape provides strong evidence of how digital entrepreneurship can drive inclusive growth, employment generation, and market expansion. The paper concludes that the future of entrepreneurship is inherently digital, and sustained innovation will be the key factor determining long-term success in online business ventures.

Keywords: Innovation, Entrepreneurship, Online Business, Digital Startups, E-commerce, India, Digital Economy

SOUVENIR

MLDC26057

Women Entrepreneurship and Digital Innovation: Bridging the Gender Gap in Chhattisgarh

RAHUL TIWARI
ASSISTANT PROFESSOR, MANAGEMENT DEPARTMENT
MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE,RAIPUR

Abstract:
This paper examines the impact of digital innovation on women's entrepreneurship in Chhattisgarh, India, and its role in reducing the gender gap in business ownership and economic participation. Using a mixed methodology of surveys, interviews, and secondary literature, the research identifies how digital tools – such as mobile technology, e-commerce, and online financial services – enable women entrepreneurs to access resources, markets, and business networks. The findings show that, although digital innovation creates new opportunities for women to start and expand enterprises, ongoing barriers related to digital literacy, infrastructure, social norms, and financial constraints continue to restrict full participation. The paper concludes by recommending digital education, supportive policies, and infrastructure development to enhance women's inclusion and entrepreneurial success in the digital economy.

Keywords: Women entrepreneurship, digital innovation, gender gap, Chhattisgarh, digital literacy, economic empowerment

SOUVENIR

MLDC26058

Learning of how theoretical Machine Learning concepts can be used to analyze, predict, and support Social Sustainability – Health Care Goals Specially Cancer effectively

PRIYANKA TIWARI [1]
RESEARCH SCHOLAR, KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

DR ANUPA SINHA [2]
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF CS
KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Abstract:
Socially sustainable healthcare prioritizes just access, premium care, and enduring wellness for all people. Among major global health challenges, cancer care requires effective mechanisms for early detection, accurate prediction, and informed decision-making to reduce mortality and social inequality. This study focuses on learning how theoretical machine learning concepts can be used to analyze, predict, and support social sustainability–oriented health care goals, with special emphasis on cancer care.

The paper examines core theoretical foundations of machine learning, including supervised and unsupervised learning, classification, regression, feature selection, and model evaluation, and discusses their relevance to cancer-related health data.

The study also highlights the importance of ethical, transparent, and fair machine learning approaches to ensure socially sustainable cancer care systems. By integrating machine learning theory with social sustainability principles, this work demonstrates how data-driven insights can support clinicians, health institutions, and policymakers in improving early detection, treatment planning, and inclusive cancer care. Overall, the study underscores the role of theoretical machine learning as a strong foundation for achieving sustainable and equitable health care goals.

Keywords: Machine learning, deep learning, regression, social sustainability goal, supervised learning, classification, unsupervised learning.

SOUVENIR

MLDC26059

Review on Skills Development & Education

ANSHIKA DUBEY
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF COMPUTER
GURUKUL MAHILA MAHAVIDYALAYA RAIPUR

Abstract:
For enhancing the employability in India, the skills development and education in India plays a key role. Skills development and education are the most serious component because it increases the value of employability where the demand for good skilled workers is on the rise (Dr. Rupali Saini, Ankit Chourasiya January- March, 2023). The economic performance of our country is concerned. India is still lagging because of many types of problems such as unemployment, illiteracy,

poverty, medical infrastructure etc. Youth play so much important role in achieving prosperity of economic of the country. In the present scenario, due to lack of technical knowledge and skills it is found that most of the youth being educated are facing severe unemployment problem (Maroof Maqbool & Mahmood Ahmad Khan March-2019). So for removing the unemployment , it is necessary that skills should be developed and provide better education. By this each and every person will get the opportunity for being employed.

Keywords: Skill Development, Education, Employability, Skills.

SOUVENIR

MLDC26060

Growth of Life Insurance in India: An Analysis of Premium Trends, Penetration and Density

DR. YULENDRA KUMAR RAJPUT [1]
PRINCIPAL & RESEARCH GUIDE
AGRASEN MAHAVIDYALAYA, PURANI BASTI, RAIPUR

VIDHI CHHABRA [2]
RESEARCH SCHOLAR, AGRASEN MAHAVIDYALAYA, PURANI BASTI, RAIPUR

Abstract:
The insurance sector is a vital component of economic development as it promotes financial security and long-term savings. This study examines the growth and performance of the life insurance sector in India by analyzing trends in life insurance premiums, insurance penetration, and insurance density over the period. The study is based on secondary data collected from published reports and official statistics.

The analysis indicates a continuous rise in total life insurance premiums, reflecting the expanding size of the industry and increased consumer participation. Although the Life Insurance Corporation of India continues to hold a dominant position, the private sector has demonstrated faster growth, contributing to enhanced market competitiveness. Insurance penetration in India shows a fluctuating trend, with a noticeable increase during the pandemic period due to heightened risk awareness, followed by a marginal decline in recent years. In contrast, insurance density exhibits a consistent upward trend, suggesting an increase in per capita premium expenditure rather than widespread coverage.

The findings highlight that while the life insurance sector in India has grown significantly in value, overall insurance penetration remains modest. The study emphasizes the need for inclusive insurance strategies, improved financial literacy, and affordable products to expand coverage and strengthen the role of insurance in economic development.

Keywords: Life Insurance, Insurance Penetration, Insurance Density, Life Insurance Premium, Insurance Sector in India

SOUVENIR

MLDC26061

Deep Learning–Based Rice Disease Detection in Chhattisgarh for Sustainable Agriculture Development

NEHA TIKARIHA,
RESEARCH SCHOLAR (IT)
AMITY UNIVERSITY, RAIPUR (CG)

Abstract:
Chhattisgarh is widely recognized as one of India's major rice-producing regions. Rice serves as a primary source of income and food security for local farming communities in Chhattisgarh. However, rice crops are often affected by some health issues such as diseases, pest infestations and nutrient deficiencies, which reduces yield when not detected at an early stage. Traditional approaches for diagnosing crop problems based on visual observation by farmers, expert knowledge and laboratory analysis, which are time-consuming and costly.

However late detection of crop disease and excessive use of pesticides harms the crop and affect the productivity. Therefore, timely identification of crop diseases is critical for achieving long-term agricultural sustainability in the region.

This study proposes a deep learning–based method for early-stage crop health detection in rice crops using leaf images collected from rice fields in the Raipur district. The system analyzes images of rice leaves to identify early disease symptoms that are very difficult to observe with the nude eyes. techniques like image preprocessing and data augmentation are used to improve model performance under real field conditions, such as changes in lighting, background, and leaf orientation.

Early detection of rice health problems enables the farmers to take timely decision and actions, which reducing unwanted uses of pesticides and preventing the spread of infection. This Method helps the farmers to improve rice production, minimize input costs and reduces environmental impact. The experimental results demonstrate that the proposed image-based deep learning tool is beneficial for rice farmers in Raipur and contributes to sustainable agricultural development.

Keywords: deep learning, Crop disease detection, Leaf image analysis , Sustainable agriculture, Chhattisgarh.

SOUVENIR

MLDC26062

Digital Inclusion in Rural Development Towards Viksit Bharat

DR. SWATI SHARMA
ASSISTANT PROFESSOR & HOD, DEPARTMENT OF ECONOMICS
GOVT. PT. SHYAMACHARAN SHUKLA COLLEGE, DHARSIWA, RAIPUR

Abstract:
India has taken the ambitious idea of Viksit Bharat and has made it a goal to become a developed country by 2047. This idea is backed by the phenomenal growth of India in all sectors and its strong digital infrastructure supporting the growth. Digital inclusion is one of the key backbones of this infrastructure. Digital inclusion means equal and simultaneous access to technology, digital skills, and the internet to every citizen. India has made huge progress in this as there are over 886 million internet users with 397 million users from urban area and 488 million from rural area. This shows that rural areas have more users compared to urban areas.

This fast digital inclusion is powered by low-cost data plans, increased coverage, and affordable smart phones. Digital inclusion has several benefits for rural area like improved education, healthcare service, economic growth, job opportunities, easy access to government services, etc. However, it also has some adverse effect like high implementation cost, digital dependence, cybersecurity risk, cultural and social access, language barriers and difficulties for elder and disabled people. The digital inclusion though fast lacks any proper digital literacy, making technology seem irritable and hard for rural areas. The increasing cybercrimes like scams, frauds and learning problems make rural people feel that digital advancement is a barrier rather than a facility.

The government has also noticed this issue, and its pivotal role in hindering the vision of Viksit Bharat. It is now offering digital literacy training, awareness programs, increasing support for local language, and designing an assessable partnership for helping rural people in this digital inclusion. The strengthening of digital inclusion in rural areas will help in the development of rural communities, promoting sustainable development, improving the standard of living, reducing inequality, and ensuring that rural population is not left behind in the digital era as this leveraging technology sets an inclusion towards Viksit Bharat.

Keywords: Cybercrimes, Digital Inclusion, Digital Literacy, Sustainable Development, Viksit Bharat.

SOUVENIR

MLDC26063

Empowering Self-Help Groups through Digital Transformation: Leveraging Technology for Inclusive Economic Growth in India under the Vision of Viksit Bharat 2047

TRIPTY DEWANGAN
RESEARCH SCHOLAR: GOVT.DIGVIJAY SNATKOTTAR SWASHASHI MAHAVIDYALAYA, RAJNANDGAON

DR. ASHANAND MAKHIJA
DEPARTMENT OF COMMERCE, GOVT, SHIVNATH SCIENCE COLLEGE, RAJNANDGAON

DR. H. S. BHATIA
DEPARTMENT OF COMMERCE, GOVT.DIGVIJAY SNATKOTTAR SWASHASHI MAHAVIDYALAYA, RAJNANDGAON (C.G.)

Abstract:
Indias Viksit Bharat 2047 plan is all about growth that includes everyone, stays sustainable, and uses technology a lot. It mean, it pushes for that kind of economic push forward. Self Help Groups, or SHGs, they have become really important at the local level for things like reducing poverty, empowering women, and starting up businesses in rural areas.

When digital stuff is added like mobile banking or digital payments, e commerce, and even online training for skills, these groups start to change a lot. They turn into something that drives growth for more people, not just a few.

This paper looks at how technology in SHGs affects society and the economy, and how they help meet the goals of Viksit Bharat 2047. It uses some descriptive ways and analytical ones to check out income from these groups, how they bring in financial inclusion, and keeping livelihoods going strong for the people involved.

The results show that bringing in technology really helps boost income, build up savings, and get better access to markets. That makes SHGs even more key in Indias bigger plan for development over the long haul. It seems like without that tech, a lot of this might not happen as well, though I am not totally sure on every detail. Some parts get a bit complicated when you think about rural spots specifically.

Keywords: Self-Help Groups, Viksit Bharat 2047, Technology, Economic Growth, Financial Inclusion, Women Empowerment.

SOUVENIR

MLDC26064

Skills Development and Education: Integrating Neural Networks for Enhanced Learning Outcomes and Employability

DEEPSHIKHA SHARMA
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE
GURUKUL MAHILA MAHAVIDYALAYA, RAIPUR

AMITA TELANG
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE
GURUKUL MAHILA MAHAVIDYALAYA, RAIPUR

Abstract:
In the rapidly evolving digital era, the focus of education has shifted from knowledge acquisition to comprehensive skills development, which is essential for employability, innovation, and societal growth. Traditional education models, heavily reliant on uniform curricula and manual assessment, often fail to address individual learning needs, skill gaps, and the demands of modern industries. To overcome these limitations, Artificial Intelligence (AI), specifically Neural Networks (NNs), has emerged as a transformative tool in education. Neural networks, inspired by the structure and functionality of the human brain, can analyse large volumes of educational data, recognize learning patterns, and provide intelligent, adaptive solutions. This paper explores the integration of neural networks in education to enhance learning outcomes, personalized learning, skill assessment, and employability. By leveraging data-driven insights, NNs can customize learning content, identify individual strengths and weaknesses, and predict skill gaps, thereby facilitating targeted interventions. Furthermore, AI-based career guidance systems can align learners' capabilities with industry requirements, enhancing workforce readiness. The paper also examines the advantages, challenges, ethical concerns, and future prospects of implementing neural network–based educational systems. Integrating neural networks in skills development and education holds the potential to create adaptive, inclusive, and future-ready learning environments, bridging the gap between academia and industry while promoting sustainable economic growth. This study highlights the role of AI as a critical enabler in transforming education into a dynamic, learner-centric, and employment-oriented ecosystem.

Keywords: Skills Development, Education, Neural Networks, Artificial Intelligence, Personalized Learning, Employability, Learning Outcomes

SOUVENIR

MLDC26065

Green Innovation and Start-up Culture: Evidence from Indian Entrepreneurs

DR. ASHOK KUMAR JHA
HEAD & ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF MANAGEMENT
VIVEKANAND MAHAVIDYALAYA, RAIPUR, (C.G.)

Abstract:
This study examines the role of green innovation in shaping the start-up ecosystem in India. With sustainability gaining prominence, Indian entrepreneurs increasingly adopt green technologies and eco-friendly business models to create competitive advantage. This research explores the drivers, challenges, and impacts of green innovation on start-up performance. Using mixed methods—survey data from 150 Indian start-ups and in-depth interviews with founders—this study highlights key insights into how green innovation is reshaping entrepreneurial culture in India. Findings reveal that while regulatory support and market opportunities motivate green innovation, challenges related to finance and technology adoption persist. The paper concludes with policy recommendations for strengthening India's green start - up landscape.

Keywords: Green Innovation, Start-up Culture, Sustainability, Indian Entrepreneurs, Eco-enterprises.

SOUVENIR

MLDC26066

Integrating Computer Education for Skills Development in the Education System

DR. DEEPTI VERMA
ASSISTANT PROFESSOR
SHRI SHANKARACHARYA INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES, RAIPUR

Abstract:
This study examines the role of green innovation in shaping the start-up ecosystem in India. With sustainability gaining prominence, Indian entrepreneurs increasingly adopt green technologies and eco-friendly business models to create competitive advantage. This research explores the drivers, challenges, and impacts of green innovation on start-up performance. Using mixed methods—survey data from 150 Indian start-ups and in-depth interviews with founders—this study highlights key insights into how green innovation is reshaping entrepreneurial culture in India. Findings reveal that while regulatory support and market opportunities motivate green innovation, challenges related to finance and technology adoption persist. The paper concludes with policy recommendations for strengthening India's green start - up landscape.

Keywords: Green Innovation, Start-up Culture, Sustainability, Indian Entrepreneurs, Eco-enterprises.

SOUVENIR

MLDC26067

Economic Impact of Machine Learning–Based Cancer Diagnosis in India's Healthcare System

MRS. RUKMANI DIGRASKAR
RESEARCH SCHOLAR, KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

DR. ANUPA SINHA
ASSISTANT PROFESSOR, DEPTMENT OF COMPUTER SCIENCE
KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Abstract:
The revolution incidence of cancer in India presents a relevance economic load on distinctive, families, and the national healthcare system. Machine Learning (ML)–based diagnostic technologies have the potential to enhance early detection, reduce false positives, optimize workflow efficiency, and cut healthcare costs. In this paper evaluate the economic impact of merging Machine Learning-based cancer diagnosis in India, focusing on accessibility expansion, long-term health outcomes, productivity gains, and cost savings.

It identifies the opportunities and financial obstacles, quantifies potential savings from early detection and decrease treatment costs. Findings suggest that effective deployment of Machine Learning diagnostics can contribute to improve resource allocation, reducing cancer-related expenditures, and support India's commitment to equitable and sustainable healthcare.

Keywords: Cancer Diagnosis, Machine Learning, Economic Impact, Cancer Diagnosis, Healthcare Economics, Cost Efficiency, India, Healthcare Policy

SOUVENIR

MLDC26068

Skill development in education

DR. PRAGATI DUBEY
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF EDUCATION,
DURGA MAHAVIDYALAYA RAIPUR

Abstract:
Skill development in education plays a crucial role in preparing students for real-life challenges and the rapidly changing job market. Modern education is no longer limited to academic knowledge; it also focuses on developing essential skills such as communication, problem-solving, critical thinking, creativity, teamwork, and digital literacy. These skills help learners become confident, independent, and employable individuals. Integrating skill-based learning into the curriculum bridges the gap between theory and practice, making education more meaningful and practical. Skill development also supports personal growth, enhances adaptability, and promotes lifelong learning. Therefore, education systems must emphasize skill-oriented training to create a capable, innovative, and future-ready generation.

Keywords: Skill Development, Education, Employability, Life Skills, Holistic Development

SOUVENIR

MLDC26069

Impact of Corporate Governance in Company Law Regime: A Key for Viksit Bharat@2047

DR. ASHISH PRATAP SINGH
ASSISTANT PROFESSOR,DEPARTMENT OF LAW
ISBM UNIVERSITY RAIPUR(C.G.)

Abstract:
The vision of Viksit Bharat @ 2047 aspires to transform India into a fully developed, inclusive, and globally competitive economy by the centenary year of its independence. Achieving this ambitious goal requires not only economic growth but also robust institutional frameworks that promote transparency, accountability, and sustainable development. Corporate governance, embedded within the company law regime, plays a pivotal role in ensuring that corporations act as responsible engines of national development.

Keywords: Skill Development, Education, Employability, Life Skills, Holistic Development

SOUVENIR

MLDC26070

SKILL DEVLOPMENT AND EDUCATION IN INDIA

DEVSHREE VERMA[1],
ASSISTANT PROFESSOR, GURUKUL MAHILA MAHAVIDYALAYA, KALABARI RAIPUR

K.K. HARRIS[2]
PROFESSOR AND HEAD, DEPARTMENT OF ZOOLOGY
GOVT. D.B. GIRLS P.G. COLLEGE, RAIPUR

Abstract:
Skill development programmes implement in India. The aim of study is to investigate the existing literature for the skill development programmes the demographic proportion in India by makes them more skilled and employable. This literature study is to review the various initiatives taken by Government of India, programmes conducted through public and private partnership, ways to increase the employability skills, challenges faced for the success of the programme. The importance of skill development in India, the role of institutions, skill development as a necessity in the beginning of technical changes, an effective measure to empower women in the country and the need of integrating skill development with education.

KEYWORDS: EDUCATION , EMPLOYABLE, SKILL DEVLOPMENT, TECHNICAL CHANGE

MLDC26071

ई-गवर्नेंस एवं डिजिटल सार्वजनिक सेवाएँ

डॉ. जी. डी. एस. बग्गा [1]
प्राध्यापक (वाणिज्य), चंदुलाल चंद्राकर शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, धमधा

नूतन देशमुख [2]
शोधार्थी, भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाई नगर

सारांश (Abstract):-
वर्तमान वैज्ञानिक उपलब्धियाँ मानव जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं। वर्तमान युग लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था का युग है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश की जनता की आकांक्षाओ को पूर्ण करना आज की शासन व्यवस्था का प्रमुख दायित्व है। अपने इस दायित्व को पूर्ण करने के लिए सार्वजानिक सेवाओं को डिजिटल स्वरुप में परिवर्तित किया जाता है तथा शासन व्यवस्था ई-गवर्नेंस का रूप धारण करती है। इस समय इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल एप, नागरिक वेबसाइट आदि की मदद से शासकीय योजनाओं एवं कार्यों का अधिकतम एवं श्रेष्टतम क्रियान्वयन किया जाता है।

मुख्य शब्द (Keywords): ई-गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन पोर्टल, नागरिक वेबसाइट, डिजिटल प्लेटफॉर्म

SOUVENIR

MLDC26072

छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय: चुनौतियां एवं संभावनाएं

नमिता सिंह
शोधार्थी, महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

सारांश (Abstract):-
यह शोध पत्र छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय की वर्तमान स्थिति, प्रमुख चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। राज्य का वार्षिक दूध उत्पादन लगभग 23-25 लाख टन है, जो देश के कुल उत्पादन का मात्र 1.5% है। 2019-20 में जहां राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 406 ग्राम प्रतिदिन थी, वहीं छत्तीसगढ़ में यह केवल 152 ग्राम प्रतिदिन रही। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ (देवभोग ब्रांड), अमूल और मदर डेयरी जैसे प्रमुख संस्थान राज्य में सक्रिय हैं।

अध्ययन में चारे की कमी, नस्ल सुधार की आवश्यकता, आधारभूत संरचना की अपर्याप्तता, कोल्ड चेन व्यवस्था की समस्याएं, बिचौलियों की भूमिका और पशु स्वास्थ्य सेवाओं की सीमाओं जैसी प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही, गोधन न्याय योजना, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, सहकारी मॉडल (अमूल से प्रेरित), महिला सशक्तिकरण और डिजिटलीकरण जैसे अवसरों की पड़ताल की गई है।

विकसित भारत 2047 के संदर्भ में, यह शोध स्थापित करता है कि आधारभूत संरचना में निवेश, वैज्ञानिक नस्ल सुधार, चारा प्रबंधन, डिजिटल तकनीक का समावेश और सशक्त सहकारी संरचना के माध्यम से छत्तीसगढ़ दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर और निर्यात सक्षम राज्य बन सकता है। यह परिवर्तन न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, बल्कि रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, पोषण सुरक्षा और सतत विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायक होगा। शोध का निष्कर्ष है कि समेकित नीतिगत हस्तक्षेप और बहुआयामी विकास रणनीति के माध्यम से छत्तीसगढ़ का दुग्ध क्षेत्र विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

मुख्य शब्द (Keywords): दुग्ध उत्पादन, छत्तीसगढ़, विकसित भारत 2047, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकारी मॉडल, गोधन न्याय योजना, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता

SOUVENIR

MLDC26073

विकसित भारत की दिशा में प्रौद्योगिकी-संचालित उद्यानिकी व्यवसाय: कृषि, खाद्य सुरक्षा एवं सतत आर्थिक विकास का मूल्यांकन (छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ में)

सत्येन्द्र [1]
शोधार्थी, महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़

डॉ. शांतनु पॉल [2]
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य विभाग)
महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़

सारांश (Abstract):-
विकसित भारत 2047 का राष्ट्रीय संकल्प भारतीय कृषि व्यवस्था में एक संरचनात्मक परिवर्तन की मांग करता है, जिसका उद्देश्य निर्वाह खेती से हटकर प्रौद्योगिकी-समर्थित कृषि-व्यवसाय की ओर बढ़ना है। छत्तीसगढ़ राज्य, अपनी विविध कृषि-जलवायु परिस्थितियों के साथ, इस परिवर्तन में केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में पिछले 11 वर्षों (2014-15 से 2024-25) के दौरान उद्यानिकी फसलों (फल, सब्जियां, मसाले) के उत्पादन, उत्पादकता और क्षेत्रफल में हुए परिवर्तनों का सांख्यिकीय मूल्यांकन करना है। यह अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है, जो उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से प्राप्त किए गए हैं। आंकडों के विश्लेषण के लिए चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR), प्रवृत्ति विश्लेषण (Trend Analysis) और वर्णनात्मक सांख्यिकी का प्रयोग किया गया है।सांख्यिकीय विश्लेषण दर्शाता है कि पिछले एक दशक में राज्य के उद्यानिकी उत्पादन में 2.06ः की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि (CAGR) दर्ज की गई है। कुल उत्पादन वर्ष 2014-15 के 85.95 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 105.47 लाख मीट्रिक टन हो गया है। आर्थिक व्यवहार्यता के विश्लेषण में पाया गया कि पपीता (लाभ-लागत अनुपात 2.89) और टमाटर (लाभ-लागत अनुपात 2.45) जैसी फसलें धान की तुलना में अत्यधिक लाभदायक हैं। यद्यपि दीर्घकालिक प्रवृत्ति सकारात्मक है, परंतु अध्ययन का एक चिंताजनक पहलू यह है कि वर्ष 2022-23 (112.45 लाख टन) के बाद से उत्पादन में लगातार दो वर्षों (2023-24 और 2024-25) में गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट जलवायु परिवर्तन और मौसमी अस्थिरता का स्पष्ट संकेत है। शोध पत्र निष्कर्ष निकालता है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संरक्षित खेती, डिजिटल कृषि (एग्री-स्टैक), और प्रसंस्करण आधारित मूल्य श्रृंखला का एकीकरण अनिवार्य है।

मुख्य शब्द (Keywords): विकसित भारत 2047, छत्तीसगढ़, उद्यानिकी-व्यवसाय, CAGR, विश्लेषण, छत्तीसगढ़ विजन, सतत विकास।

SOUVENIR

MLDC26074

भारत 2047: सतत् आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में पर्यटन उद्योग की भूमिका

सोमा गोस्वामी
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग),
महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर

सारांश (Abstract):-
भारत एक विविधताओं युक्त देश है जो अपनी संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटन उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करता है, जो GDP का लगभग 6.5% है और 4.3 करोड़ नौकरियों को सपोर्ट करता है। भारत सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं, जैसे कि PRASHAD, देखो अपना देश, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, और SWADESH 2.0

इन पहलों का उद्देश्य पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना और स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाना है। 2023 में, भारत में 9.24 मिलियन विदेशी पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया, जो 2022 की तुलना में 43.5% की वृद्धि है। विदेशी पर्यटकों के आगमन से 2.3 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा आय हुई।

भारत का पर्यटन उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, और 2034 तक GDP में इसका योगदान 7.6% होने का अनुमान है। यह सेक्टर रोजगार के अवसर पैदा करने और स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हेल्थ, वेलनेस, एडवेंचर और नीश टूरिज्म जैसे नए आयाम पर्यटन क्षेत्र को और सशक्त बना रहे हैं। सरकार की पहलों और निवेश से यह क्षेत्र 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

मुख्य शब्द (Keywords): विकसित भारत , पर्यटन, रोजगार, आर्थिक विकास,अर्थव्यवस्था

SOUVENIR

MLDC26075

परंपरा एवं प्रौद्योगिकी के मध्य सेतु के रूप में साहित्य

प्रज्ञा चौधरी
शोधार्थी

डॉ. मालती तिवारी
प्राध्यापक एवं विभाग अध्यक्ष राजनीति विज्ञान
शासकीय महा प्रभुवल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़

सारांश (Abstract):-
प्रस्तुत शोध पत्र परंपरा एवं प्रौद्योगिकी के मध्य सेतु के रूप में साहित्य के अंतर्संबंधो का गहन विश्लेषण करते हुए यह प्रतिपादित करता है कि साहित्य मात्र शब्दों का संचयन नही बल्कि मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास की वह धुरी है जो अतीत की थाती और भविष्य की संभावनाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करती है। समकालीन वैश्विक परिदृश्य में जहां एक ओर सहस्रों वर्षों पुरानी परंपराएं हमारी सांस्कृतिक पहचान और नैतिक बोथ का आधार है, वहीं दूसरी ओर द्रुत गति से विकसित होती प्रौद्योगिकी मानव जीवन के बाह्य स्वरूप को पुनर्गठित कर रही है, जिसके फल स्वरुप अक्सर परंपरा और आधुनिकता के बीच एक वैचारिक और संवेदनात्मक अंतराल उत्पन्न हो जाता है। यह शोध इस मौलिक प्रश्न की पड़ताल करता है कि साहित्य किस प्रकार एक जीवंत सेतु बनकर प्राचीन मूल्यो, लोक अनुभवो, और सांस्कृतिक धरोहरों को आधुनिक तकनीक के शुष्क एवं यांत्रिक ढांचे में ढालकर उन्हें प्रासंगिक बनाए रखता है।

शोध के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि साहित्य जहां परंपराओं को रूढ़िवादिता की जकड़न से मुक्त कर उनमें प्रगतिशील चेतना का संचार करता है, वहीं दूसरी ओर वह प्रौद्योगिकी के मानवीकरण की प्रक्रिया को भी संपन्न करता है ताकि विज्ञान और तकनीक केवल भौतिक उन्नति का साधन न रहकर मानवीय संवेदनाओं के संवाहक बन सके। मुद्रण क्रांति से लेकर वर्तमान के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इबुक्स और फॉर डिजिटल मीडिया के युग तक, साहित्य ने अपनी अभिव्यक्ति के माध्यमों को तकनीक के अनुरूप परिवर्तित किया है, किंतु उसकी अंतर्वस्तु में सदैव वही शाश्वत मानवीय प्रश्न विद्यमान रहे हैं जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। विश्लेषणात्मक पद्धति का आश्रय लेते हुए यह शोध यह भी रेखांकित करता है कि कैसे समकालीन साहित्यकार पौराणिक आख्यानों और लोक-परंपराओं को नवीन तकनीकी विधाओं के माध्यम से वैश्विक मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे स्थानीय और वैश्विक का भेद मिट रहा है। निष्कर्षत यह शोध पत्र सिद्ध करता है कि साहित्य ही वह एक मात्र माध्यम है जो परंपरा की नैतिकता और प्रौद्योगिकी की गतिशीलता को एक सूत्र में पिरोकर एक ऐसी संतुलित सभ्यता के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है जहां मनुष्य अपनी जड़ों को खोए बिना भविष्य के शिखर की और अग्रसर हो सके।

मुख्य शब्द (Keywords): साहित्य, परंपरा, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक धरोहर, वैश्विक परिदृश्य, मानवीय संवेदना, डिजिटल मीडिया, प्रगतिशील चेतना, तकनीकी विधायेँ।

SOUVENIR

MLDC26076

छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा चुनौतियां एवं संभावनाएं

डॉ युलेंद्र कुमार राजपूत [1]
प्राचार्य,अग्रसेन महाविद्यालय पुरानी बस्ती रायपुर (छग)

ओंकार प्रसाद साहू [2]
शोधार्थी, अग्रसेन महाविद्यालय पुरानी बस्ती रायपुर (छग)

सारांश (Abstract):-
नवीकरणीय ऊर्जा सतत एवं स्थाई विकास की मूल आधारशिला मानी जाती हैं। वर्तमान परिदृश्य में ऐसी नवाचार तकनीकों का विकास एवं उपयोग करना आवश्यक है जो पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा निर्मित कर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करें। इनका प्रमुख उद्देश्य प्रदूषण में कमी, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित विदोहन कर आर्थिक व सामाजिक विकास को गति प्रदान करना है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं, विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्र जो अधिकांशतः पहाड़ो एवं वनाच्छादित क्षेत्र में स्थित है, जहां पर ऊर्जा पहुंच सीमित है। नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए स्थाई विकल्प बन सकता है। यह अध्ययन छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों, संभावनाओं और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का विश्लेषण करता है। नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर, जल विद्युत और बायोमास इन क्षेत्रों में न केवल ऊर्जा सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, बल्कि स्थानीय रोजगार सृजन, आजीविका संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य जो भारत का प्रमुख कोयला उत्पादन राज्य है जहां नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता सीमित हैं, विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्र जहां राज्य का लगभग 32% आबादी निवास करते हैं। इस क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा के लिए बुनियादी ढांचे की कमी, भू-अधिग्रहण की समस्या, जलवायु परिवर्तन, नक्सलवाद और नीतिगत कमियां प्रमुख चुनौतियां हैं। इसके बावजूद भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 GW अक्षय ऊर्जा हासिल करना है जिसमें अनुसूचित क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं का क्रियान्वयन स्थानीय आवश्यकताओं, सामाजिक संरचना एवं सामुदायिक सहभागिता के साथ किया जाए तो अनुसूचित क्षेत्र में ऊर्जा आवश्यकता एवं सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्य शब्द (Keywords): नवीकरणीय, सौर ऊर्जा, अनुसूचित क्षेत्र, सतत विकास, पर्यावरण, संरक्षण ।

SOUVENIR

MLDC26077

विकसित भारत के निर्माण में हिन्दी भाषा : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं समकालीन प्रासंगिकता

प्रीतम कुमार दास
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी)
महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर (छ. ग.)

सारांश (Abstract):-

भारत विविधताओं का देश है। यहाँ थोड़े अंतराल पर ही भौगोलिक परिस्थितियों में उल्लेखनीय परिवर्तन परिलक्षित होता है। जैसे-जैसे लोग स्थान बदलते हैं, वैसे-वैसे उनकी संस्कृति, जीवन-शैली और भाषिक अभिव्यक्ति में भी परिवर्तन आ जाता है। प्राचीन कहावत भी है- "चार कोस पर पानी बदले, आठ कोस पर वाणी।" विकसित भारत की संकल्पना में हिन्दी भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है। हिन्दी भाषा न केवल सर्वाधिक व्यापक जनभाषा है, बल्कि यह सामाजिक एकता, लोकतांत्रिक सहभागिता, शिक्षा, प्रशासन, ज्ञान-विज्ञान, डिजिटल सशक्तिकरण और सांस्कृतिक पहचान का सशक्त माध्यम भी है। सन् 2047 में भारत अपनी स्वतंत्रता की गौरवपूर्ण शताब्दी का उत्सव मनाएगा। इस अवसर तक भारत को एक विकसित, आत्मनिर्भर, समावेशी एवं वैश्विक नेतृत्वकर्ता राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य राष्ट्रीय संकल्प के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसे 'विकसित भारत-2047' की संकल्पना कहा जा रहा है। इस विकास यात्रा में आर्थिक प्रगति, तकनीकी नवाचार, औद्योगिक विस्तार, सामाजिक न्याय और सुशासन के साथ-साथ भाषा की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाषा केवल संप्रेषण का साधन न होकर विचार, संस्कृति, चेतना और राष्ट्रीय अस्मिता की संवाहक होती है।

यह शोधपत्र विकसित भारत 2047 की परिकल्पना में हिन्दी भाषा की भूमिका का ऐतिहासिक, संवैधानिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। साथ ही हिन्दी के समक्ष विद्यमान चुनौतियों, संभावनाओं तथा नीतिगत समाधानों पर भी विस्तार से विचार करता है। निष्कर्षतः यह अध्ययन प्रतिपादित करता है कि हिन्दी भाषा को यदि ज्ञान, शासन और तकनीक की भाषा के रूप में सुनियोजित ढंग से विकसित किया जाए, तो वह विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

मुख्य शब्द (Keywords): विकसित भारत 2047, हिन्दी भाषा, भाषा और विकास, शिक्षा, प्रशासन, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय एकता।

SOUVENIR

MLDC26078

विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का भौगोलिक वितरण एवं सतत विकास

डॉ. श्वेता शर्मा
सहायक प्राध्यापक, भूगोल
महंत लक्ष्मीनारायण दास कॉलेज, रायपुर, छत्तीसगढ़

सारांश (Abstract):-
भारत 21वीं सदी के मध्य तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के साथ " विकसित भारत 2047 " की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में अग्रसर है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में ऊर्जा क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा भाग जीवाश्म ईंधनों से पूरा होता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन, पर्यावरण प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। ऐसी स्थिति में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन—जैसे सौर, पवन, जल, बायोमास और भू-तापीय ऊर्जा—भारत के सतत विकास के लिए एक व्यवहारिक एवं दीर्घकालिक समाधान प्रस्तुत करते हैं।

प्रस्तुत शोध-पत्र में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के भौगोलिक वितरण, उनकी क्षेत्रीय संभावनाओं, तथा आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। साथ ही, यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि किस प्रकार तकनीक, नीति और भूगोल के समन्वय से नवीकरणीय ऊर्जा विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों—ऊर्जा आत्मनिर्भरता, हरित अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण—को प्राप्त करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

मुख्य शब्द (Keywords): विकसित भारत 2047, नवीकरणीय ऊर्जा, भौगोलिक वितरण, सतत विकास, ऊर्जा आत्मनिर्भरता

SOUVENIR

MLDC26079

डिजिटल इंडिया और होटल उद्योग: रायपुर (छत्तीसगढ़) का अध्ययन विकसित भारत–2047 के संदर्भ में

लोकेश कुमार साहू
शोधार्थी (वाणिज्य)
महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

डॉ. श्वेता महाकालकर
सहायक प्राध्यापक, महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर

सारांश (Abstract):-
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य देश को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। इस कार्यक्रम का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर विशेष रूप से देखा गया है, जिसमें होटल एवं आतिथ्य उद्योग का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। होटल उद्योग न केवल पर्यटन को बढ़ावा देता है, बल्कि रोजगार सृजन, स्थानीय आर्थिक विकास एवं विदेशी मुद्रा अर्जन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य रायपुर (छत्तीसगढ़) में होटल उद्योग पर डिजिटल इंडिया के प्रभाव का अध्ययन करना तथा विकसित भारत–2047 की परिकल्पना के संदर्भ में इसके योगदान का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन वर्ष 2020 से 2025 की अवधि पर केंद्रित है, जिसमें होटल उद्योग में अपनाई गई डिजिटल तकनीकों—जैसे ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म, UPI एवं डिजिटल भुगतान प्रणाली, डिजिटल मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट सिस्टम (HMS) तथा डेटा-आधारित सेवाओं—के प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। डेटा संग्रह के लिए द्वितीयक स्रोतों जैसे पर्यटन विभाग, होटल एसोसिएशन रिपोर्ट्स, सरकारी प्रकाशन एवं समाचार पत्रों के साथ-साथ स्थानीय होटलों से प्राप्त सीमित प्राथमिक जानकारी का उपयोग किया गया है। अध्ययन के निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि रायपुर के होटल उद्योग में डिजिटल अपनाने की प्रवृत्ति में निरंतर वृद्धि हुई है। ऑनलाइन बुकिंग की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि, डिजिटल भुगतान माध्यमों—विशेषकर UPI—का व्यापक उपयोग तथा डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से ग्राहक आधार का विस्तार इस परिवर्तन के प्रमुख संकेतक हैं। डिजिटलीकरण के परिणामस्वरूप होटल उद्योग की परिचालन दक्षता में सुधार हुआ है, ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि हुई है तथा सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर हुई है। इसके साथ ही, डिजिटल तकनीकों के कारण रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं, जैसे आईटी सपोर्ट, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा प्रबंधन एवं ऑनलाइन ग्राहक सेवा से संबंधित भूमिकाएँ। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह अध्ययन दर्शाता है कि डिजिटल इंडिया समर्थित होटल उद्योग ने रायपुर की स्थानीय GDP में सकारात्मक योगदान दिया है। होटल व्यवसाय की उत्पादकता में वृद्धि, पर्यटन गतिविधियों में विस्तार और पारदर्शी वित्तीय लेन-देन ने क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है। यद्यपि डिजिटल साक्षरता की कमी, साइबर सुरक्षा जोखिम तथा छोटे होटलों की तकनीकी सीमाएँ जैसी कुछ चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं, फिर भी उचित प्रशिक्षण, नीतिगत समर्थन एवं डिजिटल अवसंरचना के विकास से इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है। अंततः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि डिजिटल इंडिया और होटल उद्योग एक-दूसरे के पूरक हैं। रायपुर के होटल उद्योग का डिजिटलीकरण न केवल वर्तमान आर्थिक विकास को गति दे रहा है, बल्कि विकसित भारत–2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, होटल प्रबंधन तथा शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द (Keywords): डिजिटल इंडिया, होटल उद्योग, रायपुर, विकसित भारत–2047, ऑनलाइन बुकिंग, डिजिटल भुगतान

SOUVENIR

MLDC26080

स्मार्ट सिटीज़ और शहरी विकास : ऐतिहासिक भारतीय संस्कृति एवं स्वदेशी ज्ञान प्रणाली का पुनरुत्थान

आशा गुप्ता [1]
शोधार्थी, महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर

डॉ. श्वेता महाकालकर [2]
सहायक प्राध्यापक, महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर

सारांश (Abstract):-
भारत का स्मार्ट सिटी मिशन आधुनिक शहरी विकास को एक नई दिशा देने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें ऐतिहासिक भारतीय संस्कृति और स्वदेशी ज्ञान प्रणाली को शामिल किया जा सकता है। जहाँ वैश्विक स्मार्ट सिटी मॉडल मुख्य रूप से डिजिटल तकनीक और डेटा आधारित शासन पर केंद्रित हैं, वहीं भारत की प्राचीन नगर व्यवस्थाएँ—जैसे मोहनजोदड़ो, वाराणसी और जयपुर—स्थायित्व, सामुदायिक सहभागिता और पर्यावरणीय संतुलन के सिद्धांतों पर आधारित रही हैं। यह शोध पत्र पारंपरिक पारिस्थितिकीय ज्ञान और स्थानीय वास्तुकला के माध्यम से टिकाऊ और समावेशी शहरी भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करता है। स्वदेशी योजनाओं में जल, भूमि और जलवायु के साथ परस्पर संबंधों को महत्व दिया गया है जो औपनिवेशिक शहरीकरण की तकनीकी प्रवृत्तियों को चुनौती देते हैं। शोध में भारतीय परिप्रेक्ष्य से लिए गए उदाहरणों के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि कैसे विरासत-संवेदनशील अवसंरचना, स्थानीय सामग्रियों का उपयोग और सांस्कृतिक परिदृश्य स्मार्ट सिटी डिज़ाइन में एकीकृत किए जा सकते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल शहरी कल्पनाओं का उपनिवेशीकरण समाप्त करता है, बल्कि सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ भी मेल खाता है विशेष रूप से सांस्कृतिक संरक्षण, समावेशी समुदायों और जलवायु अनुकूलन से संबंधित लक्ष्यों के साथ।

मुख्य शब्द (Keywords): स्मार्ट सिटी, शहरी विकास,ऐतिहासिक भारतीय संस्कृति,स्वदेशी ज्ञान प्रणाली, पारंपरिक शहरी नियोजन

SOUVENIR

MLDC26081

प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्यटन विकास और चुनौतियां

जगदीश प्रसाद खटकर
शोध छात्र, कलिंगा विश्वविद्यालय नवा रायपुर

डॉ ए राजशेखर
(प्राध्यापक)शोध निदेशक, विभागाध्यक्ष -भूगोल
कलिंगा विश्वविद्यालय नवा रायपुर

सारांश (Abstract):-
पर्यटन आधुनिक युग में भौगोलिक तथा सांस्कृतिक जीवन पद्धति को देखने का अवसर प्रदान कर जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने तथा पर्यटकों को लुभावने वाला नई प्रवृत्ति बन रही है ,वर्तमान दौर में प्रौद्योगिकी के विभिन्न माध्यमों ने पर्यटन के विभिन्न आयामों को ज्यादा अधिक व्यक्तिगत ,स्मार्ट, सतत्, सस्टेनेबल बनाकर वैश्विक पहचान दिलाई है प्रौद्योगिकी के विभिन्न माध्यमों जैसे एआई ,इंटरनेट, डाटा ,ब्लॉकचैन,आन साइट अनुभव, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरनेट आफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग,वीआर,एआर से पर्यटन क्षेत्र में विभिन्न इवेंट प्रचार- प्रसार व वर्कशॉप इत्यादि में तीव्र गति से बदलाव आया है जिससे पर्यटन स्थलों की श्रेणी, सुविधा यात्रा मार्ग, ऑन साइट अनुभव ,मीटिंग व कैंप टूर ,पैकेज टूर, बुकिंग, पर्यटन सूचना केंद्र,टोलफ्री नं.,डॉक्यूमेंट्री ,प्रोमोज , गिजिट्स, आर्टिफिशियल वेबसाइट, टूरिज्म मैप, 24 घंटे सेवा, पंजीकृत ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स, होटल ,गाइड सेवाएं, साइकिल और बाइक राइड इवेंट की जानकारी व समाधान उपलब्ध हुआ है प्रौद्योगिकी के माध्यम से नए स्थलों की पहचान, समुदायों की भागीदारी, आर्थिक लाभ तथा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहर स्थलों का संरक्षण के प्रति जागरूकता होमस्टे ,रात्रि पर्यटन (नोक्टर्नल टूरिज्म), ट्राइबल टूरिज्म, इको टूरिज्म, वाईल्डलाइफ टूरिज्म ,वाटर टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म तथा धार्मिक दर्शनीय स्थल टूरिज्म की आपार संभावनाएं बढ़ी है जिससे जीडीपी में पर्यटन का योगदान बढ़ रहा है तथा प्रौद्योगिकी माध्यमों से वैश्विक स्तर पर बदलते बजारों की जरूरत के अनुरूप ढालने तथा प्रतिस्पर्धा बढ़ने में उनके उपयोग के प्रति जिम्मेदारी भी बढ़ी है, दुर्गम स्थलों पर सुगम पहुंच में बाधा, बजट में कम प्रावधान, पर्यटन से पारिस्थितिकी पर्यटन जन चेतना का अभाव ,धोखाधड़ी, फीडबैक रिपोर्ट की नकारात्मकता, डाटा उपयोगिता, गोपनीयता,साइबर सुरक्षा, पर्यावरण अवनयन व दबाव,ओवर टूरिज्म ,नैतिकता एवं सामाजिक मुद्दे हैं तथा इनसे जुड़े खतरों को कम करने की अंतर्दृष्टि प्रदान करना है क्योंकि पर्यावरण अनुकूल समन्वित विकास लक्ष्य की पूर्ति में पर्यटन उद्योग सहायक हो तब ज्यादा सार्थक बनेगा

यह शोध पत्र प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्यटन विकास और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, प्रस्तुत शोधपत्र द्वितीय आंकड़ों पर आधारित हैl

मुख्य शब्द (Keywords): प्रौद्योगिकी साधन, पर्यटन आयाम,सस्टेनेबल, सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण ,अवनयन

SOUVENIR

MLDC26082

छत्तीसगढ़ में एमएसएमई में महिला उद्यमिता और तकनीकी नवाचार: एक अध्ययन

सुमन धृतलहरे
शोधार्थी, महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर

डॉ. श्वेता महाकालकर
सहायक प्राध्यापक, महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर

सारांश (Abstract):-
छत्तीसगढ़ राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिला उद्यमशीलता के उत्थान का यह अनुसंधान विशेष रूप से बिहान दीदी कार्यक्रम के अंतर्गत यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) एवं फिनटेक्नोलॉजी समाधानों के व्यावसायिक प्रभावों की गहन पड़ताल प्रस्तुत करता है। उद्यम पंजीकरण प्रणाली के अनुसार राज्य में 56,254 महिला संचालित उद्यम औपचारिक रूप से पंजीकृत हैं, जबकि स्वयंसहायता समूहों सहित अनौपचारिक क्षेत्र में 3.25 लाख से अधिक सक्रिय महिला उद्यमी कार्यरत हैं। रायपुर संभाग में लगभग 29,500 पंजीकृत एवं एक लाख से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों की उपस्थिति दर्ज की गई।

मिश्रित अनुसंधान पद्धति के अंतर्गत रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर जिलों से चयनित 250 महिला उद्यमियों पर आधारित प्राथमिक सर्वेक्षण कार्यान्वित किया गया। R सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर में बहु-चर प्रतिगमन विश्लेषण से प्रमाणित हुआ कि डिजिटल वित्तीय सेवाओं के स्वीकार्यता से औसतन 55% व्यावसायिक आय वृद्धि ($\beta=0.42$, $p<0.01$) एवं 42% व्यवसाय विस्तार प्राप्त हुआ। रायपुर शहरी क्षेत्र में 65% UPI उपयोगिता दर के विरुद्ध ग्रामीण पट्टियों में 48% स्वीकार्यता दर्ज हुई। स्वयंसहायता समूह ग्रामीण रोजगार सृजन में 70.84% योगदान प्रदान कर रहे हैं।

राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 के तहत 50 लाख तक कोलैटरल मुक्त ऋण सुविधा एवं 30-55% पूँजीगत अनुदान उपलब्ध कराया गया। प्रमुख अवरोधक: डिजिटल प्रशिक्षण अभाव (55%), ग्रामीण 4G संपर्क विषमता (30%)। निष्कर्ष दर्शाते हैं कि प्रौद्योगिक हस्तक्षेप छत्तीसगढ़ को विकसित भारत@2047 का प्रतिरूप स्थापित करने में सक्षम बनाते हैं।

नीतिगत सुझाव: वार्षिक 1,000 बिहान दिदियों हेतु त्रैमासिक डिजिटल साक्षरता शिविर, ग्रामीण दूरसंचार अवसंरचना हेतु सब्सिडी, हकदारशक प्लेटफार्म का 33 जिलों में विस्तार। अनुसंधान परिणाम राष्ट्रीय प्रतिकृति हेतु उपयुक्त हैं।

मुख्य शब्द (Keywords): महिला उद्यमशीलता, डिजिटल वित्तीय सेवाएँ, बिहान दीदी, UPI स्वीकार्यता, एमएसएमई विकास, छत्तीसगढ़ आर्थिक मॉडल, विकसित भारत 2047

SOUVENIR

MLDC26083

स्मार्ट सिटी अवधारणा के अंतर्गत हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा सामाजिक उद्यमिता के नवाचारी प्रयासों का अध्ययन (प्रोजेक्ट शक्ति)

सुषमा पटले
पीएच.डी. शोधार्थी
बिजनेस स्टडीज विभाग, मेट्स विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.), भारत

डॉ. प्रियंका बोस
सहायक प्राध्यापक एवं शोध मार्गदर्शक
बिजनेस स्टडीज विभाग, मेट्स विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.), भारत

सारांश (Abstract):-
स्मार्ट सिटी अवधारणा का उद्देश्य शहरी विकास के साथ-साथ सामाजिक समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है इस संदर्भ में यह अध्ययन हिंदुस्तान युनिलीवर लिमिटेड द्वारा संचालित प्रोजेक्ट शक्ति के अंतर्गत किए गए सामाजिक उद्यमिता के नवाचारी प्रयासों का अध्ययन करता है। इस अध्ययन में द्वितीयक आंकड़ों, शोधलेखो, कंपनी रिपोर्ट्स का विश्लेषण किया गया है अध्ययन में वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग कर प्रोजेक्ट शक्ति की संरचना, कार्य प्रणाली और सामाजिक प्रभावों की विवेचना की गई है। यह अध्ययन विशेष रूप से प्रोजेक्ट शक्ति द्वारा महिला सशक्तिकरण आजीविका सृजन और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से स्मार्ट सिटी के सामाजिक आयाम को मजबूत करता है तथा ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र की महिलाओं को सूक्ष्म उद्यमी के रूप में विकसित कर आर्थिक आत्मनिर्भर वह डिजिटल सहभागिता को बढ़ावा देता है साथ ही, इन महिलाओं द्वारा स्वच्छता उत्पादों स्वास्थ्य जागरूकता तथा दैनिक उपभोग वस्तुओं का वितरण कर स्मार्ट सिटी के सामाजिक एवं आर्थिक स्तंभों को सशक्त किया गया है।

अध्ययन का निष्कर्ष यह दर्शाता है कि प्रोजेक्ट शक्ति एक प्रभावी सामाजिक उद्यमिता मॉडल है जो स्मार्ट सिटी अवधारणा के अंतर्गत सामाजिक उद्यमिता तथा नवाचार के सतत् विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सिद्ध होता है।

मुख्य शब्द (Keywords):- उद्यमिता, अवधारणा, सामाजिक, नवाचार, ग्रामीण, आत्मनिर्भरता, वर्णनात्मक।

MLDC26084

विकसित भारत 2047 के निर्माण में कौशल विकास एवं शिक्षा की भूमिका: एक शोधात्मक अध्ययन

डॉ. किरण अग्रवाल
विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग,
महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर

सारांश (Abstract):-
विकसित भारत 2047 की परिकल्पना भारत को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और तकनीकी रूप से एक सशक्त एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षा और कौशल विकास की भूमिका अत्यंत निर्णायक मानी जाती है। वर्तमान समय में वैश्विक प्रतिस्पर्धा, तकनीकी परिवर्तन और रोजगार की बदलती प्रकृति ने मानव संसाधन को राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया है। केवल साक्षरता या डिग्री आधारित शिक्षा अब पर्याप्त नहीं रह गई है, बल्कि व्यावहारिक, तकनीकी और जीवनोपयोगी कौशलों का विकास भी आवश्यक हो गया है। यह शोध पत्र विकसित भारत 2047 के संदर्भ में शिक्षा और कौशल विकास के महत्व पर आधारित अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान, सोच और चरित्र का विकास करती है, वहीं कौशल विकास उसे रोजगार योग्य और आत्मनिर्भर बनाता है। शोध में नई शिक्षा नीति 2020, तकनीक आधारित शिक्षा, डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा सरकारी कौशल विकास योजनाओं की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही, शोध पत्र में शिक्षा और कौशल विकास से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों—जैसे क्षेत्रीय असमानता, डिजिटल सुविधाओं की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव और उद्योग-शिक्षा के बीच समन्वय की कमी—का भी विश्लेषण किया गया है। अंततः यह शोध इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यदि शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाए, कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए और तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जाए, तो विकसित भारत 2047 का सपना साकार किया जा सकता है। यह अध्ययन नीति निर्माताओं, शिक्षकों और विद्यार्थियों—सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द (Keywords): विकसित भारत 2047, शिक्षा, कौशल विकास, तकनीक, रोजगार, मानव संसाधन

MLDC26085

कौशल विकास में योग की भूमिका

डॉ. लक्ष्मीकांत साहू
दर्शनशास्त्र विभाग
महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर

सारांश (Abstract):-
वर्तमान युग में कौशल विकास किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत, सामाजिक एवं व्यावसयिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। बदलती जीवनशैली, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और मानसिक तनाच के कारण युवाओं में कौशल विकास प्रभावित हो रहा है। योग एक प्राचीन भारतीय जीवन-पद्धति है, जो शरीर, मन और आत्मा के समन्वय पर आधारित है। यह शोध-पत्र कौशल विकास में योग की भूमिका का विश्लेषण करता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि योग मानसिक एकाग्रता, आत्माविश्वास, तनाव प्रबंधन, निर्णय क्षमता तथा कार्यक्षमता को बढ़ाकर कौशल विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। योग को यदि शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जाए तो युवा वर्ग अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बन सकता है।

मुख्य शब्द (Keywords): योग,कौशल विकास,युवा,मानसिक स्वास्थ्य,आत्मनिर्भरता

SOUVENIR

MLDC26086

विकसित भारत में पत्रकारिता के आयाम

राम प्रसाद दुबे
सहायक प्राध्यापक, पत्रकारिता विभाग
महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय,रायपुर

सारांश (Abstract):-
अपने रोजमर्रा के जीवन के आमदिन की कल्पना कीजिए। दो लोग आसपास रहते है। और लगभग रोज मिलते है, कभी बाजार में, कभी राह चलते ओर कभी एक दूसरे के घर पर। भेंट से पहले के कुछ मिनट की उसकी बातचीत पर ध्यान दीजिए। हर दिन उनका पहला सवाल क्या होता है " क्या हालचाल है " या 'कैसे है'? या फिर क्या समाचार है। रोजमर्रा के इन सहज प्रश्नों में उपरी तौर पर कोई विशेष बात नहीं दिखाई देती। इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और सोचिए। इसमें आपकों एक इच्छा दिखाई देगी। नया ताजा समाचार जानने की कहने की जरूरत नहीं है कि अपने आसपास की चीजों, घटनाओं और लोगो के बारे में ताजा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है। उसमें जिज्ञासा का भाव प्रबल होता है। यहीं जिज्ञासा पत्रकारिता का मूल तत्व है। वहीं हम सूचनाएं या समाचार क्यों जानना चाहते है। दरअसल सूचनाएं अगला कदम तय करने में हमारी सहायता करती है। वहीं समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रूचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगो पर प्रभाव पड़ रहा हो।

SOUVENIR

MLDC26087

ई गवर्नेंस और डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं

डॉ राकेश कुमार चंद्राकर
सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान,
महंत लक्ष्मी नारायण दास महाविद्यालय

सारांश (Abstract):-
21वीं सदी को डिजिटल युग कहा जाता है आज सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है शिक्षा स्वास्थ्य व्यापार और संचार के साथ-साथ शासन व्यवस्था भी डिजिटल परिवर्तन से अछूती नहीं रही है पारंपरिक शासन प्रणाली में कागजी कार्यवाही समय की बर्बादी भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी जैसी समस्याएं लंबे समय से बनी हुई थी इन्हीं समस्याओं के समाधान के रूप में ई गवर्नेंस की अवधारणा विकसित हुई है। गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को सरल सुलभ और नागरिक अनुकूल बनाना है डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं नागरिकों को घर बैठे सरकारी सुविधा उपलब्ध करा रही है जिस समय धन और श्रम की बचत होती है भारत जैसे विशाल और विविधता पूर्ण देश में हीई.गवर्नेंस का महत्व और भी बढ़ जाता है यह कहा जा सकता है कि ई गवर्नेंस डिजिटल की सहायता से मानवहस्ति की कला सृजन क्षमता को और भी विकसित किया है।क्षमता अंतर्निहित हो सकती है लेकिन यह हर संभव काम में इंसान की सहायता कर रही है सरकार की डिजिटल सेवाओं से तकनीकी रूप से मानव जाति के हर कम में सहायक सिद्ध हो रही है जिससे सरकार सार्वजनिक सेवाओं को जन-जन तक पहुंचने में अपने आप को सक्षम अनुभव कर रही है।

SOUVENIR

MLDC26088

कृत्रिम बुद्धिमता और कौशल विकास विकसित भारत के महत्वपूर्ण आयाम

डॉ.किरण तिवारी
सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग
महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय रायपुर.

सारांश (Abstract):-
शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमता और शैक्षिक प्रौद्योगिकी का समाकलन एवं कौशल विकास एक महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है। पारंपरिक शिक्षक तरीको की तुलना में कृत्रिम बुद्धिमता एवं शैक्षिक प्रौद्योगिकी का मंच व्यक्तिगत शिक्षण, स्वचालित मूल्यांकन और वास्तविक समय में प्रतिक्रिया प्रदान करने की क्षमता रखते है। जो शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाते है। इस शोध का उद्धेश्य कृत्रिम बुद्धिमता तथा शैक्षिक प्रोघौगिकी के समाकलन तथा कौशल विकास के प्रभावों और लाभों और उससे जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण करना है। साथ ही यह अध्ययन तकनीकी, शैक्षिक, नैतिक पहलुओं पर प्रकाश डालता है। जिसमें डेटा की गोपनीयता और शिक्षकों की भूमिका इत्यादि महत्वपूर्ण है। परिणाम स्वरूप यह शोध कृत्रिम बुद्धिमता और शैक्षिक प्रौघोगिकी तथा कौशल विकास के समाकलन के लिए आवश्यक रणनीतियों सुधारो की और पहचान करता है। जिससे शिक्षा प्रणाली अधिक समावेशी,प्रभावशली और भविश्योंमुखी बनाया जा सके। उसे कौशल विकास से जोड़ा जा सके तथा विकसित भारत की कल्पना साकार हो सके।

मुख्य शब्द (Keywords):कृत्रिम बुद्धिमता, शैक्षिक प्रौघौगिकी, शिक्षा तकनीक, डेटा गोपनीयता उच्चशिक्षा नैतिकता, शैक्षिक नवाचार तथा कौशल विकास

SOUVENIR

MLDC26089

निरंतरता का एक लक्ष्य: विकसित भारत @ 2047

डॉ. युलेंद्र कुमार राजपूत (शोध-निर्देशक)
अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर

एकता ठाकुर (शोधार्थी)
अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर

सारांश (Abstract):-
स्वतंत्र भारत के 100 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व उसे विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि निरंतर प्रगति और देश के हर वर्ग के नागरिकों के समृद्धि से संभव है। प्रस्तुत शोध पत्र भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य हेतु किए जा रहे प्रयासों के अध्ययन तथा आवश्यक सुझावों के संदर्भ में है। इसमें द्वितीयक समंकों से प्राप्त जानकारियों को सम्मिलित करते हुए शिक्षा, कृषि, रोजगार, नवाचार तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों का उल्लेख किया गया है। जब किसी कार्य को निरंतर किया जाता है तो उसमें विशिष्टता और स्थिरता दोनों विकसित होती है, साथ ही मार्ग में आने वाली बाधाओं और हमारी कमजोरियों का ज्ञान भी होता है, जिसमें समय रहते सुधार कर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। विकसित भारत के लक्ष्य हेतु आर्थिक विकास, सामाजिक समरसता, पर्यावरणीय सजगता, कानूनी उत्तरदायित्व, तकनीकी समझ आदि क्षेत्रों में गति और सुधार देखने को मिल रहे हैं, इन्हीं विचारों का समावेष कर महिलाओं की शिक्षा एवं सुरक्षा, डिजिटल तकनीकों के उचित प्रयोग, मानव रचनाधर्मिता के विकास तथा भारतीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने हेतु कुछ आवश्यक सुझाव जो भारत को विकसित बनाने के मार्ग में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, को शोध पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्द (Keywords): विकसित भारत / 2047, निरंतरता, विकसित भारत के लक्ष्य हेतु प्रयास, रोजगार एवं नवाचार, आत्मनिर्भर राष्ट्र

SOUVENIR

MLDC26090

विकसित भारत 2047: आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना
फिनटेक और वित्तीय समावेशन

संगीता सेन
शोधार्थी, मैट्स विश्वविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़

डॉ.कमलजीत कौर
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य), मैट्स विश्वविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़

सारांश (Abstract):-
वित्तीय समावेशन का तात्पर्य समाज के प्रत्येक वर्ग को बैंकिंग, बचत, ऋण, बीमा और भुगतान जैसी बुनियादी वित्तीय सेवाओं तक समान और सुलभ पहुँच प्रदान करना है। विकासशील देशों में गरीबी, अशिक्षा, भौगोलिक दूरी और उच्च लेन-देन लागत के कारण बड़ी जनसंख्या अब भी औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर है। फिनटेक ने पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था को चुनौती देते हुए डिजिटल माध्यमों से वित्तीय सेवाओं को अधिक समावेशी बनाया है। स्मार्टफोन और इंटरनेट के बढ़ते उपयोग ने फिनटेक को वित्तीय समावेशन का एक सशक्त माध्यम बना दिया है।

SOUVENIR

MLDC26091

कृषि एवं खाद्य सुरक्षा : चुनौतियाँ, अवसर एवं सतत समाधान

मोहन पटेल
सहायक प्राध्यापक, महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर

सारांश (Abstract):-
कृषि एवं खाद्य सुरक्षा किसी भी देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिरता, जनस्वास्थ्य तथा राष्ट्रीय विकास का आधार होती है। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ जनसंख्या का बड़ा भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, वहाँ खाद्य सुरक्षा का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील एवं बहुआयामी है। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य केवल पर्याप्त भोजन की उपलब्धता से नहीं है, बल्कि सभी लोगों को हर समय सुरक्षित, पौष्टिक एवं सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य भोजन की भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक पहुँच से है। यह शोध पत्र कृषि उत्पादन, वितरण प्रणाली, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी नवाचार, सरकारी नीतियों एवं सामाजिक-आर्थिक कारकों के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा की स्थिति का विश्लेषण करता है। साथ ही, यह अध्ययन भारत में खाद्य सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियों, अवसरों तथा सतत कृषि आधारित समाधानों पर प्रकाश डालता है। शोध का निष्कर्ष यह इंगित करता है कि समग्र एवं समन्वित कृषि नीति, तकनीकी हस्तक्षेप, किसानों की आय में वृद्धि तथा पोषण-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से ही दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

मुख्य शब्द (Keywords): कृषि, खाद्य सुरक्षा, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, पोषण, नीति

SOUVENIR

MLDC26092

विकसित भारत 2047 हेतु औद्योगिक 4.0 एवं विनिर्माण में प्रौद्योगिकी की भूमिका का अध्ययन

मानवी शर्मा
शोधार्थी, मैट्स विश्वविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़

डॉ. संपदा भावे
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य), मैट्स विश्वविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़

सारांश (Abstract):-
भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की राष्ट्रीय परिकल्पना में आर्थिक विकास के साथ-साथ सतत् विकास को समान रूप से प्राथमिकता दी गई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में प्रौद्योगिकी की भूमिका अत्यंत निर्णायक है, विशेषतः इंडस्ट्री 4.0 के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र में हो रहे संरचनात्मक परिवर्तन के संदर्भ में। औद्योगिक 4.0 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा विश्लेषण, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग एवं साइबर-भौतिक प्रणालियों जैसी उन्नत तकनीकों का समावेश है, जो पारंपरिक विनिर्माण प्रणालियों को स्मार्ट और दक्ष उत्पादन प्रणालियों में परिवर्तित कर रही हैं। यह शोध-पत्र इंडस्ट्री 4.0 और विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्संबंध का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट करता है कि किस प्रकार डिजिटल नवाचार उत्पादन लागत में कमी, उत्पाद गुणवत्ता में सुधार, संसाधनों के कुशल उपयोग तथा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देकर आर्थिक एवं पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। अध्ययन में यह भी दर्शाया गया है कि स्मार्ट विनिर्माण और डिजिटल आपूर्ति शृंखला न केवल औद्योगिक उत्पादकता को सुदृढ़ करती हैं, बल्कि रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन कर समावेशी विकास को भी प्रोत्साहित करती हैं। साथ ही, शोध में भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में इंडस्ट्री 4.0 के क्रियान्वयन से संबंधित प्रमुख चुनौतियों-जैसे तकनीकी कौशल की कमी, पूंजी निवेश की आवश्यकता, डिजिटल अवसंरचना का अभाव तथा साइबर सुरक्षा जोखिमका विवेचन किया गया है। निष्कर्षतः, यह अध्ययन प्रतिपादित करता है कि प्रभावी नीतिगत समर्थन, कौशल उन्नयन एवं तकनीकी नवाचार के माध्यम से इंडस्ट्री 4.0 भारत को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर करने में एक सशक्त माध्यम सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द (Keywords): विकसित भारत, प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विनिर्माण, समावेशी विकास

SOUVENIR

MLDC26093

भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली का विकास व आर्थिक सशक्तिकरण में इसकी भूमिका

महिमा जोबनपुत्रा
शोधार्थी, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव

डॉ. ए. एन. माखीजा
शोध निर्देशक, प्राध्यापक, शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव

सारांश (Abstract):-
पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है विशेषकर 2020 के पश्चात। इससे केवल व्यापारिक प्रक्रिया सरल नहीं हुई अपितु भारत आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास की ओर भी बढ़ रहा है। इस शोध पत्र का उद्देश्य विभिन्न डिजिटल माध्यमों का अध्ययन कर आर्थिक सशक्तिकरण में उनकी भूमिका का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन पूर्णत: द्वितीय क समंको पर आधारित है, समंको को आरबीआई, एनपीसीआई, भारत सरकार के विभिन्न प्रतिवेदनों से एकत्रित किया गया है । शोध से यह ज्ञात हो रहा है कि डिजिटल भुगतान से व्यापारिक प्रक्रिया सरल एवं पारदर्शी हुई है और साथ ही उपभोक्ता, छोटे व्यापारी, एमएसएमई व्यापारियों के कार्य भी सहज हो गए हैं हालांकि साइबर सुरक्षा जोखिम ,डिजिटल साक्षरता की कमी अभी भी चिंता का विषय है, परंतु इस समस्या पर एनपीसीआई व सरकार द्वारा जागरुकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । निष्कर्ष में यह कह सकते हैं कि डिजिटल भुगतान प्रणाली विकसित भारत 2047 के लक्ष्य तक पहुंचने और भारत को आत्मनिर्भर व सशक्त अर्थव्यवस्था बनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है ।

मुख्य शब्द (Keywords): डिजिटल भुगतान प्रणाली, आर्थिक सशक्तिकरण,आर बीआई,एन पी सी आई

SOUVENIR

MLDC26094

कृषि और खाद्य सुरक्षा

डॉ. दिव्या शुक्ला
सहायक प्राध्यापक
दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

सारांश (Abstract):-
कृषि और खाद्य सुरक्षा के बिना राज्य के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कृषि और खाद्य सुरक्षा आपस में घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए है, जहाँ कृषि भोजन उत्पादन का आधार है, वही खाद्य सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि सभी लोगों को हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिलें । जलवायु में परिवर्तन बढ़ती माँग और खराब प्रबंधन आदि जैसी चुनौतियाँ दोनों को प्रभावित करती है जिससे खाद्य असुरक्षा बढ़ती है, लेकिन सतत् कृषि पद्धतियाँ और सरकारी मिशन (जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन) इन समस्याओं को कम करने और खाद्य उपलब्धता व पोषण में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। कृषि की भुमिका जहाँ भोजन के स्त्रोत्, आर्थिक आधार एवं पोषक तत्वों का उत्पादन करने में है वहीं खाद्य सुरक्षा के (4) चार मुख्य पहलू उपलब्धता, पहुँच, उपयोग एवं स्थिरता में है। इन दोनों के लिये ही जलवायु परिवर्तन, संसाधन प्रबंधन, जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि, संघर्ष और असमानता महत्वपूर्ण चुनौतियाँ है जिनका सामना करने के लिये सतत् कृषि तकनीकें, खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रम, आपूर्ति श्रृखंला में सुधार, पोषण पर ध्यान केन्द्र, सुरक्षा जाल का बेहतर प्रबंधन ताकि कमजोर वर्ग के लोगों को पर्याप्त भोजन व धन आसानी से उपलब्ध हो सकें।

मुख्य शब्द (Keywords): कृषि, खाद्य, जलवायु, सुरक्षा, तकनीकी जनसंख्या, पर्यावरण, सतत् विकास, आर्थिक विकास, पोषक तत्व, सरकारी मिशन, सुरक्षा-जाल, किसान, प्रौद्योगिकी, कीटनाशक।

SOUVENIR

MLDC26095

पर्यटन संस्कृति और विरासत

श्रीमती कुसुम राठौर,
सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग
दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

सारांश (Abstract):-
संस्कृति मानव का आईना होता है आज पर्यटन वि-रु39 यव अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है इसमें सांस्कृतिक विरासत की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी दे-रु39या की सांस्कृतिक विरासत दुनिया भर से अधिक पर्यटकों को आकि्नवजर्यात कर सकती है और दे-रु39 या में पर्यटन विकास के लिए प्रेरक बन सकती है पर्यटन विविध प्रकार के प्राकृतिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक व धार्मिक तत्व तथा आधारभूत सुविधाओं यातायात आवासीय सुविधाओं ि–रु39 याक्षा स्वास्थ्य बैंकिंग सुरक्षा आदि का मिश्रित अद्-रु39 यय उद्योग है पर्यटन वर्तमान में वि-रु39यव को सबसे तेजी से विकसित करने वाला संसाधन है।

संक्षेप में संस्कृति और विरासत पर्यटन का आधार है और पर्यटन संस्कृति और विरासत को जिंदा रखना और उन्हें वै-रु39यवक मंच में प्रस्तुत करने का एक -रु39याक्ति-रु39याली माध्यम है।

SOUVENIR

MLDC26096

ई-गवर्नेंस और डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं

डॉ. संगीता घई
प्राचार्य
श्रीमती पी. जी. डागा कन्या महाविद्यालय
रायपुर, छ.ग.

सारांश (Abstract):-
वर्तमान युग में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ;ICT न केवल प्रशासनिक कार्यो को सरल बनाती है, बल्कि यह सरकार और नागरिको के बीच की दुरी को कम करने का एक सशक्त माध्यम है। वर्तमान में शासन का अर्थ केवल नीति निर्धारण नहीं, बल्कि सेवाओं का कुशल और त्वरित वितरण है। सेवा वितरण का लोकतंत्रीकरण कर बिचौलियों की भुमिका को समाप्त कर सरकारी सेवाओं को सीधे आम जनता के हाथ में पहुंचाया जा रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत अनेक आधार जैसे, डिजिलॉकर, उमंग ऐप, भारत नेट ऑनलाईन कर भुगतान ई-हास्पिटल, ई-कोर्टस, ई-पंचायत ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और समयबद्ध बनाया है। इन सेवाओं के माध्यम से न केवल समय और लागत की बचत हुई है, बल्कि भ्रष्टाचार में कमी और सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार भी हुआ है। डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं विशेष रूप से ग्रामीण एवं दुरस्त क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए लाभकारी सिद्ध हुये हैं जहां भौतिक पहुंच की सीमाएं पहले एक बड़ी समस्या थी।
ई गवर्नेस के प्रभावी क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां भी विद्यमान है जैसे- डिजिटल साक्षरता की कमी, साइबर सुरक्षा संबंधी जोखिम, तकनीकी डेटा गोपनीयता से जुड़े मुद्दे। इन चुनौतियों को समाधान हेतू सरकार को समावेशी नीतियां सुदृढ साइबर सुरक्षा ढांचा और व्यापक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम पर ध्यान देना आवश्यक है। अतः ई गवर्नेस और डिजिटल सेवाएं सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि इन्हे समुचित योजना प्रशिक्षण और तकनीकि समर्थन के साथ लागू किया जाए तो यह न केवल प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाएगी बल्कि लोकतंत्र को अधिक सहभागी और सशक्त भी बनाएंगी।

मुख्य शब्द (Keywords): दुग्ध उत्पादन, छत्तीसगढ़, विकसित भारत 2047, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकारी मॉडल, गोधन न्याय योजना, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता

SOUVENIR

MLDC26097

आर्थिक विकास में मानव संसाधन प्रबंध की भूमिका

डॉ० गिरजा शंकर गुप्ता
सहायक प्राध्यापक स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग
दुर्गा महाविद्यालय रायपुर [(छ.ग.]

सारांश (Abstract):-
किसी भी संगठन के लिए मानव संसाधन प्रबंधन महत्वपूर्ण है जो कि संगठन के सिद्धान्तों को बनाये रखे और दुविधाओ विवादों और संघर्षों के बिना विकास के वाछित उद्देश्य पूरा कर सके। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में यदि कोई देश समाज संस्था व उद्योग नयी तकनीकों को नहीं अपनायेगा तो वह इस दौर में पिछड़ जायेगा। अतः यह आवश्यक है कि श्रमिकों कर्मचारियों एवं अधिकारियों सहित समाज के प्रत्येक क्षेत्र में सभी लोग विकास के लिए प्रयत्न करें। विवेकानंद जी ने कहा है कि भारत में जो व्यक्ति निम्न स्तर का जीवन व्यतीत कर रहा है इसका कारण है अशिक्षा जिससे उनमें स्वयं के विकास की कोई इच्छा हीं नहीं रह जाती है। अतः भारत के नव निर्माण हेतु हमें शिक्षा के क्षेत्र में एवं बहुआयामी क्षमता जैसे तकनीकी शिक्षा गृह उद्योग प्रबंध कम्प्यूटर शिक्षा आदि से लोगों को परिचित कराना चाहिए। हमें शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विकास करना होगा क्योंकि आज भी देश में लगभग 24 प्रतिशत पुरुष तथा 46 प्रतिशत महिलायें अशिक्षित हैं। जब तक शत प्रतिशत साक्षरता नहीं होगा सर्वांगिण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः मानव संसाधन पूरी दक्षता के साथ कार्य तभी कर पायेगा जब सभी को उचित वपर्याप्त शिक्षा मिले।

मानव संसाधन प्रबंधन किसी संगठन की संपत्ति होती है अर्थात उसका कार्यबल या कर्मचारियों के प्रबंधन में एक व्यवस्थित रणनीतिक दृष्टिकोण है। यह एक बहुआयामी प्रणाली है। इसका उद्देश्य सगठन में कर्मचारियों के कामकाज को सुव्यवस्थित करना और एक स्वस्थ कार्य सस्कृति को बनाये रखना है। यह सगठन का एक आवश्यक विभाग है जिसे मानव संसाधन प्रबंधकों द्वारा उत्साही मानव संसाधन पेशेवरों की एक जीवत टीम के सहयोग से संचालित किया जाता है। मानव संसाधन प्रबंध से तात्पर्य है किसी राष्ट्र की समस्त जनसंख्य के सभी गुणों एवं सपूर्ण क्षमता का विकास कर उसे राष्ट्र के हित के लिए उपयोग करना। जिस प्रकार किसी राष्ट्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर उसके सर्वश्रेष्ठ रूप का उपयोग किया जाता है उसी प्रकार राष्ट्र की सपूर्ण जनशक्ति की क्षमता में विकास कर इसका उपयोग राष्ट्र की उन्नति के लिए किया जा सकता है। किसी राष्ट्र का निर्माण तब तक संभव नहीं है जब तक की उसमें रहने वाले लोगों का चहुमुखी विकास नहीं होता। प्रबंध निरंतर चलनी वाली प्रक्रिया है जो समय के मांग के अनुसार परिवर्तित होता है। नये विचारों नई तकनीकों नई विचार धाराओं नये चिन्तन एवं नये प्रारूपों के साथ। प्रबंध की कार्य प्रणालियों में तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। प्रबंध के क्षेत्र में अनेक नवीन प्रवृत्तियां जन्म ले रही है। नई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं तथा नये सामाजिक एवं नीतिगत मूल्यों का उदय हो रहा है। इस नये उत्तर दायित्वों एवं चुनौतियों से प्रबंध की भूमिका अत्यन्त गतिशील तथा सम्बन्ध अति 'सहवीजी' हो गये हैं। मानव की प्रकृति गतिशील होने के कारण मानव का प्रबंध करना हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। क्योंकि संसार में कोई भी दो व्यक्ति ऐसे नहीं है जो योग्यता क्षमता, भावनाओं तथा व्यवहार आदि में एक समान हो। ऐसी परिस्थिति उन्हें मशीन की भांति प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। अतः उनके साथ व्यवहार करने और उनका प्रबंध करने में बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है जो कि मानव संसाधन प्रबंध के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है।

SOUVENIR

MLDC26098

विकसित भारत @ 2047 : फल एवं फूल व्यवसाय के माध्यम से समावेशी आर्थिक विकास

ललित मोहन वर्मा
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)
महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर (छ. ग.)

सारांश (Abstract):-

प्रस्तुत शोधपत्र विकसित भारत @ 2047 की राष्ट्रीय परिकल्पना के संदर्भ में फल एवं फूल व्यवसाय (बागवानी एवं फ्लोरीकल्चर) की भूमिका का बहुआयामी विश्लेषण करता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ कृषि आजीविका का प्रमुख साधन रही है; किंतु पारंपरिक अनाज-आधारित कृषि की सीमाओं को देखते हुए उच्च मूल्यवर्धित कृषि क्षेत्रों की ओर संक्रमण आवश्यक हो गया है। इस परिप्रेक्ष्य में फल एवं फूल व्यवसाय न केवल किसानों की आय में वृद्धि का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है, बल्कि रोजगार सृजन, निर्यात संवर्धन तथा समावेशी आर्थिक विकास की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है।

शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि किस प्रकार फल एवं फूल व्यवसाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ महिला, युवा एवं सीमांत किसानों को आर्थिक विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक हो सकता है। अध्ययन में यह प्रतिपादित किया गया है कि बागवानी फसलों का उत्पादन पारंपरिक कृषि की तुलना में कम भूमि पर अधिक आय प्रदान करता है, जिससे छोटे एवं सीमांत किसानों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। साथ ही, फ्लोरीकल्चर उद्योग श्रम-प्रधान होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करता है, जो समावेशी विकास का आधार बनता है।

शोध में यह भी रेखांकित किया गया है कि फल एवं फूल व्यवसाय का विस्तार केवल उत्पादन तक सीमित न होकर मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, कोल्ड-चेन, परिवहन तथा विपणन जैसी गतिविधियों के माध्यम से एक संपूर्ण कृषि-व्यवसाय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है तथा आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को सुदृढ़ आधार प्रदान करता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई–नाम, ऑनलाइन मार्केटिंग और आधुनिक आपूर्ति शृंखला प्रणालियाँ फल एवं फूल व्यवसाय को अधिक लाभकारी एवं पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

इसके अतिरिक्त, शोधपत्र में सतत विकास के संदर्भ में फल एवं फूल व्यवसाय की प्रासंगिकता पर भी प्रकाश डाला गया है। जैविक खेती, जल-संरक्षण तकनीक, पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन पद्धतियाँ तथा हरित रोजगार के अवसर इस क्षेत्र को पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। फल एवं फूल उत्पादन न केवल पोषण सुरक्षा एवं जीवन-स्तर में सुधार करता है, बल्कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु फल एवं फूल व्यवसाय को नीति-स्तर पर विशेष प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। उचित सरकारी समर्थन, तकनीकी नवाचार, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन एवं बाजार तक पहुँच सुनिश्चित कर इस क्षेत्र को समावेशी आर्थिक विकास का सशक्त माध्यम बनाया जा सकता है। इस प्रकार, फल एवं फूल व्यवसाय विकसित भारत की यात्रा में ग्रामीण समृद्धि, सामाजिक समावेशन और सतत आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ सिद्ध हो सकता है।

MLDC26099

विकसित भारत 2047 की दिशा में डिजिटल पत्रकारिता की भूमिका

श्रीमति गीता शर्मा
सहायक प्राध्यापक ,पत्रकारिता विभाग
महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय रायपुर

सारांश (Abstract):-
भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए समाज के हर क्षेत्र में जागरूकता, भागीदारी और पारदर्शिता जरूरी है। डिजिटल पत्रकारिता आज सूचना का सबसे तेज़ और प्रभावशाली माध्यम बन चुकी है। यह शोध-पत्र विकसित भारत 2047 के संदर्भ में डिजिटल पत्रकारिता की भूमिका का अध्ययन करता है। इसमें यह बताया गया है कि डिजिटल मीडिया किस प्रकार लोगों तक सरकारी योजनाओं, सामाजिक मुद्दों और विकास से जुड़ी जानकारियाँ पहुँचा रहा है। शोध में डिजिटल पत्रकारिता की वर्तमान स्थिति, उसके सकारात्मक प्रभाव और उससे जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यदि डिजिटल पत्रकारिता को जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ अपनाया जाए, तो यह भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

मुख्य शब्द (Keywords): डिजिटल पत्रकारिता, विकसित भारत 2047, मीडिया, सूचना तकनीक, सामाजिक विकास

SOUVENIR

MLDC26100

ई-शासन और डिजिटल सार्वजनिक सेवाएँ

सुश्री माया निर्मलकर
शोधार्थी
सेठ आर.सी.एस. आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, दुर्ग (सी.जी.)

सारांश (Abstract):-
भारत में ई-शासन सुशासन का पर्याय बनता जा रहा है। केन्द्र व राज्य सरकारो के विभिन्न विभाग नागरिको, व्यापारियों तथा सरकारी संगठनों को ही नही अपितु समाज के हर वर्ग को सूचना व प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न सेवायें प्रदान कर रहे है। भारत में ई-शासन का प्रादुर्भाव शासकीय विभागों के तेजी से कप्यूटरीकरण से आरंभ हुआ।अब यह उस बिन्दु तक पहुँच चुका है, जिससे शासन के सूक्ष्मतर बिंदुओं जैसे नागरिक केंद्रित, संवा अभिमुखीकरण तथा पारदर्शिता से बढ़ावा मिल रहा है। वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी का युग है।और इसका प्रमाण है ई-शासन की अवधारणा। संपूण भारत में आज शायद ही कोई ऐसी जगह हो, ई-शासन पहल न की हो। सूचना तकनीकी युग ने ज्ञान पर आधारित पहल के जो द्वार खोले है, उसका एक उत्साहजनक परिणाम ई- शासन की अवधारणा के रूप में उभरकर सामने आया है।सरकार की आम जनता के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इलेक्ट्रानिक माध्यम जैसे - कंप्यूटर, इंटरनेट,मोबाईल आदि से उपलब्ध कराना ई-शासन कहलाता है। इसे अंतर्गत शासकीय सेवायें व सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना सन् 1970 में की तथा सन् 1977 में नेशनल इनफॉमैटिक्स सेंटर की स्थापना ई-शासन की दिशा में प्रथम प्रयास था।

SOUVENIR

MLDC26101

विकसित भारत में पत्रकारिता के नए आयाम

डॉ. लोकेश्वर प्रसाद सिन्हा,
सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग
दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

सारांश (Abstract):-
विकसित भारत में पत्रकारिता के नए आयामों में डिजिटल क्रांति, AI और डेटा का उपयोग, नागरिक पत्रकारिता, पॉडकास्टिंग, और व्याख्यात्मक पत्रकारिता शामिल हैं, जो तकनीक और बदलती उपभोक्ता ज़रूरतों से प्रेरित हैं, जहाँ अब सिर्फ़ समाचार नहीं, बल्कि गहरी विश्लेषण, इंटरैक्टिव कहानियाँ और बहुआयामी आवाज़ों को मंच मिलता है, हालांकि बाजारवाद और विश्वसनीयता बनाए रखने की चुनौती भी है।

पत्रकारिता के नए आयाम (New Dimension of Journalism): डिजिटल और सोशल मीडिया का प्रभुत्वः-युवा पीढ़ी के लिए प्राथमिक समाचार स्रोत अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया हैं, जिससे प्रिंट मीडिया के सामने चुनौती है। तेज़ प्रतिपुष्टि (feedback) और वैश्विक पहुंच (Global village) की अवधारणा ने पत्रकारिता को नया रूप दिया है।

तकनीकी एकीकरण(Technical Integration) : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI समाचार लेखन, सामग्री सिफ़ारिश (content recommendation) और तथ्य-जाँच (fact-cheking)में AI का उपयोग बढ़ रहा है।

डेटा जर्नलिज्मः डेटा विश्लेषण से साक्ष्य.आधारित रिपोर्टिंग और खोजी पत्रकारिता मज़बूत हुई है, जिससे विश्वसनीयता बढ़ी है।

पॉडकास्टिंगः यह गहन रिपोर्टिंग और विविध आवाज़ों को उभारने का एक नया और प्रभावी माध्यम बन गया है, जो भविष्य को आकार दे रहा है।

व्याख्यात्मक पत्रकारिता (Explanatory Journalism): सिर्फ़ घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं, बल्कि उनकी पृष्ठभूमि और परिणामों का विश्लेषण करना।

सहयोगी और भागीदारी पत्रकारिता (Collaborative & Participatory Journalism): इसमें नागरिक भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जिससे पारंपरिक गेटकीपिंग (gatekeeping) की भूमिका बदल रही है।

व्यावसायिक चुनौतियाँ और स्थिरता (Business Challenges & Sustainability): मीडिया का बाज़ार.उन्मुख होना और सामाजिक सरोकारों की खबरों की कमी एक चुनौती है।

डिजिटल सब्सक्रिप्शन, क्राउडफंडिंग जैसे नए मॉडल गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता और संपादकीय स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

नागरिक.केंद्रित पत्रकारिता (Citizen – Centric Journalism) : मीडिया साक्षरता (Media literacy) अब ज़रूरी है, ताकि नागरिक विश्वसनीय स्रोतों को पहचान सकें और लोकतांत्रिक चर्चा में भाग ले सकें।

स्थानीयकृत और खंडित समाचार कवरेज के बीच भी विश्वसनीयता और प्रभाव बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है।

संक्षेप में, विकसित भारत में पत्रकारिता तकनीक, डेटा और जन.भागीदारी के साथ विकसित हो रही है, जहाँ अब रिपोर्टिंग सिर्फ़ सूचना देना नहीं, बल्कि विश्लेषण करना, संलग्न करना और समाज को सशक्त बनाना भी है, लेकिन इन सभी के बीच सत्यनिष्ठा और गुणवत्ता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

SOUVENIR

MLDC26102

स्मार्ट सिटी और शहरी विकास

नीलू शुक्ला
सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान)
श्रीमती पी. जी. डागा कन्या महाविद्यालय कचहरी चौक रायपुर छत्तीसगढ़

सारांश (Abstract):-
भारत में शहरीकरण की गति अत्यंत तीव्र हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन के कारण नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जिससे बुनियादी सेवाओं, आवास, परिवहन, जल आपूर्ति, स्वच्छता, ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण जैसी आवश्यकताओं पर भारी दबाव पड़ा है। इस संदर्भ में भारत सरकार ने 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की। स्मार्ट सिटी की अवधारणा तकनीक-आधारित, नागरिक-केंद्रित और सतत विकास पर आधारित है, जिसका उद्देश्य शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना है।

इस शोध पत्र में स्मार्ट सिटी और शहरी विकास के विभिन्न आयामों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसमें शामिल हैं: स्मार्ट सिटी की अवधारणा, शहरी विकास की परिभाषा, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन की प्रगति, स्मार्ट सिटी और शहरी विकास से जनता को होने वाले लाभ और नुकसान, प्रशासनिक सुधार, ई-गवर्नेंस, परियोजनाओं की चुनौतियाँ, सुझाए गए उपाय और रायपुर (छत्तीसगढ़) आधारित उदाहरण।

स्मार्ट सिटी और शहरी विकास के माध्यम से नगरों में अवसंरचना और डिजिटल सेवाओं का सुधार हुआ है। नागरिकों को बेहतर जल आपूर्ति, स्वच्छता, ट्रैफिक प्रबंधन, डिजिटल भुगतान, ई-म्युनिसिपल सेवाएँ और स्मार्ट पार्किंग जैसी सुविधाएँ मिली हैं। इसके अतिरिक्त, रोजगार के नए अवसर, पर्यावरणीय सुरक्षा और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा मिला है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-गवर्नेंस ने प्रशासनिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुदृढ़ किया है। रायपुर स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के माध्यम से इन लाभों का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है।

इस प्रकार, स्मार्ट सिटी और शहरी विकास न केवल नगरों के शारीरिक ढाँचे को सुधारने का माध्यम हैं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से सतत शहरी भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। यह पहल भविष्य के शहरीकरण को व्यवस्थित, टिकाऊ और समावेशी बनाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

SOUVENIR

MLDC26103

विकसित भारत अर्थव्यवस्था में ग्रामीण उद्यमी महिलाओं की सहभागिता: एक दृश्टिकोण

डॉ. मनोज कुमार शर्मा[1]
सहायक प्राध्यापक , वाणिज्य
शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय महासमुंद (छ.ग.)

श्री ओम प्रकाश पटेल [2]
सहायक प्राध्यापक, भूगोल
शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय महासमुंद (छ.ग.)

सारांश (Abstract):-
वर्तमान' में तेजी से वैश्विक पटल मे उभरते भारत में प्रबंधन, वाणिज्य तथा कृषि व उस पर आधारित ग्रामीण रोजगार एवं उद्योगों के क्षेत्र में ग्रामीण परिवेश की महिला शक्ति के उचित प्रयोग एवं उसके योगदान से समुचित लाभ उठाने के मार्ग मे बहुत सी बाधायें एवं समस्याएं आगे आ रही हैं। यदि हमने ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध महिला संसाधनों के उचित दोहन तथा उनके योगदान के मूल्यांकन की उचित व्यवस्था नही की तो विकसित भारत की संकल्पना को आर्थिक विकास एवं प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने में काफी कठिनाई आयेगी। आज जिस प्रकार ग्रामीण परिवेश की महिलायें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह प्रबंधन हो, वाणिज्य या व्यवसाय हो अथवा चिकित्सा या तकनीकी एवं कौशल विकास के क्षेत्र हो उनमें कामयाबी के जिस तरह नये कीर्तिमान बना रही हैं उसको देखते हुये यह आवश्यक हो गया है कि महिलाओं की कार्यक्षमताओं तथा कार्यकुशलता का प्रयोग वाणिज्य, व्यवसाय एवं कृषि तकनीक तथा उससे सह-संबंधित उद्योगों के विकास एवं प्रबंध में किया जाये तभी एक सशक्त एवं विकसित राष्ट्र की आर्थिक प्रगति एवं विकास सुनिश्चित हो सकेगी अन्यथा महिलाओं की सहभागिता के बिना कौशल विकास एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की सफलता एक कोरी कल्पना मात्र होगी। वर्तमान में सरकार द्वारा ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके विकास के लिये कौशल एवं उद्यमिता विकास के अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं लेकिन इन महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते समय यह अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिये कि इन कार्यक्रमों से जुड़ी महिलाओं के लिये लगाये गये विभिन्न शिविरों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का स्थान व समय इन महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुये निश्चित किया जाये तो अधिक से अधिक महिलायें उसमें उपस्थित होकर उसका लाभ उठा सकती है एवं एक सफल महिला उद्यमी बनकर विकसित भारत राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विकास एवं तरक्की में अपना श्रेष्ठ योगदान प्रदान कर सकती है। इस स्वीकार्य सत्य को सभी को ध्यान मे रखना होगा कि महिला उद्यमिता एवं उनके नवाचारों को आज देश में आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत माना गया है।

मुख्य शब्द (Keywords): ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला उद्यमिता, नवाचार, विकसित भारत संकल्पना, कौशल विकास

SOUVENIR

MLDC26104

ई-शासन और डिजिटल सार्वजनिक सेवाएँ

डॉ. मनोज कुमार शर्मा[1]
सहायक प्राध्यापक , वाणिज्य
शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय महासमुंद (छ.ग.)

श्री ओम प्रकाश पटेल [2]
सहायक प्राध्यापक, भूगोल
शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय महासमुंद (छ.ग.)

सारांश (Abstract):-
भारत में ई-शासन सुशासन का पर्याय बनता जा रहा है। केन्द्र व राज्य सरकारो के विभिन्न विभाग नागरिको, व्यापारियों तथा सरकारी संगटनो को ही नही अपितु समाज के हर वर्ग को सूचना व प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न सेवाए प्रदान कर रहे है। भारत में ई-शासन का प्रादुर्भाव शासकीय विभागों के तेजी से कप्यूटरीकरण से आरंभ हुआ। अब यह उस बिन्दु तक पहुच चुका है, जिससे शासन के सूक्ष्मतर बिन्दुओं जैसे नागरिक केंद्रित, संवा अभिमुखीकरण तथा पारदर्शिता कसे बढ़ावा मिल रहा है। वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। और इसका प्रमाण है ई-शासन की अवधारणा। संपूण भारत में आज शायह ही कोई ऐसी जगह हो, ई-शासन पहल न की हो। सूचना तकनीकी युग ने ज्ञान पर आधारित पहल के जो द्वार खोले है, उसका एक उत्साहजनक परिणाम ई- शासन की अवधारणा के रूप में उभरकर सामने आया है। सरकार की आम जनता के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इलेक्ट्रानिक माध्यम जैसे - कंव्यूटर, इंटरनेट, मोबाईल आदि से उपलब्ध कराना ई-शासन कहलाता है। इसे अंतर्गत शासकीय सेवाएॅ व सूचनाएॅ ऑनलाइन उपलब्ध होती है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना सन् 1970 में की तथा सन् 1977 में नेशनल इनफॉमैटिक्स सेंटर की स्थापना ई-शासन की दिशा में प्रथम प्रयास था।

ई-शासन के अंतर्गत कई सरकारी सेवाएॅ संचालित होती है, जिनका मुख्य उदेश्य सरकारी कार्यो को डिजिटाईज करना, पारदर्शिता बढ़ाना तथा नागरिको को धर बैठे सुविधाएॅ प्रदान करना है। डिजिलॉकर, दस्तावेजो जैसे -ड्राविंग लाइसेंस, मार्कशीट, आदि को डिजिटल रूप से स्टोर तथा साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा आधार, जीएसटी, ई-हॉस्पिटल (ऑनलाईन अपांइटमेंट), राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, आयकर ई-फाइलिंग, भू-अभिलेखो का डिजिटलीकरण, तथा विभिन्न शासकीय पोर्टल जैसे डिजिटल इंडिया पोर्टल, ई-सेवा पोर्टल आदि के माध्यम से जानकारी व सेवाओं तक पहुच शामिल है, जो नागरिको के लिए कर भुगतान, लाईसेंस नवीनीकरण, परमिट आवेदन एवं अन्य प्रशासनिक कार्यो को आसन बनाता है। ये सेवाएॅ डिजिटल इंडिया पहल के तहत संचालित होती है। तथा उनका उदेश्य सरकार को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक -अनुकल बनाना है।

मुख्य शब्द (Keywords): ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला उद्यमिता, नवाचार, विकसित भारत संकल्पना, कौशल विकास

SOUVENIR

MLDC26105

छत्तीसगढ़ राज्य के आर्थिक विकास में प्लाईवुड उद्योग की भूमिका का अध्ययन: रायपुर जिले के संदर्भ में

देवाशीष मुखर्जी
प्राचार्य , महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर

राकेश मनचंदा
शोधार्थी (वाणिज्य),महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर

सारांश (Abstract):-
यह शोधपत्र छत्तीसगढ़ राज्यए विशेषकर रायपुर वजलेके संदभभमेंप्लाईुिड उद्योग के आवथभक योगदान काविश्लेषण करता है। इसमेंउद्योग के प्रकारए तथ्ांकए रोजगार सृजनए उद्योग.विकास और क्षेत्रीय प्रभिा का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत वकया गया है। अध्ययन मेंयह भी दशाभया गया हैवक कै सेप्लाईुिड उद्योग राज्य की लघुऔर मध्यम औद्योवगक संरचना को मजबूत कर रहा है।

SOUVENIR

MLDC26106

Empowering Bharat: Financial Inclusion and FinTech for Rural Transformation and Urban Growth through Artificial Intelligence

DRMANJU KUSHWAHA
DEPARTMENT OF COMPUTER APPLICATIONS
SHRI SHANKRACHARYA INSTITUTE OF PROFESSIONAL STIDIES RAIPUR(C.G.)

Abstract:
Financial inclusion plays a vital role in empowering Bharat by ensuring equitable access to financial services and fostering sustainable economic growth. The rapid advancement of Financial Technology (FinTech), combined with Artificial Intelligence (AI), has significantly transformed India's financial ecosystem, benefiting both rural and urban populations. This paper examines the impact of AI-driven FinTech solutions in enhancing financial accessibility, efficiency, and security across diverse socio-economic groups. AI applications such as machine learning-based credit scoring, biometric authentication, fraud detection, predictive analytics, and intelligent chatbots have enabled personalized and reliable financial services. In rural areas, AI- powered digital banking, mobile payment systems, and micro-financing platforms support farmers, self-help groups, and small entrepreneurs by improving access to credit and promoting financial literacy. Simultaneously, urban growth is strengthened through AI-enabled smart payment systems, digital lending, and data-driven financial management tools that enhance operational efficiency and innovation. The study highlights the role of digital infrastructure, government initiatives, and public–private partnerships in accelerating AI-based financial inclusion. It concludes that the integration of Artificial Intelligence with FinTech serves as a powerful catalyst for rural transformation and urban development, thereby contributing significantly to the vision of an inclusive and digitally empowered Bharat.

Keywords: Financial Inclusion, FinTech, Artificial Intelligence, Rural Transformation, Urban Growth, Digital India

SOUVENIR

MLDC26107

Role of Artificial Intelligence in Transforming Education and Skill Development

MS APARNA TIWARI
ASSISTANT PROFESSOR (COMPUTER SCIENCE)
SHRI SHANKARACHARYA INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES, RAIPUR (C.G.)

Abstract:
Intelligence (AI) has become a powerful driver in transforming education and skill development, contributing significantly to the vision of Viksit Bharat 2047. The integration of AI technologies into educational systems is reshaping traditional teaching–learning processes by promoting personalized, adaptive, and technology-enabled learning environments. AI-based tools such as intelligent tutoring systems, virtual classrooms, automated evaluation methods, and learning analytics enable learners to acquire knowledge at their own pace while improving learning outcomes and engagement.

In the domain of skill development, Artificial Intelligence plays a crucial role in identifying emerging industry requirements and aligning educational curricula with market demands. AI-powered platforms support continuous upskilling and reskilling by analyzing learner performance, predicting skill gaps, and recommending customized learning pathways. This approach enhances employability, workforce productivity, and innovation capacity, which are essential for sustainable economic growth. Furthermore, AI-driven career guidance and vocational training systems empower students and professionals to make informed career choices aligned with future job trends.

Despite its vast potential, the adoption of Artificial Intelligence in education and skill development faces challenges such as digital divide, lack of infrastructure, data privacy concerns, and the need for trained educators capable of effectively using AI tools. Addressing these challenges through inclusive policies, ethical AI practices, and capacity building is critical. This paper highlights the transformative role of Artificial

Intelligence in strengthening education and skill development ecosystems and concludes that strategic and responsible use of AI can serve as a key enabler in achieving inclusive growth and sustainable development for Viksit Bharat 2047.

Keywords: Artificial Intelligence, Education Transformation, Skill Development, Viksit Bharat 2047, Digital Learning, Sustainable Development

SOUVENIR

MLDC26108

Innovation & Enterpreneurship

MS. JALPA SONI
ASSISTANT PROFESSOR
SHRI SHANKARACHARYA INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES, RAIPUR

Abstract:
Innovation and entrepreneurship are central to achieving the vision of Vikshit Bharat 2047, where inclusive economic growth and sustainability move hand in hand. Rapid advancements in digital technologies such as artificial intelligence, fintech, green technology, and Industry 4.0 are transforming traditional business models and creating new entrepreneurial opportunities across sectors. This paper examines how technology-driven innovation strengthens India's startup ecosystem, enhances productivity, and promotes employment generation while addressing social and environmental challenges. Special emphasis is placed on sustainable entrepreneurship, which integrates economic viability with environmental responsibility and social equity. The study highlights the role of policy support, digital infrastructure, skill development, and innovation ecosystems in enabling entrepreneurs to contribute effectively to national development goals. By fostering technology-enabled enterprises, India can accelerate industrial growth, empower rural and urban economies, and ensure long-term sustainability. The findings suggest that innovation-led entrepreneurship is a critical pathway for realizing the aspirations of a developed, resilient, and self-reliant India by 2047.

SOUVENIR

MLDC26109

Enhancing Citizen Participation and Trust through Digital Innovation

NEETA DHANGAR
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE,
GOVT.NAGARJUNA POST GRADUATE COLLEGE OF SCIENCE, RAIPUR

KIRAN BALA DUBEY
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE,
GOVT.NAGARJUNA POST GRADUATE COLLEGE OF SCIENCE, RAIPUR

Abstract:
Abstract—Digital innovation has become a key enabler of modern governance by reshaping the ways in which governments interact with citizens. This research paper explores the role of digital technologies in enhancing citizen participation and strengthening trust in government institutions. Based on a review of existing literature, the study examines how digital platforms, e-governance systems, and ICT-enabled services pro- mote transparency, accountability, and citizen-centric service delivery. The analysis reveals that digital innovation improves access to information, facilitates inclusive participation, enhances service efficiency, and supports effective grievance redressal, thereby contributing to higher levels of public trust. However, challenges such as unequal digital access, limited digital literacy, cybersecurity risks, and privacy concerns continue to pose significant barriers. The paper emphasizes that addressing these challenges through inclusive digital policies and robust governance frameworks is essential for achieving sustainable and trustworthy governance.

Keywords: E-governance, Citizen Participation, Trust, Transparency, ICT

SOUVENIR

SOUVENIR

SOUVENIR

SOUVENIR

PROGRAM OFFERED

- B.Com.
- B.B.A
- B.A.
- B.C.A.
- B.Sc(CS)
- BAMC
  Journalism
- M.A.
  Hindi, English, Political
- M.Sc.(CS)
- M.Sc.(IT)
- DCA
- PGDCA
- M.Com.
- PGDY
  Yoga
- Ph. D.
  Commerce
- PGDJ
  Journalism

MAHANT
Laxminaryan Das College

Gandhi Chowk, Raipur, CG. Tel.: 0771-4024234